# चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 12-18 अक्टूबर 2009



**जटिल है इस चुनाव का बीज गणित**

सियासी दुनिया पेज 3

**पटरी से उतरी ममता की गठबंधन एक्सप्रेस**

सियासी दुनिया पेज 5

**क्या भारत कमज़ोर राष्ट्र बन चुका है-2**

प्रशासन दुनिया पेज 6

**भारत को मिली नई चुनौती**

बाक़ी दुनिया पेज 11


# लोकसभा का अपमान

संतोष भारतीय

इतिहास को देखने से दो सीखें तो ज़रूर मिलती हैं, कि या तो हम आगे बढ़े हैं या फिर हम जहां थे, वहां से भी पीछे खिसक गए हैं. हम भारत के संसदीय इतिहास की दो घटनाएं बताते हैं और फ़ैसला करने का आप से आग्रह करते हैं. आप इन्हें पढ़ें और देखें कि हमारी लोकसभा की उस समय क्या गरिमा थी, और आज हमारी लोकसभा की क्या गरिमा है.

इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थीं और गुलज़ारी लाल नंदा भारत के गृहमंत्री थे. लोकसभा का सत्र चल रहा था. गुलज़ारी लाल नंदा भारत सेवक समाज और भारत साधु समाज से जुड़े हुए थे. इन दोनों संस्थाओं को भारत सरकार से अनुदान मिलता था. जिन संस्थाओं को भारत सरकार अनुदान देती है, यदि उनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत हो तो संसद की लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है. भारत सेवक समाज और भारत साधु समाज के ख़िलाफ़ ऐसी ही शिकायतों पर उस समय की लोक लेखा समिति जांच कर रही थी.

लोकलेखा समिति के अध्यक्ष श्री आर आर मोरारका थे. लोकसभा की लॉबी में गुलज़ारी लाल नंदा और आर आर मोरारका का सामना हुआ. नंदा जी ने आंखें चढ़ाते हुए मोरारका से कहा कि आप क्यों भारत सेवक समाज और भारत साधु समाज को परेशान कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ जांच करने का कोई मतलब नहीं है. मोरारका जी ने उनसे कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो केवल अध्यक्ष हूं, समिति के बाक़ी सदस्य इस मसले में जांच कर उचित फ़ैसला लेंगे. नंदा जी आख़िर दो बार प्रधानमंत्री रह चुके थे, उन्हें लगा कि आर आर मोरारका को उनकी बात माननी ही चाहिए. उन्होंने फिर ज़ोर दिया कि जांच बंद होनी चाहिए. लोक लेखा समिति के अध्यक्ष आर आर मोरारका ने कहा कि यह उनके हाथ में नहीं है. दोनों इसके बाद सदन में चले गए.

**लोकसभा की लॉबी में गुलज़ारी लाल नंदा और आर आर मोरारका का सामना हुआ. नंदा जी ने आंखें चढ़ाते हुए मोरारका से कहा कि आप क्यों भारत सेवक समाज और भारत साधु समाज को परेशान कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ जांच करने का कोई मतलब नहीं है.**

अगले दिन फिर सदन प्रारंभ हुआ. लोकसभा के स्पीकर ने प्रश्न काल प्रारंभ किया. अचानक थोड़ी देर बाद आचार्य कृपलानी ने खड़े होकर गुलज़ारी लाल नंदा के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना

(शेष पृष्ठ 2 पर)

## भागवत जी, भाजपा को बचाइए

भाजपा के बारे में हमें क्यों चिंता करनी चाहिए, यह सवाल है और इसका उत्तर भी बहुत मायने रखता है. भाजपा को देश की जनता ने लोकसभा में विपक्षी दल की ज़िम्मेदारी सौंपी है और उससे अपेक्षा की है कि वह कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन पर लगातार न केवल नज़र रखे, बल्कि हमेशा उन सवालों को उठाए जिनसे आप आदमी की तकलीफ़ों का रिश्ता है. भाजपा इन पर खरी नहीं उतर रही. अटल बिहारी वाजपेयी के ख़ामोश होने के साथ ही भाजपा जनता से अलग दिखाई देने लगी है. अटल जी के सक्रिय रहते भाजपा को लोग सवालों से जूझने वाला दल मानते थे, पर अटल जी की तस्वीरों का जैसा अपमान भाजपा ने किया, वैसा ही अपमान वह जनता की भावनाओं का भी कर रही है. भाजपा को जनता ने यूं ही अपनी नज़रों से नहीं गिरा दिया, उसके कारण हैं. सबसे बड़ा कारण स्वयं लालकृष्ण आडवाणी हैं जिन्होंने अपनी सारी राजनीति अपने इर्द-गिर्द चलाई. नब्बे के बाद उन्होंने भाजपा का कलेवर ही बदल दिया तथा उन सभी को भाजपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो भाजपा के ज़मीनी नेता थे. उन्होंने अपनी एक टीम बनाई, जिसका मुखिया अरुण जेटली को बनाया. अरुण जेटली ने कभी सीधे और कभी टेढ़े ढंग से भाजपा के भीतर सफाई अभियान चलाया. इसका परिणाम यह निकला कि आज आडवाणी के बाद भाजपा में नरेंद्र मोदी और फिर अंतिम नेता अरुण जेटली ही दिखाई दे रहे हैं. सुषमा स्वराज शॉक एब्जॉरवर की तरह हैं, जो आडवाणी और अरुण जेटली की आंख का धूप का चश्मा बन गई हैं. जसवंत सिंह के निकाले जाने के पीछे की कहानी जो सामने आई है वह भी मज़ेदार है. लोकसभा चुनावों के आख़िरी दिनों में भाजपा के साथ संघ में भी यह चिंता थी कि यदि लिब्राहन कमीशन ने आडवाणी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा. दो नाम

(शेष पृष्ठ 2 पर)

**अरुण जेटली ने कभी सीधे और कभी टेढ़े ढंग से भाजपा के भीतर सफाई अभियान चलाया. इसका परिणाम यह निकला कि आज आडवाणी के बाद भाजपा में नरेंद्र मोदी और फिर अंतिम नेता अरुण जेटली ही दिखाई दे रहे हैं.**

सभी फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

# दिल्ली का बाबू



दिलीप चेरियन

## कंगाली में भी मौज

इतने सख़्त नियमों के बावजूद कुछ बाबुओं ने अपने वेतन में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी का जुगाड़ कर ही लिया. संशोधित वेतनमान के अनुसार, सचिव स्तर के अधिकारी पहले मिलने वाले वेतन से 80 प्रतिशत ज़्यादा वेतन पाएंगे. अब अतिरिक्त सचिव का वेतनमान 37,400 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 67,000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा. इसका मतलब हुआ कि अब वरिख़ अतिरिक्त सचिवों को केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) के निदेशकों से ज़्यादा वेतन मिलेगा.

अजीब बात यह है कि मुश्किल से कुछ ही दिन पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के भुगतान नियमों के अंतर्गत केंद्र सरकार ने आईआईटी और आईआईएम के शिक्षकों को खर्चों में कटौती करने के लिए कहा था, जिसमें यात्राओं और छात्रों को दी जाने वाली सब्सिडी में कमी शामिल है. अब से बड़े बाबुओं को वेतन में तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मिलेगी. बेशक बड़ा सवाल यह है कि इतना सारा पैसा आएगा कहां से? इस बारे में बेहतर तो कोई ज्ञानी बाबू ही बता सकते हैं.




## सुपर रेगुलेटर पर तनातनी

वित्तीय बाज़ार के अस्थिर रुख़ को देखते हुए सरकार अब पूंजी बाज़ार पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति (एचएल–सीसी) को पूर्ण विकसित नियामक में तब्दील करने की योजना बना रही है. 1990 के पूर्वार्द्ध से ही यह सेबी समेत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं की समस्त गतिविधियों के संयोजन और निरीक्षण का काम करती रही है. यूके के प्रारूप फाइनेंसियल सर्विस अथॉरिटी (एफएसए) की तर्ज पर सुपर रेगुलेटर को बदलने के पिछले तमाम प्रयासों पर सरकार की ओर से विरोध देखने को मिला था. 2008 में प्रधानमंत्री के तत्कालीन आर्थिक सलाहकार रघुराम राजन ने इस कदम को अनुचित बताया था. साल के शुरू में वित्त मंत्रालय के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य, आरबीआई के उप गवर्नर राकेश मोहन और पूर्व सेबी प्रमुख एम दामोदरन का भी यही सोचना था कि समिति काफी अच्छा काम कर रही है. अजीब बात यह है कि आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव, जो पहले एचएलसीसी के रुपांतरण के पक्ष में थे, अब इसके विरोध में हैं. एचएलसीसी के वर्तमान रूप में अन्य लोगों के अलावा सुब्बाराव, सेबी प्रमुख चंद्रशेखर भास्कर भावे और आर्थिक मामलों के सचिव अशोक चावला शामिल हैं.




# लोकसभा का अपमान

पृष्ठ 1 का शेष

करने का आरोप लगा दिया. दादा कृपलानी अमरोहा से संसद का उप चुनाव जीत कर लोकसभा के सदस्य बन चुके थे. इंदिरा जी सदन में मौजूद थीं.

दादा कृपलानी ने स्पीकर से कहा कि गृहमंत्री ने सदन की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को धमकी दी है और उन पर दबाव डालने का प्रयास किया है. गुलज़ारी लाल नंदा ने खड़े होकर सफाई दी कि उन्होंने आर आर मोरारका से कांग्रेस पार्टी के सदस्य के नाते बात की थी और दूसरा यह कि श्री चांदी वाला भारत सेवक समाज और भारत साधु समाज का काम अच्छी तरह कर रहे हैं. आचार्य कृपलानी तत्काल खड़े हुए और कहा कि मैं चांदीवाला या सोनावाला की बात नहीं सुनना चाहता. श्री नंदा ने सदन की कमेटी के अध्यक्ष पर एक मामले को लेकर दबाव डाला है, अतः इनके ख़िलाफ़ मामला बनता है. श्रीमती गांधी ख़ामोश होकर सारी बातें सुनती रहीं. नंदा जी को सभ्य शब्दों में सदन से माफी मांगनी पड़ी और तब जाकर यह मामला शांत हुआ.

पंद्रहवीं लोकसभा मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और लाल कृष्ण आडवाणी की लोकसभा है. इस लोकसभा के एक सदस्य जसवंत सिंह हैं जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं. इन्हें लोकसभा के अध्यक्ष ने लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नामांकित किया है. इन्हें अगर हटाना हो तो यह केवल लोकसभा के अध्यक्ष ही कर सकते हैं. जसवंत सिंह के घर 31 अगस्त को अचानक सुषमा स्वराज पहुंचीं. वे वहां तीस मिनट से ज़्यादा रहीं. वे जसवंत सिंह को भाजपा में वापस ले जाने के लिए कहने नहीं गई थीं. वे जसवंत सिंह से कहने गई थीं कि जसवंत सिंह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दें.

सुषमा स्वराज ख़ुद इस लोकसभा की सदस्य हैं. उनका जसवंत सिंह को इस्तीफ़ा देने के लिए कहना लोकसभा के विशेषाधिकार और सदन की अवमानना का विषय बन जाता है. देश के सभी अख़बारों ने इस ख़बर को प्रमुखता से छापा. लेकिन यह लोकसभा निर्जीव लोकसभा है. किसी सदस्य ने लोकसभा अध्यक्ष को सुषमा स्वराज के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस नहीं भेजा है. इसमें आचार्य कृपलानी जैसा शायद एक भी सदस्य नहीं है जिसे लोकसभा के सम्मान की चिंता हो.

इतिहास की ये दो घटनाएं बताती हैं कि लोकसभा के चरित्र में कितना फ़र्क़ आ गया है और सदस्य कितने ज़्यादा असंवेदनशील हो गए है. वैसे कारण की तलाश भी मज़ेदार है. भाजपा के ही एक नेता अनंत कुमार की पत्नी एक संस्था चलाती हैं जिसे राज्य सरकार अनुदान देती है. अनंत कुमार की सिफ़ारिश पर भाजपा की कई सरकारों ने कुछ संस्थाओं को अनुदान दिया है और ये संस्थाएं बच्चों को दोपहर का भोजन देती हैं. अनंत कुमार को डर है कि जसवंत सिंह कहीं लोक लेखा समिति की जांच के दायरे में दोपहर का भोजन देने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं को न ले आएं.

हमारी ये मांग है कि दोपहर के भोजन की योजना में लगी सभी संस्थाओं की व्यापक जांच होनी चाहिए. ग़रीब बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में भयानक भ्रष्टाचार तो है ही, कभी–कभी सड़े खाने की वजह से बच्चे बीमार भी होते हैं और हमेशा के लिए भयानक बीमारियों के जाल में फंस जाते हैं. भारत में ग़रीब बच्चों को भोजन देने के नाम पर जहां कई संस्थाएं भारत की सरकार से, राज्य सरकारों से अनुदान लेती हैं वहीं दूसरी ओर वे विदेशों में एक व्यापक पैसा जुटाओ अभियान चलाती हैं. यह पैसा कभी ग़रीब बच्चों की भूख मिटाने में इस्तेमाल नहीं होता. कहां होता है, यह जांच का विषय है. और यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जसवंत सिंह कुछ ताक़तों की आंख की किरकिरी बने हुए हैं.

editor@chauthiduniya.com

# भागवत जी, भाजपा को बचाइए





पृष्ठ 1 का शेष

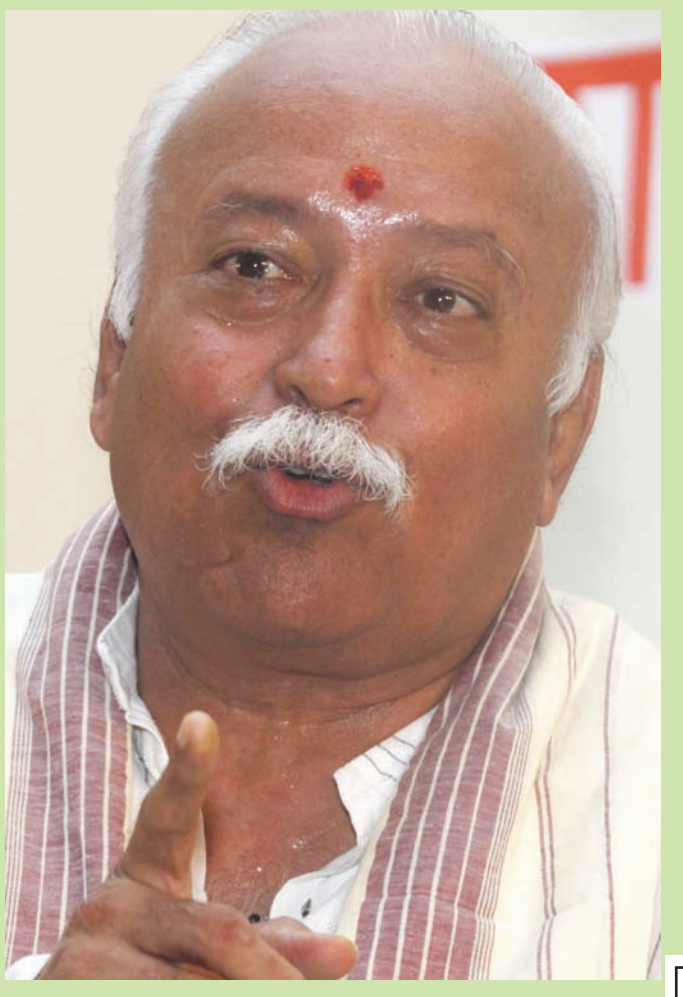

उभरे, पहला मुरली मनोहर जोशी और दूसरा जसवंत सिंह. संघ को लगा कि यदि जोशी का नाम सहयोगी दलों ने न माना तो जसवंत सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा. आडवाणी और उनकी टीम को यह अखर गया. मुरली मनोहर जोशी के ख़िलाफ़ कुछ करना मुश्किल था. अतः पहले जसवंत सिंह को निबटाने का फ़ैसला लिया गया.

जसवंत सिंह ने राजनाथ सिंह को एक ख़त लिखा और हार के कारणों पर विचार करने की मांग की. भाजपा डर गई कि यदि ऐसा हुआ तो पांच लोगों को पद से हटना पड़ेगा. वैसे भाजपा में आडवाणी और राजनाथ सिंह के दो गुट माने जाते हैं. राजनाथ सिंह को दर्द था कि अध्यक्ष रहने के बाद भी किसी ने उनका नाम प्रधानमंत्री पद के योग्य क्यों नहीं समझा, क्यों जसवंत सिंह का नाम सामने आया. यहां जसवंत सिंह, आडवाणी और राजनाथ के निशाने पर आ गए.

**जैसे जसवंत सिंह की किताब बाज़ार में आई, रणनीति बन गई. शिमला में चिंतन बैठक होने वाली थी. जसवंत सिंह समेत सभी लोग पहुंच गए थे. सुबह नाश्ते पर नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को संबोधित कर कहा कि वे आज ही गुजरात वापस चले जाएंगे, क्योंकि जसवंत सिंह की किताब में सरदार पटेल के ज़िक्र की वजह से दंगे हो सकते हैं. नरेंद्र मोदी के पास कोई जानकारी नहीं थी, न ही उनकी ख़ुफ़िया पुलिस ने उन्हें कोई संदेश भेजा था. दरअसल उन्होंने तो अपने चाणक्य साथी की रणनीति का पहला बम फोड़ा था.**

जैसे जसवंत सिंह की किताब बाज़ार में आई, रणनीति बन गई. शिमला में चिंतन बैठक होने वाली थी. जसवंत सिंह समेत सभी लोग पहुंच गए थे. सुबह नाश्ते पर नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को संबोधित कर कहा कि वे आज ही गुजरात वापस चले जाएंगे, क्योंकि जसवंत सिंह की किताब में सरदार पटेल के ज़िक्र की वजह से दंगे हो सकते हैं. नरेंद्र मोदी के पास कोई जानकारी नहीं थी, न ही उनकी ख़ुफ़िया पुलिस ने उन्हें कोई संदेश भेजा था. दरअसल उन्होंने तो अपने चाणक्य साथी की रणनीति का पहला बम फोड़ा था. अब बारी राजनाथ सिंह की थी.

उन्होंने कहा कि बैठक से पहले पार्लियामेंटरी बोर्ड की मीटिंग करते हैं. सभी तैयार बैठे थे. राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किताब पर कोई फ़ैसला हो, अन्यथा वे चिंतन बैठक में शामिल नहीं होंगे. वापस चल जाएंगे, क्योंकि गुजरात में पटेल समुदाय दंगा कर सकता है. किताब पर क्या फ़ैसला होता, जसवंत सिंह पर फ़ैसला हो गया. उन्हें दल से निकालने की बात तय हो गई. बैठक में शामिल आडवाणी जी बिल्कुल ख़ामोश रहे. फ़ैसले के दो माह बाद बोले कि वे फ़ैसले से सहमत नहीं थे. कैसे नेता हैं आडवाणी जी, बैठक में बोलते नहीं, निकालने का फ़ैसला हो जाने देते हैं. देश में हुई प्रतिक्रिया को देखते हुए बाद में कहते हैं कि वे सहमत नहीं थे. देश ने भाजपा को बहुमत नहीं दिया और न आडवाणी जी प्रधानमंत्री बन पाए.

भाजपा के अंतर्विरोधों और अंतःकलह से घबराकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तीन बार संघ के एक समय दिमाग़ कहे जाने वाले गोविंदाचार्य को मिलने के लिए बुलाया. लंबी–लंबी बातचीत हुई, विश्लेषण हुए, भाजपा को कैसे ठीक किया जाए इस पर बात हुई. संघ के अंदरूनी लोगों ने बताया कि मोहन भागवत ने गोविंदाचार्य से भाजपा का ज़िम्मा लेने का अनौपचारिक प्रस्ताव रखा. इसका मतलब कि वे जानना चाहते थे कि यदि गोविंदाचार्य को भाजपा का अध्यक्ष बनाया जाए तो क्या वे इसे स्वीकार करेंगे? संघ सूत्र बताते हैं कि गो–विंदाचार्य ने मोहन भागवत से क्षमा मांग ली है, लेकिन मोहन भागवत चाहते हैं कि या तो गोविंदाचार्य या उन जैसा कोई दूसरा भाजपा का अध्यक्ष बने ताकि भाजपा गगन बिहारी नेताओं के चंगुल से निकल सके.

आज भाजपा पर लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, अनंत कुमार और सुषमा स्वराज का राज चल रहा है. वेंकैय्या नायडू और राजनाथ सिंह प्यादे हैं. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को भाजपा के आसमान से मिटाने में यही टीम ज़िम्मेदार है. इतना ही नहीं, भाजपा कार्यकर्ता खुले आम कह रहे हैं कि इस टीम के रहते हुए भाजपा का दिल्ली की सत्ता में आना नामुमकिन है. कार्यकर्ताओं से यह पूछने पर कि फिर दूसरी टीम कौन हो, वे चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने किसी और को पार्टी में रहने कहां दिया है. भाजपा में आग सुलग रही है और कुछ लोगों को जलाने के लिए बढ़ रही है. देखना है कि कौन जलता है और कौन बचता है. पर इस सारी उठा पटक में सबसे ज़्यादा ठगे गए वे लोग हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया और भरोसा किया कि वह विपक्षी दल की भूमिका निभाएगी. क्या भाजपा विपक्षी दल की भूमिका निभाने लायक़ भी नहीं बची है? इंतज़ार करते हैं कि भाजपा इसका कब जवाब देती है.

संतोष भारतीय
editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 1 अंक 31, 12 अक्टूबर–18 अक्टूबर 2009

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110001

फोन न.
संपादकीय 011–47149999
विज्ञापन + 0120–4783999
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4 बिहार व झारखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

नेहरु नगर महाराष्ट्र के श्रम मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक की परंपरागत सीट रही है. इसका दूसरे विधान सभा क्षेत्र कलिना में विलय हो गया है जो कांग्रेसी नेता कृपा शंकर सिंह का गढ़ माना जाता है.



## महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव

फोटो–प्रभात पाण्डेय

# जटिल है इस चुनाव का बीजगणित

**अजब नजारा है सूबे में. चुनावी शंखनाद हो चुका है. एक ओर कल तक गलबहियां डालकर दो जिस्म-एक जान होने का दम भरने वाले लोग आज एक दूसरे के सामने खा जाने वाली नजरों से ताल ठोक रहे हैं. वहीं दूसरी ओर एक दूसरे की शक्ल तक नापसंद करने वाले आज एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं. जनता असमंजस में है कि बहुरुपियों की इस भीड़ में कौन सा चेहरा उसका अपना है.**

ममता सेन

राज्य विधानसभा की 288 सीटों में से कम से कम 90 सीटें परिसीमन के बाद दूसरी सीटों में समाहित हो नक़्शे से हमेशा के लिए ग़ायब हो चुकी हैं. अब वे नए स्वरूप में सामने हैं, दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों के हिस्से के तौर पर. आगामी चुनाव के बाद किस गठबंधन को बढ़त हासिल होगी या फिर किसकी सरकार बनेगी, इसके निर्धारण में परिसीमन के पेट में समाई सीटों में से 11 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं. इसलिए सभी चार बड़े राजनीतिक दल– कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने अपने प्रतिद्वंद्वियों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है, ताकि उनके उम्मीदवार इन जिताऊ सीटों पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सकें. इनमें से कुछ विधानसभा सीटों पर पार्टी में अंदरूनी कलह, मतभेद और आपसी खींचतान भी देखने को मिल रही है. यह बात पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के लिए ख़तरे की घंटी जैसी है.

कांग्रेस और राकांपा भले ही सीटों के बंटवारे को लेकर सहमत हो गए हों, लेकिन कुछ सीटों पर वे आपस में ज़ोर–आज़माइश भी कर रहे हैं. मतभेद सिर्फ़ परिसीमन के बाद समाप्त कर दी गई सीटों को लेकर ही नहीं है. परिसीमन की जद में आने से बची सीटों पर भी दोनों दलों के बीच ठनी हुई है. टिकट से वंचित नेता अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध बग़ावत कर चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा राज्य की कई सीटों पर हो रहा है.

बांद्रा पश्चिम से राकांपा ने जब तक अपनी दावेदारी नहीं जताई थी, कांग्रेस ने वहां से अपने उम्मीदवार बाबा सिद्दीकी के लिए ख़ूब ज़ोर लगाया. इसी तरह अणुशक्ति नगर व मानखुर्द, दोनों ही निर्वाचन क्षेत्र दलित और मुस्लिम बहुल हैं. यहां पर दोनों ही दलों को अपनी जीत सुनिश्चित दिख रही थी. उनके बीच मान मनौव्वल का लंबा दौर भी चला. श्रम मंत्री नवाब मलिक, जो मलिना से कृपाशंकर सिंह के चुनाव मैदान में उतरने के कारण टिकट से वंचित कर दिए गए थे, को कांग्रेस ने अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार बनाया और मानखुर्द सीट भी कांग्रेस के ही क़ब्ज़े में रही. निवर्तमान विधायक सैयद अहमद यहां से उम्मीदवार बनाए गए.

नवसृजित निर्वाचन क्षेत्र दिंदोशी को लेकर भी राकांपा और कांग्रेस के बीच टकराव था, यह सीट कांग्रेस के हिस्से में आई. बीएमसी में विपक्ष के नेता राजहंस सिंह को कांग्रेस ने यहां से पहली बार चुनाव मैदान में उतारा तो विगत आठ वर्षों से यहां सक्रिय राकांपा के कॉरपोरेट अजीत राव राणे नाराज़ हो गए और उन्होंने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर डाली.

महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक बहुल सुरक्षित सीटें ऐसी हैं जिसका पलड़ा किसी भी ओर झुक सकता है. माना जा रहा है कि मनसे और तीसरा मोर्चा यहां मुख्य भूमिका निभाने की स्थिति में होंगे. ख़ासतौर पर पुणे और नासिक में. यहां कांग्रेस को मनसे के हाथों वोट गंवाने की चिंता सता रही है, जबकि विदर्भ में राकांपा और कांग्रेस दोनों को मायावती फैक्टर से परेशानी का डर है.

गुहागार विधानसभा सीट को लेकर भी शिवसेना और भाजपा के बीच ज़बर्दस्त तनाव रहा. यहां से शिवसेना ने रामदास क़दम को उतारा है. परिसीमन के बाद कोंकण में अपनी खेड सीट की समाप्ति के बाद उन्हें अपने लिए एक सीट की तलाश थी. खेड निर्वाचन क्षेत्र का ख़ात्मा उनके लिए किसी हादसे से कम नहीं था, क्योंकि वह 1990 से ही इस सीट की नुमाइंदगी कर रहे थे. सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिवसेना ने सिर्फ़ उन्हें ही कोंकण में बागी शिवसैनिक नारायण राणे को उनके अपने ही अखाड़े पर पटकनी देने के लायक़ समझा. उद्धव ठाकरे इस सीट के लिए भाजपा को मना पाने में सफल तो रहे, लेकिन इस निर्णय ने भाजपा–आरएसएस खेमे की बेचैनी बढ़ा दी. दरअसल भाजपा तीन बार विधायक रह चुके विनय नाटू को यहां से उम्मीदवार बनाना चाहती थी. श्रीधर सेना के नाम से अलग पार्टी गठित कर नाटू अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं.

पार्टी नेताओं की बग़ावत को राकांपा काफी गंभीरता से ले रही है. गत लोकसभा चुनाव में बग़ावत के चलते राकांपा को पश्चिम महाराष्ट्र की दो महत्वपूर्ण सीटें कोल्हापुर और हतमंगले गंवानी पड़ी थीं.

मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता निज़ामुद्दीन रेयन के मुताबिक़, मुंबई, ठाणे और कोंकण पट्टी के 60 में 35 निर्वाचन क्षेत्रों में उत्तर भारतीय निर्णायक भूमिका में हैं. वह कहते हैं कि कांग्रेस को सत्ता फिर से हासिल करने के लिए यहां 12 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने के बारे में सोचना चाहिए था. बहरहाल कांग्रेस ने यहां से पांच मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं.

मुस्लिम वोटों की अहमियत जानकर ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की प्रथम सूची जारी करने के लिए ईद का दिन चुना. 147 सीटों पर चुनाव लड़ रही मनसे कम से कम 20 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है. जबकि उद्धव ठाकरे ने मनसे और कांग्रेस के बीच गुप्त समझौता होने की आशंका ज़ाहिर की है.

कमोबेश सभी दल बग़ावत से जूझ रहे हैं. राकांपा और कांग्रेस के नेता तो आख़िर तक सीटों के बंटवारे को लेकर कोई अंतिम समझौता न हो पाने के कारण मुंबई और दिल्ली के बीच दौड़ लगाते रहे. नवरात्र के प्रारंभ में उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली भाजपा और शिवसेना भी बग़ावत का सामना कर रही है. तीसरा मोर्चा जो कि 18 राष्ट्रीय, प्रांतीय और क्षेत्रीय पार्टियों का महा गठजोड़ है, काफी समय तक अंतर्कलह की आशंका के चलते अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी करने से कतराता रहा. और, जब सूची जारी की गई तो विवाद सड़क पर आ गया. राजेंद्र गवई के नेतृत्व में आरपीआई का एक खेमा रामविलास पासवान के तीसरा मोर्चा में शामिल होने के विरोध में मोर्चे से बाहर हो गया तो कांग्रेस ने गवई की पार्टी के लिए तीन सीटें छोड़ दीं.

तीसरे मोर्चे में मुख्यत: दलित और मुस्लिम पार्टियां शामिल हैं और यह बड़ी तेज़ी से अपना प्रभाव फैला रहा है. आरपीआई नेता रामदास अठावले की अगुवाई में तीसरा मोर्चा सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. अठावले दावा करते हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री तय करने में तीसरा मोर्चा निर्णायक भूमिका अदा करेगा. अठावले के इस दावे में कितना दम है यह तो पता नहीं, लेकिन तीसरे मोर्चे के चुनाव मैदान में उतरने से राष्ट्रीय दलों में बेचैनी ज़रूर देखी जा रही है. यह इस बात से भी पता चलता है कि राकांपा और कांग्रेस एक दूसरे के प्रति सशंकित होते हुए भी साथ चुनाव लड़ रहे हैं.

माना जा रहा है कि इसके पीछे भी कहीं न कहीं तीसरे मोर्चे का डर ही मुख्य वजह है. एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की मानें तो कांग्रेस नाज़ुक मुक़ाम पर कोई जोख़िम नहीं उठाना चाहती थी. कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने राकांपा के साथ गठबंधन ग्रामीण महाराष्ट्र में तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार की हार सुनिश्चित करने के लिए ही किया है. ज़ाहिर है, जीत चाहे जिस किसी की भी हो, तीसरे मोर्चे की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होना तय है. मोर्चा मैदान मारने की स्थिति में भले न हो, दूसरों की लुटिया तो वह डुबो ही सकता है.

रामदास अठावले के मुताबिक़, कांग्रेस के दस से बारह फ़ीसदी वोटों का झुकाव तीसरा मोर्चा के पक्ष में होने और तैंतीस फ़ीसदी तटस्थ मतदाताओं का समर्थन हासिल हो पाने की उम्मीद लगाई जा रही है. उधर मनसे के बारे में भी यही बात कही जा रही है कि उसे कांग्रेस का परोक्ष समर्थन हासिल है और वह भी दूसरों का खेल बिगाड़ने का ही काम करेगी.

feedback@chauthiduniya.com

## परिसीमन की जद में

चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन से तक़रीबन 89 विधान सभा क्षेत्र सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. इनमें से 30 सीटें कांग्रेस, 20 सीटें राकांपा, 19 सीटें शिवसेना, 16 सीटें भाजपा और चार सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के क़ब्ज़े में थीं. राकांपा का गढ़ मानी जाने वाली पश्चिमी महाराष्ट्र की चीनी पट्टी (पुणे, सतारा, सांगली, अहमद नगर, शोलापुर और कोल्हापुर की करीब 70 विधानसभा सीटें) परिसीमन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है.

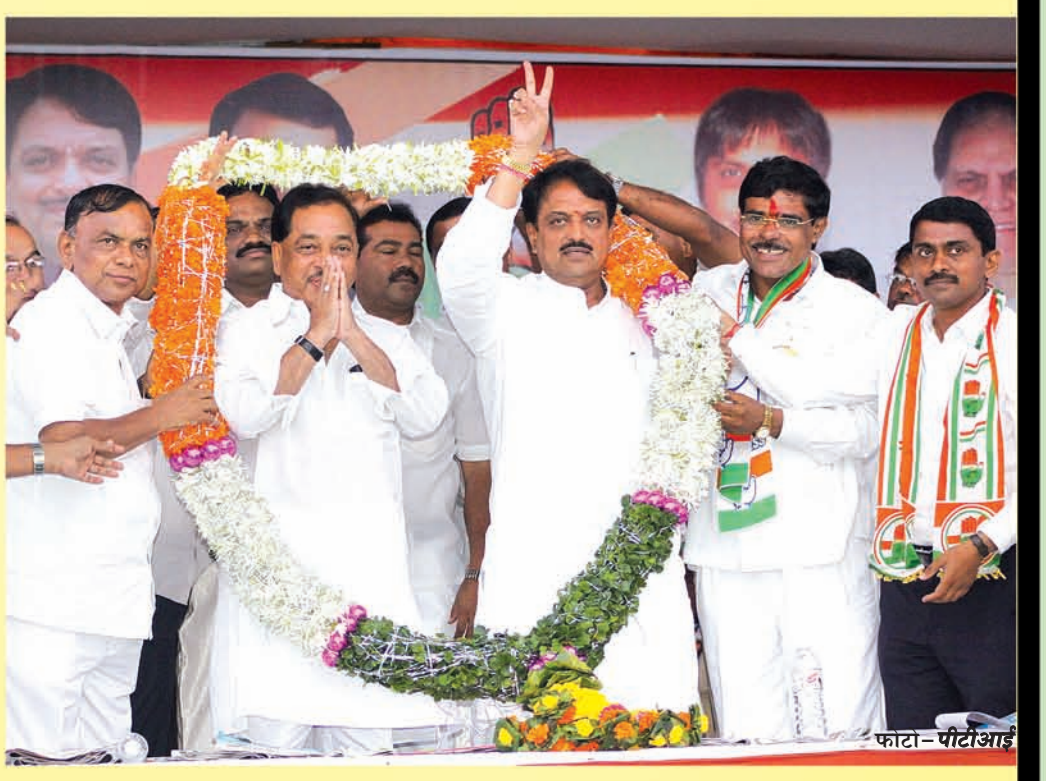

फोटो– पीटीआई

## चुनाव में इन इलाक़ों की होगी निर्णायक भूमिका

**पश्चिमी महाराष्ट्र :** गन्ना उत्पादकों का गढ़ है पश्चिमी महाराष्ट्र . पुणे, सतारा, सांगली और कोल्हापुर आदि ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पकड़ यहां मज़बूत है, लेकिन राकांपा के दो उम्मीदवारों को स्वतंत्र उम्मीदवारों के हाथों मिली पराजय के बाद शिवसेना को यहां अपनी जीत की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही हैं.

**उत्तरी महाराष्ट्र :** इस क्षेत्र में महाराष्ट्र के नासिक, जलगांव, धुले, अहमदनगर, नंददरबार आदि ज़िले आते हैं. नासिक राज ठाकरे का मज़बूत गढ़ माना जाता है.

**मराठवाड़ा :** यह शिवसेना-भाजपा का अभेद्य दुर्ग है. यह भाजपा के गोपीनाथ मुंडे, कांग्रेस के विलासराव देशमुख और अशोक चव्हाण का गृहक्षेत्र भी है.

**कोंकण :** शिवसेना से विद्रोह कर कांग्रेस में शामिल हुए धुरंधर नेता नारायण राणे की यहां तूती बोलती है.

**विदर्भ :** राज्य की 67 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं. नक्सली गतिविधियों से आक्रांत यह इलाक़ा सबसे अधिक किसानों की आत्महत्या का गवाह रहा है.

## राकांपा और कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गई सीटें

**नेहरुनगर :** राकांपा नेता नवाब मलिक की इस परंपरागत सीट का कलिना विधान सभा क्षेत्र में विलय हो गया है. कलिना कांग्रेसी नेता कृपा शंकर सिंह का गढ़ माना जाता है.

**कुर्ला :** कांग्रेसी नेता नसीम ख़ान का चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है. सीटों के तालमेल में कांग्रेस कलिना सीट झपट चुकी है और बदले में राकांपा रविंद्र पवार के लिए कुर्ला पश्चिम सीट सुनिश्चित कर चुकी है. दलित और मुस्लिम बहुल होने के कारण दोनों ही दलों के लिए यह संभावनाओं से भरी सीट है.

**रोहा :** श्रीवर्द्धन सीट के साथ विलय के बाद राकांपा नेता सुनील तत्कारे रोहा से रायगढ़ भेज दिए गए. रोहा सीट को लेकर कांग्रेस और राकांपा के बीच विवाद की तह में हक़ीक़त यह है कि रोहा कांग्रेसी नेता ए आर अंतुले का मज़बूत गढ़ माना जाता है. वैसे तत्कारे कांग्रेस से यह सीट हथियाने में कामयाब रहे.

**मलशिरास :** पूर्व उप मुख्यमंत्री और राकांपा नेता विजय सिंह मोहिते पाटिल का यह निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन की भेंट चढ़ गया. अब वह प्रहलादपुर से क़िस्मत आजमाएंगे. लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब स्वयं शरद पवार निवर्तमान विधायक बबन शिंदे को मना पाने में कामयाब होंगे. बगावत पर उतारू शिंदे स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे है, जबकि उन्हें दूसरी सीट माधा से चुनाव लड़ने को कहा गया था.

**तासगांव :** पूर्व उप मुख्यमंत्री और राकांपा नेता आर आर पाटिल की परंपरागत सीट परिसीमन के बाद चुनावी नक़्शे से ग़ायब हो चुकी है. इसके बाद राकांपा ने पड़ोस की कवाथे महंकल से चुनाव लड़ने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन कांग्रेस उन्हें यह सीट सौंपने को राजी ही नहीं है.

**गर्धिंगलाज :** विधानसभा अध्यक्ष और राकांपा नेता कुपेकर की इस सीट का अब कहीं अस्तित्व नहीं है. इसका पड़ोस की चंदगड़ निर्वाचन क्षेत्र में विलय हो चुका है. कांग्रेस ने इस सीट के लिए बहुत जोर लगाया. इतनी कि राकांपा कुपेकर को कोल्हापुर से लड़ाने का मन बना चुकी थी. आख़िरकार कुपेकर को यहीं से टिकट मिल गया.

**मजगांव :** शिवसेना के क़ब्ज़े वाली यह सीट बायकुल के साथ मिल चुकी है. राकांपा और कांग्रेस दोनों इस सीट के लिए दावेदारी जता रहे थे. अंततः कांग्रेस के मधु चव्हाण ने सीटों के तालमेल में यहां से बाजी मार ली.

**उमरखाड़ी (मुंबई) :** मुस्लिम मतदाता बहुल उमरखाड़ी का खेतवाड़ी और नागपाड़ा विधानसभा सीट में विलय कर दिया गया. राकांपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता इस सीट को अपनी मान कर चल रहे थे. राकांपा ने अपने प्रत्याशी वशीर पटेल के लिए कांग्रेस पर काफी दवाब बनाया भी, लेकिन सीट आख़िरकार कांग्रेस के खाते में आई. अमीन पटेल यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जबकि वशीर पटेल राकांपा का दामन छोड़ सपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं.

## भाजपा और शिवसेना के लिए मुसीबत बन गई सीटें

**दादर :** शिवसेना का अभेद्य दुर्ग मानी जाने वाली यह सीट अब माहिम का हिस्सा बन चुकी है. दादर से शिवसेना के विधायक सदा सर्वंकर माहिम से टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया. सर्वंकर शिवसेना से अलग हो कांग्रेस में शामिल हो गए. अब वह दादर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं.

**खेड :** शिवसेना के नेता रामदास क़दम खेड का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन जब उनकी यह सीट गुहागार और क़दम विधानसभा क्षेत्रों में बंट गईं तो उन्हें गुहागार से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है. लेकिन इससे भविष्य में सेना और भाजपा में दोफाड़ होने की आशंका प्रबल हो गई है.

**ओपेरा हाउस :** परिसीमन के बाद तीन हिस्सों में बंट चुकी इस सीट का सबसे बड़ा हिस्सा अब मालाबार हिल्स निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है. यहां भाजपा के शाइनी और निवर्तमान विधायक मंगल प्रभात लोधा के बीच सीट पर दावेदारी को लेकर ठन गई, लेकिन लोधा कामयाब रहे.

चाटुकारिता की यह हद नहीं तो और क्या है? आरएसएस के शस्त्र पूजा के दौरान ख़ाकी वर्दी की गरिमा भूल एसपी ने ख़ुद तो जमकर गोलियां दागी ही, बेटे से भी ऐसा करवाया.



# विकास नहीं, विनाश कर रहे नीतीश : लालू

फोटो- प्रभात पाण्डेय

सरोज सिंह

*बहुत पुरानी, लेकिन मानी हुई बात है कि इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है. लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बिल्कुल बदल कर रख दिया है. आत्ममंथन के दौर में उन्हें अपनी ग़लतियों का अहसास हुआ, इसलिए अब वह बहुत फूंक फूंककर अपनी राजनीतिक चालें चल रहे हैं. रेलमंत्री के कार्यकाल के दौरान जहां आम जनता और कार्यकर्ताओं से कट जाने का ग़म उन्हें सालता है तो वहीं नीतीश के शासन में सूबे की स्थिति को लेकर भी वह चिंतित हैं. अगड़ी जातियों को गले लगाने की बात कहकर लालू प्रसाद यह भ्रम दूर करना चाहते हैं कि उनके दिल में किसी जाति व धर्म विशेष के प्रति कोई ग़लत भावना है. वह दावा करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार की विदाई तय है. इसकी वजह भी लगे हाथ गिनाते हुए वह कहते हैं कि राज्य में विकास के नाम पर लूट मची है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, पुलिस व प्रशासन से लोगों का भरोसा उठ रहा है. उपचुनाव में जनता ने नीतीश को ख़ारिज़ कर दिया और वह विधानसभा चुनाव में इस सरकार के सफ़ाए का मन बना चुकी है. कांग्रेस से अपने रिश्ते, महंगाई और चुनावी संभावनाओं पर वह पहली बार खुलकर बोले. पेश हैं, बातचीत के प्रमुख अंश:*

***क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार बिहार को विकास की पटरी पर लाने में सफल रहे हैं?***

बिल्कुल बकवास बात है. झूठा प्रचार किया जा रहा है. उपचुनाव में हम घूमकर आए हैं. पूरे सूबे में विकास के नाम पर लूट मची है. मंत्री, विधायक और अफ़सरों के घरों में जा रहा है विकास का सारा पैसा. जो सड़कें बनी हैं, उनका हाल आप ख़ुद जाकर देख लीजिए, वे साल भर में ही उजड़ गई हैं. कमीशन का खेल जारी है. जो इस खेल में शामिल हैं उनकी तिजोरियां भर रही हैं. जनता को केवल विकास का सपना ही दिखाया जा रहा है. दिल्ली में, जब हम सरकार में थे तो हमने बिहार को पैसा दिलाया और केंद्रीय एजेंसियों को काम करने के लिए भेजा. देख लीजिए, अब क्या हो रहा है? विकास का पैसा लूटा जा रहा है. केंद्रीय एजेंसियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है. बिहार का विकास नहीं, बल्कि नीतीश उसका विनाश कर रहे हैं.

***लेकिन जब आपके हाथों में राज्य की सत्ता थी तो उस समय बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ पाया?***

हमें क्या केंद्र ने दिल खोलकर पैसा दिया था? चिल्लाते चिल्लाते थक गए थे हम, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी तिजोरी नहीं खोली थी. बिहार बंट गया और संसाधनों में हम पिछड़ गए. इसके बावजूद कोशिश की तो सांप्रदायिक ताक़तों ने झूठे मुक़दमों में फंसा दिया. हमें तो काम करने का मौक़ा ही नहीं मिला. आज हम विपक्ष में हैं और सही बात पर सरकार की टांग नहीं खींचते, लेकिन लालू यादव ग़लत नहीं होने देंगे. ग़रीबों पर अत्याचार होंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे.

***नीतीश और उनकी सरकार के कामकाज पर आपकी क्या राय है?***

मेरे साथ ही न थे नीतीश. वह किसी के नहीं हैं. उनके अपने मंत्री और विधायक उनसे नाराज़ हैं. वह किसी की क़द्र नहीं करते. आप किसी मंत्री से ऑफ़ द रिकार्ड जाकर पूछिए, पता चल जाएगा कि नीतीश के लिए उसके दिल में कितनी जगह है. नीतीश में संयम नहीं है. नेता को सबकी बात सुननी चाहिए. हम तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते, वरना यह सरकार तो कभी भी जा सकती है. जहां तक काम की बात है तो बताइए कि इस सरकार ने अपना कौन सा वादा पूरा किया. पटना छोड़कर कहां बिजली है? किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने वाले थे, क्या हो गया? महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है, कालाबाज़ारियों की चांदी हो गई है और सरकार का इस पर कोई नियत्रंण नहीं है. शिक्षा व्यवस्था चौपट है. नए बहाल किए गए शिक्षकों को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा जा रहा है. नक्सली आतंक का आलम यह है कि राज्य के कई इलाक़े ऐसे हैं, जहां शाम होते ही बाज़ार बंद हो जाते हैं. पुलिसिया ज़ुल्म भी बढ़ा है, घरों में घुसकर बच्चों व महिलाओं को पीटा जा रहा है.

***अगड़ी जातियों के मन में लालू यादव को लेकर जो भ्रम था, उसे पिछले दिनों आपने दूर करने की कोशिश की. आपको लगता है कि जदयू-भाजपा गठबंधन छोड़कर यह तबका आपका साथ देगा?***

मैंने बार-बार कहा है कि किसी भी जाति व धर्म के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है. विपक्ष और मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं, जो इस तरह का ग़लत प्रचार करने में लगे रहते हैं कि लालू अगड़ी जातियों को खा जाएगा. मैंने कभी भूरा बाल साफ़ करो जैसी बात नहीं कही थी, लेकिन ऐसा प्रचार करके मुझे बदनाम किया गया. लालू आ जाएगा-लालू आ जाएगा का हौआ खड़ाकर जदयू व भाजपा के नेता मुझे अगड़ी जातियों से दूर रखना चाहते हैं. लेकिन, अब वे लोग भी जान गए हैं कि नीतीश ने केवल उन्हें ठगने का काम किया. मैं तो सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं. सब लोग एक दूसरे से दोस्ती रखें, अपना काम करें, तभी सूबा आगे बढ़ेगा. एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि

> **मैंने बार-बार कहा है कि किसी भी जाति व धर्म के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है. विपक्ष और मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं, जो इस तरह का ग़लत प्रचार करने में लगे रहते हैं कि लालू अगड़ी जातियों को खा जाएगा. मैंने कभी भूरा बाल साफ़ करो जैसी बात नहीं कही थी, लेकिन ऐसा प्रचार करके मुझे बदनाम किया गया.**

इस दोस्ती को तोड़ने की कोशिश करने वाला अगर मेरा कोई सगा-संबंधी भी रहेगा तो वह भी बख्शा नहीं जाएगा.

***दलितों को बांटकर महादलित बनाया गया. आपकी राय में इसके पीछे नीतीश की क्या मंशा समझ में आती है?***

बेवकूफ़ी भरा क़दम है. दलितों को बांट दिया और महादलितों के लिए वादों का अंबार लगा दिया, लेकिन उन्हें मिला क्या? देखिए, नीतीश फेडअप हो चुके हैं. अनाप शनाप फ़ैसले ले रहे हैं. अपना नुक़सान तो वह कर ही रहे हैं, राज्य को भी रसातल में ले जा रहे हैं.

***बटाईदार क़ानून पर हाय-तौबा मची हुई है, किसानों में भ्रम की स्थिति है, बटाई करने वाले भी असमंजस में हैं.***

नीतीश, ज्योति बाबू बनना चाहते हैं. उन्होंने सच न बताकर सभी लोगों को परेशान कर रखा है. मेरी मांग है कि इस क़ानून पर सरकार अपनी नीति व नीयत साफ़ करे. जहां तक मुझे जानकारी है, नीतीश सरकार देर सबेर इस क़ानून को लागू करना चाहती है.

***कांग्रेस से आपके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे. बिहार और झारखंड में उससे तालमेल पर आप क्या सोच रहे हैं?***

दिल्ली में ताक़त की पूजा होती है. लोकसभा में हमारी ताक़त घटी तो कुछ लोगों ने सोनिया जी को बरगला दिया, लेकिन हम बात के पक्के हैं. अगर साथ देने का वादा किया है तो निभाएंगे. सोनिया व राहुल गांधी का हम पूरा सम्मान करते हैं. सांप्रदायिक ताक़तों को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम कोई भी क़ुर्बानी देने के लिए तैयार हैं. जहां तक तालमेल का सवाल है तो हम दिल्ली में कह आए हैं कि अगर झारखंड में राजद व कांग्रेस का तालमेल न हुआ तो सत्ता भाजपा के हाथ में चली जाएगी. मैं साफ़ बोलने वाला आदमी हूं, इसलिए सच्ची बात कहने से नहीं डरता. बिहार में तालमेल के लिए मैंने पहले भी पहल की थी. हम तो चाहते हैं कि नीतीश सरकार की विदाई हो. गेंद कांग्रेस के पाले में है, अब उसे ही फ़ैसला करना है.

***रामविलास पासवान तो आपके साथ हैं. और किन किन दलों को आप साथ लाना चाहते हैं?***

मैं सबको साथ लेकर चलने वाला आदमी हूं. इस निकम्मी सरकार को बाहर करना है. जनता भी अपना मूड बना चुकी है, उपचुनाव में यह बात साबित हो चुकी है. इसलिए वामदल हों या और भी छोटी-बड़ी पार्टियां, सभी मिलकर राज्य के हित की बात सोचें और मज़बूती से चुनावी अखाड़े में कूदने का मन बनाएं.

feedback@chauthiduniya.com

# शस्त्र पूजा में गंवा दी जान

संध्या पाण्डे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वरूप अब बदलता जा रहा है. भाजपा शासित राज्यों में वह अपनी छवि को उग्र एवं हिंसक हिंदूवादी छवि में परिवर्तित कर रहा है. मध्य प्रदेश में तो ऐसा साफ़ दिखने भी लगा है.

आरएसएस की शह पर ही राज्य के अधिकारियों के हौसले भी बुलंद हैं. हर अधिकारी ख़ुद को आरएसएस की विचारधारा के क़रीब दिखाना चाहता है. पिछले दिनों दशहरा के अवसर पर आयोजित होने वाली शस्त्र पूजा में ऐसा ही कुछ देखने को मिला.

शस्त्र पूजा के दौरान जहां राजधानी के पुलिस अधीक्षक जयदीप प्रसाद ने ख़ुद जमकर हवाई फायर किए, वहीं उनके सात वर्षीय बेटे ने भी हवा में गोलियां चलाईं. और तो और, संघ का एक कार्यकर्ता किसी अन्य के असलहे से निकली गोली का शिकार होकर अचानक काल के गाल में समा गया. संघ के स्वयंसेवकों ने दशहरे के दिन राज्य के कई हिस्सों में जमकर फायरिंग की. चूंकि, इस हवाई फायरिंग को शस्त्र पूजा से जोड़कर देखा जा रहा है, इसलिए पुलिस ने भी किसी के ख़िलाफ़ कहीं कोई मामला दर्ज़ नहीं किया.

दशहरे के दिन मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में संघ कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से हथियार लेकर बाहर निकलने की ख़बरें सुनने को मिली हैं. मालूम हो कि विजयादशमी का त्योहार संघ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन पथ संचालन के अलावा संघ कार्यकर्ता सामूहिक रूप से शस्त्रों की पूजा करते हैं. राज्य में भाजपा

फोटो- पीटीआई

की सरकार होने के कारण इस बार बिना किसी पूर्व अनुमति के शस्त्र पूजन के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर शस्त्र संचालन का कौशल भी इन कार्यकर्ताओं द्वारा बेख़ौफ़ दिखाया गया. यही नहीं, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भी संघ की इस शस्त्र पूजा में खुलकर शामिल हुए.

भोपाल के पुलिस अधीक्षक जयदीप प्रसाद ने न सिर्फ़ ख़ुद हवाई फायर किए, बल्कि उनके सात वर्षीय बेटे को भी पुलिसवालों ने हवाई फायर का ग़ैर-कानूनी अवसर प्रदान किया, जबकि क़ानून के अनुसार किसी अवयस्क के हाथों में कोई हथियार होना या उसका संचालन वर्जित है. राजधानी पुलिस जिस समय संघ कार्यकर्ताओं के साथ एसपी साहब के उत्साह को बढ़ा रही थी, उसी समय कहीं से आई एक गोली शस्त्र पूजा कार्यक्रम में शामिल संघ कार्यकर्ता नरेश मोटवानी की गर्दन को भेद गई और मौक़े पर ही उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले की जांच किए बिना ही इसे महज़ एक हादसा करार दे दिया. जबकि मोटवानी के बेटे ने इसके पीछे हत्या का संदेह व्यक्त किया है. संघ कार्यालय में हुई इस घटना के दौरान क़रीब पचास स्वयंसेवक मौजूद थे. इस तरह की वारदातों से भले ही आम जनजीवन प्रभावित होता हो, किसी की जान जाती हो, लेकिन संघ के लोगों का यह मानना है कि शस्त्र संचालन की इस परंपरा से कार्यकर्ताओं में एक नया आत्मविश्वास पैदा होता है.

उधर, खरगौन ज़िला शस्त्रागार में हुई पूजा के दौरान एसएलआर से अचानक फायर हो गया और गोली खरगौन के पुलिस अधीक्षक प्रमोद वर्मा की कनपटी के पास से होकर गुज़र गई. यदि वर्मा अपनी जगह से थोड़ा भी इधर-उधर होते तो वह किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते थे. यह बात अलग है कि इसके बावजूद, पुलिस अधिकारियों ने पूजन के बाद शस्त्रागार में उपलब्ध एसएलआर से जमकर हवाई फायरिंग की.

feedback@chauthiduniya.com

हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके जनादेश का सम्मान कर बोर्ड नहीं गठित कर सके, चार अक्टूबर को सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी जनता को यह सफ़ाई दे रही थीं.

# पटरी से उतरी ममता की गठबंधन एक्सप्रेस?

**सिलीगुड़ी में स्थानीय निकाय के चुनाव में मेयर पद तृणमूल की झोली में नहीं आया. तृणमूल को सहयोगी कांग्रेस का साथ नहीं मिला और इसके साथ ही कांग्रेस-तृणमूल गठबंधन के भविष्य पर सवाल भी उठने लगे हैं.**



बिमल राय

हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके जनादेश का सम्मान कर बोर्ड नहीं गठित कर सके– चार अक्टूबर को सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी जनता को यह सफ़ाई दे रही थीं. निशाने पर वह कांग्रेस पार्टी थी, जिसकी सरकार में वह रेल मंत्री हैं. वही कांग्रेस पार्टी, जिसने पिछली केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेने वाले वाममोर्चा की मदद से सिलीगुड़ी नगर निगम का मेयर पद हासिल किया है और विडंबना यह कि तृणमूल कांग्रेस के पार्षद यहां विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं. ममता कांग्रेस के इस कृत्य को राजनीतिक अपराध और विश्वासघात बता रही हैं. पर सवाल यह है कि जनता से विश्वासघात किसने किया है? अपनी एकता के बूते लगातार कामयाबी की सीढ़ियां नाप रहे विपक्ष के इन दो खेमों को क्या अपने अंदर झांककर नहीं देखना चाहिए कि स्थानीय निकायों जैसे छोटे लक्ष्य के लिए वे जनता में फिर वही आशंका क्यों पैदा कर रहे हैं, जिसे पिछले 30 सालों तक दूर नहीं किया जा सका था?

हाल में हुए कई चुनावों से साफ़ हुआ है कि जनता ने 33 सालों से बंगाल में सत्ता पर क़ाबिज़ वाममोर्चा को हटाने का मन बना लिया है. 47 वार्डों वाले सिलीगुड़ी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस व तृणमूल गंठबंधन ने 30 सीटों पर क़ब्ज़ा जमाया और वाममोर्चे को केवल 17 सीटें मिलीं. इनमें कांग्रेस को 15 और तृणमूल के पास 14 सीटें हैं. विपक्षी खेमे में एक सीट निर्दलीय के खाते में गई, जिसे पूरे 15 दिनों तक रस्सी की तरह खींचा जाता रहा. आख़िर, कांग्रेस ने उसे पटा लिया. तीन दशक बाद वहां विपक्षी झंडा लहराया और उत्तर बंगाल के मुख्यमंत्री माने जाने वाले अशोक भट्टाचार्य का भ्रम भी टूटा. इसके पहले यानी 2004 के नगर निगम चुनाव में वाममोर्चे को 38, कांग्रेस को चार और तृणमूल को पांच सीटें मिली थीं. 15 सितंबर को परिणाम आने के बाद पूरे 15 दिनों तक गतिरोध बना रहा. ममता मेयर पद की मांग पर अड़ी रहीं.

यही नहीं, उन्होंने दिल्ली में भी इस मामले पर कांग्रेसी नेताओं से बात नहीं की. इसके पहले कोलकाता के बहूबाज़ार और सियालदह सीटों में से ममता ने एक भी सीट नहीं दी और यहां भी ममता ने कांग्रेस पर अपना डंडा चलाना चाहा. पर सब गड़बड़ा गया.

**हाल में हुए कई चुनावों से साफ़ हुआ है कि जनता ने 33 सालों से बंगाल में सत्ता पर क़ाबिज़ वाममोर्चा को हटाने का मन बना लिया है. 47 वार्डों वाले सिलीगुड़ी नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस व तृणमूल के गठबंधन ने 30 सीटों पर क़ब्ज़ा जमाया और वाममोर्चे को केवल 17 सीटें मिलीं.**

एक अक्टूबर को सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस को ज़ोर का झटका लगा. मेयर पद के लिए हुए मतदान का परिणाम आया तो ममता के होश उड़ गए. कांग्रेस की गंगोत्री दत्त को 32 व तृणमूल कांग्रेस के गौतम देव को 15 मत मिले. वाममोर्चा के 17 पार्षदों के समर्थन से गंगोत्री दत्त मेयर की कुर्सी पर बैठ गईं. सिलीगुड़ी की राजनीति में ग़ैर-बंगाली वोट काफी निर्णायक है, इसलिए पिछले वाममोर्चा बोर्ड की तरह चेयरमैन का पद कांग्रेस ने एक हिंदी भाषी महिला को दिया है. वाममोर्चा ने दिलीप सिंह को चेयरमैन बनाया था. दिलीप ने चौथी दुनिया को बताया कि समर्थन देने के बावजूद हम विपक्ष में हैं और सत्ता में भागीदारी नहीं कर रहे हैं. चुनाव के बाद विरोध की चिंगारी उठने लगी. तृणमूल ने वाकआउट किया. एक निर्दलीय समेत 15 पार्षद वहां से उठकर चले गए. तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने बाघाजतीन पार्क में पंडाल व कुर्सियों को तोड़ दिया. कुछ तो इतने नाराज़ हैं कि वे सीधे दीदी से अपनी बात कहना चाहते हैं, पर सवाल हिम्मत का है. हक़ीक़त है कि तृणमूल के किसी नेता में इस तरह की हिम्मत कभी दिखी भी नहीं. कांग्रेस ने प्रस्ताव दिया था कि अगर तृणमूल मेयर पद से दावा छोड़ दे तो उसे उप मेयर, चेयरमैन, पांच मेयर इन कौंसिल विभाग और दो बोरो कार्यालय प्रमुख पद दिए जा सकते हैं. दूसरा फ़ार्मूला था– बारी-बारी से दोनों दल ढाई-ढाई साल के लिए सत्ता सुख प्राप्त करें. मगर ममता मेयर पद के लिए अड़ी रहीं.

सांसद दीपा दासमुंशी ने मानो इस बार ममता को करारा जवाब देने की ठान ली थी. उन्हें मनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई, बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष व वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी और बंगाल कांग्रेस के प्रभारी केशव राव को. दीपा ने इन नेताओं से साफ़ कहा कि अगर इसी तरह ममता के आगे घुटने टेकते रहा जाए तो 2011 के विधानसभा चुनाव आने तक पार्टी के मोल-तोल की क्षमता ही ख़त्म हो जाएगी. वैसे अगले महीने ही राज्य में दस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं.

2010 में कोलकाता नगर निगम के साथ-साथ 82 स्थानीय निकायों के चुनाव भी होंगे. इनमें कोलकाता नगर निगम काफी अहम है. जिस तरह ममता ने पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को कोलकाता या उसके आसपास की कोई सीट नहीं दी, उससे कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं. उसके हताश कार्यकर्ता या तो निष्क्रिय होते जा रहे हैं या मजबूरन तृणमूल का दामन थाम रहे हैं. इसी वजह से सिलीगुड़ी प्रकरण पर कांग्रेस का दावा काफी मज़बूत लग रहा था. ममता अगर यह मानती हैं कि दक्षिण बंगाल में कांग्रेस का वैसा जनाधार नहीं है तो उत्तर व मध्य बंगाल में तृणमूल का भी संगठन ढीला-ढाला है और इन इलाक़ों में माकपा की संगठनात्मक ताक़त और बाहुबल का जवाब कांग्रेस ने ही दिया है. दीपादास मुंशी ने काफी कम समय में लोकप्रियता हासिल की है. यह मानकर कि राज्य में वामविरोधी हवा केवल मैंने बनाई है, ममता बंगाल के राजनीतिक नक्शे पर केवल ख़ुद का प्रभाव देखना चाहती हैं. यह काफी हद तक सही भी है कि सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलनों के बूते ही बदलाव की बयार उठी है, पर केंद्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस के फैक्टर को ख़ारिज़ नहीं किया जा सकता. कांग्रेस के नेता अभी भी कह रहे हैं कि 2011 के चुनावों के लिए गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पर ममता का रुख़ गरम ही है. सवाल तो यही है कि टकराव के इन थपेड़ों से क्या गठबंधन बच पाएगा?

feedback@chauthiduniya.com

# कोई नहीं करता जनता की परवाह

***देश के सबसे बड़े सूबे की जनता का दुर्भाग्य तो देखिए, उसकी अगुवाई का दम भरने वाले एक नहीं, बल्कि चार-चार हैं. बावजूद इसके, उसकी दिक़्क़तों का कोई छोर नहीं है. वह क़दम-क़दम पर छली जा रही है. आख़िर कब तक चलेगा ऐसा?***

अजय कुमार

यह सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की ही नाकामयाबी की कहानी है. कोई भी दल जनता के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर रहा है. मायावती ख़ुद को दलित की बेटी कहती हैं, लेकिन इनके राज में दलित ही सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं. मुलायम सिंह ख़ुद को धरती पुत्र कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन ज़मीनी लड़ाई से वह भी परहेज़ करते हैं.

समाजवादी पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता से शायद हाथ न धोना पड़ता, अगर उसकी सरकार क़ानून व्यवस्था पर ज़रा भी ध्यान देती. लेकिन अफ़सोस, तब सत्ता के नशे में चूर मुलायम सिंह को अपनी ख़ामियां नहीं दिखीं. नतीजा यह हुआ कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश की लचर क़ानून व्यवस्था का ऐसा ढिंढोरा पीटा कि मुलायम सिंह पैदल हो गए. सारे समीकरण और भविष्यवाणियां धरी की धरी रह गईं. उधर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही मायावती ने क़ानून-व्यवस्था को सुधारने का बीड़ा उठा लिया. जनता मायावती से कुछ और भी उम्मीदें लगा बैठी, लेकिन उसे इस सरकार की हक़ीक़त जानने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा. जनता की सारी उम्मीदें तार-तार हो गईं. मायावती जनता की भलाई के लिए कम अपनी पार्टी का एजेंडा पूरा करने के लिए ज़्यादा लालायित थीं. जनता से अधिक ध्यान उन्होंने बुतों पर दिया. मायावती सरकार की तुलना मुलायम सरकार के पिछले कार्यकाल से की जाए तो दोनों के बीच कोई अंतर नहीं दिखता. कुछ मामलों में तो मुलायम सरकार वर्तमान सरकार से बेहतर थी. यह तो मायावती सरकार की ख़ुशनसीबी है कि उसके सामने एक मज़बूत विपक्ष का अभाव है. प्रदेश में नंबर दो की हैसियत रखने वाली समाजवादी पार्टी ने आगरा अधिवेशन के बाद ज़रूर कुछ तेज़ी दिखाई है. उसके कार्यकर्ता मायावती सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर दिख भी रहे हैं, लेकिन पार्टी द्वारा क़ानून-व्यवस्था और अन्य ज़रूरी मुद्दों को अभी भी ठीक से हवा नहीं दी जा रही है, जिसके सहारे शासन की नींद उड़ाई जा सके. यह हालत तब है, जबकि मुख्यमंत्री मायावती स्वयं स्वीकार कर चुकी हैं कि प्रदेश की क़ानून-व्यवस्था ठीक नहीं है. विक्रम सिंह को हटाकर कर्मवीर सिंह को नया डीजीपी बनाने की वजह भी प्रदेश की बिगड़ती क़ानून-व्यवस्था पर लगाम लगाना ही था. लेकिन, अभी तक क़ानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मायावती द्वारा उठाए गए सारे क़दम हवा-हवाई साबित हुए हैं.

प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है. महिलाओं के उत्पीड़न और उनके प्रति अन्य अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सभी ज़िलों में महिला थानों की स्थापना करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक कुछ ज़िलों में ही महिला थाने खुल सके हैं. उन थानों की हालत भी काफी बुरी है, वहां न पर्याप्त फोर्स है और न ही संसाधन. मायावती ने अभिसूचना संगठन को पुनर्गठित और मज़बूत करने के लिए इसका एक अलग संवर्ग गठित करने का निर्णय लिया था. अभिसूचना संगठन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए करोड़ों रुपये के उपकरण ख़रीदने के लिए पैसा भी मिल गया है, लेकिन संगठन को मज़बूत करने का काम कछुआ गति से चल रहा है. आला अफ़सरों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए गठित किए गए अंतर्विषयक विशेष अनुसंधान दल की हालत सफ़ेद हाथी बनकर रह गई है. मुख्यमंत्री के पास भ्रष्टाचार की शिकायतों का अंबार लगा हुआ है. इसमें मंत्री से लेकर अधिकारियों तक की शिकायतें शामिल हैं. प्रदेश में फ़िदायीन हमलों से निपटने के लिए एनएसजी कमांडो की तरह दो हज़ार कमांडो तैयार करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन आज तक कमांडो चयन की प्रक्रिया ही चल रही है. शासन के एक आला अफ़सर के अनुसार, मुख्यमंत्री ने क़ानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए जो क़दम उठाए थे, वे मील के पत्थर साबित हो सकते हैं, बशर्ते मुख्यमंत्री यह समीक्षा भी कर लेतीं कि उन क़दमों पर कितना अमल हुआ है? मुख्यमंत्री के क़रीबी अधिकारियों को एक दूसरे को नीचा दिखाने से ही फ़ुर्सत नहीं मिलती.

feedback@chauthiduniya.com

सैन्य आधुनिकीकरण जैसे गंभीर मसलों पर राजनीति और नौकरशाही का अड़ंगा ख़तरनाक संकेत है. देश की सुरक्षा के प्रति हमें गंभीर होना होगा.



# क्या भारत कमज़ोर राष्ट्र बन चुका है-II

**पिछले अंक में आपने पढ़ा कि किस तरह चीन भारत को हर तरफ़ से घेरने की साज़िश रच रहा है. इसके लिए वह भारत के पड़ोसी देशों से न सिर्फ़ रणनीतिक, बल्कि सामरिक स्तर पर भी पींगे बढ़ा रहा है. अब पढ़िए इससे आगे...**

फोटो- *पीटीआई*

सीमा मुस्तफा

चीन श्रीलंका के दक्षिण में हमबनटोटा बंदरगाह के निर्माण में लगा हुआ है, जिससे वह भारतीय जल सीमा में आसानी से पहुंच सकता है. सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस इलाक़े में चीन की पीएलए नेवी (पीएलएएन) परमाणु शक्ति से लैस बैलेस्टिक पनडुब्बी सहित ब्लू वाटर फोर्स की तैनाती की योजना बना रहा है. दिलचस्प बात यह है कि श्रीलंका ने सबसे पहले इस परियोजना के लिए भारत को आमंत्रित किया था, लेकिन भारत के इंकार ने चीन के लिए दरवाज़े खोल दिए.

चीन ने श्रीलंका को तमिलों से निपटने के लिए एंटी एयर क्राफ्ट गन सहित विभिन्न रेंज के कई हथियार भी सप्लाई किए. श्रीलंका के रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के भाई गोताबया राजपक्षे ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम के नारायणन सहित भारतीय अधिकारियों को दिल्ली में बताया कि सुरक्षा मजबूरियां हमें चीन, पाकिस्तान और दूसरे आपूर्तिकर्त्ताओं से सैन्य हथियार ख़रीदने के लिए बाध्य कर रही हैं.

चीन अर्से से पाकिस्तान का परमाणु और सामरिक सहयोगी रहा है और उसने नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए बांग्लादेश से भी समझौते किए हैं, जिसकी बदौलत उसे इन क्षेत्रों में कोयला और प्राकृतिक गैस की खोज का अधिकार मिल गया है. चीन अपना आर्थिक और कूटनीतिक विस्तार नेपाल में भी कर रहा है. इस दिशा में क़दम उठाते हुए उसने अपना समर्थन अपदस्थ राजा की जगह अब माओवादियों को देना शुरू कर दिया है. जबकि भारत इस पूरे मामले में अपनी भूमिका को लेकर दुविधा की स्थिति में रहा है. म्यांमार में भी इसकी मौजूदगी के प्रत्यक्ष सबूत मिले हैं, जहां यह अक्याब, कोकोस द्वीप, हैंगयी, खॉक्फ्यू, मेरगुई और ज़दत्कयी में रडार लगाने के ज़रिए नेवल बेस के आधुनिकीकरण का काम कर रहा है. इससे चीनी पनडुब्बियों को अंडमान और भारतीय जल सीमा में ऑपरेशन के दौरान मरम्मत और ईंधन भरने की सुविधा मिलेगी. अगस्त 2008 में, भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को इस बात की भी सूचना मिली थी कि चीन कोकस द्वीपीय इलाक़े में संचार व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा है. साथ ही, उसकी योजना एक हैली पैड बनाने की भी है.

भारत को घेरने के लिए इसके नाभिकीय प्रतिद्वंद्वी और चीनी सहयोगी पाकिस्तान ने भी म्यांमार को गत वर्षों में सैन्य साज़ो-सामान और आयुधों की आपूर्ति की है. पाकिस्तान म्यांमार के सैनिकों को चीनी टैंक, फाइटर एयरक्राफ्ट और तोप चलाने की ट्रेनिंग भी देता रहा है. वर्ष 2001 से पाकिस्तान ने म्यांमार में अपना एक स्थाई रक्षा प्रतिनिधि भी नियुक्त कर रखा है. इस दौरान बीजिंग ने भारत को स्पष्ट किया है कि तिब्बत और अरुणाचल का मुद्दा काफी संवेदनशील है और वह आधिकारिक और ग़ैर-आधिकारिक दोनों रूप से इस मसले को उठाता रहेगा. चीन ने एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत को कर्ज़ देने का विरोध किया, क्योंकि इस धन को अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए ख़र्च किया जाना था. अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा मानने की वजह से ही उसने एक वरिष्ठ अधिकारी को वीज़ा देने से इंकार कर दिया. सरकारी अधिकारियों का पक्ष लेते हुए चीनी मीडिया ने भी हाल में भारत के प्रति आलोचनात्मक रुख़ अख्तियार किया है. चीनी मीडिया ने भारत-अमेरिकी परमाणु संबंधों को लेकर भी कड़ा रुख़ दिखाया. उसका कहना है कि भारत, अमेरिका का सबसे क़रीबी रणनीतिक और सैन्य सहयोगी बनता जा रहा है.

राजनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर दोनों देशों के बीच पिछले दो सालों से गहमागहमी चल रही है. प्रमाण, वर्ष 2007 की तुलना में 2008 में चीन की तरफ़ से 170 की जगह 203 बार सीमा उल्लंघन का मामला सामने आया, जिसमें अधिकतर मामले अरुणाचल प्रदेश के ही थे. सैन्य अधिकारियों का कहना है कि चीन चूहे-बिल्ली के इस अंतहीन खेल में भारतीय सामरिक क्षमताओं की परीक्षा ले रहा है. ले. जनरल ओबराय के मुताबिक़, भारत ने इस दिशा में अभी क़दम उठाया ही है. उन्होंने नई दिल्ली से अनुरोध किया कि भारत को भी इस क्षेत्र में अपनी शीघ्र पहुंच बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए. वर्षों से इस इलाक़े को नज़रअंदाज़ करने के बाद भारत ने भी चीनी सुविधाओं का मुक़ाबला करने के लिए अब यहां सड़कें, पुल और हवाई पट्टियां बनानी शुरू कर दी हैं. फिर भी, भारत को चीन के साथ इस क्षेत्र में बराबरी करने में कम से कम 15 साल लग जाएंगे. सेना की कई टुकड़ियां यहां 1962 के युद्ध के बाद से ही तैनात हैं, लेकिन वह भी किसी सामान की सप्लाई के लिए आसपास के जानवरों पर ही निर्भर रहते हैं. भारतीय सेना को इन इलाक़ों तक पहुंचने में 15 दिन का वक़्त लगता है, जबकि चीनियों के पास हर तरह की परिवहन सुविधा उपलब्ध है. सरकार ने भी दो आर्मी डिवीज़न या 50,000 के आसपास सैनिकों को बहाल कर अपने इरादे ज़ाहिर कर दिए हैं. चीनी सीमा के पास तेज़पुर में सुखोई 30 एमके 1 और 36 फाइटर एयरक्राफ्ट को भी तैनात करने की योजना है. तेज़पुर में मिग 21 के रनवे का निर्माण हाल ही में दोबारा किया गया है. ग़ौरतलब है कि सुखोई 30 एमके 1 चीन के अंदरूनी इलाक़ों को भी निशाना बनाने की क्षमता रखता है. लेकिन, भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी बाधा सेना के आधुनिकीकरण और ठोस रणनीतिक पहल की है.

रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने हाल ही में कहा कि सरकार की आत्मनिर्भर बनने की घोषणा के बावजूद इस देश को अपने 70 फ़ीसदी सैनिक साज़ो-सामान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है. ऐसे हालात बेहद शर्मनाक और ख़तरनाक हैं. संसद में उन्होंने कहा कि हमने यह लक्ष्य 50 साल पहले तय किए थे, लेकिन हम अभी भी 70 फ़ीसदी सामान का आयात करते हैं. ले. जनरल ओबराय के मुताबिक़, रक्षा क्षेत्र ऐसा है, जिस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया. सरकार मक्खन और बंदूक़ के बीच अंतर करने में भी नाकाम रही है. रक्षा मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पैसे का आवंटन कभी मसला नहीं रहा, बल्कि मुद्दा यह है कि इस पैसे का उपयोग सही समय पर सही तरीक़े से नहीं किया गया. उन्होंने अपने कार्यकाल को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि अभी काफी कुछ करना बाक़ी है. वित्त वर्ष 2008-09 के फ़ैसले में देरी की वजह से रक्षा मंत्रालय को आवंटित 48,000 करोड़ रुपये में से 7000 करोड़ रुपये सरकार को वापसकरने पड़े. रक्षा मंत्रालय की पांच वर्षीय कार्य योजना प्रासंगिक नहीं है. जबकि इससे जुड़े मसले 15 साल के अंतराल के बाद वर्ष 2002 में जारी किए गए. जबकि ताज़ा मुद्दा अभी लंबित पड़ा है. चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का मामला भी अभी लंबित पड़ा हुआ है, जो रक्षा, सिविलियन और राजनीतिक प्रतिष्ठानों के बीच महत्वपूर्ण इंटरफेस के तौर पर काम करता. साथ ही साज़ो-सामान की ख़रीद-फ़रोख्त और संचालन प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभा सकता था. सरकार ने एक समझौते के तहत रक्षा मंत्रालय और अन्य सेवाओं के बीच तालमेल बनाने के लिए अक्टूबर 2001 में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को मंजूरी भी दी. स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड की औपचारिक शुरुआत इसी साल से हुई. पूर्वी तट पर अंडमान और निकोबार में भारत का एकमात्र ट्राई सर्विस कमांड है और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी सहित सभी एजेंसियों को सीडीएस के तहत काम करना था. जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, हमें किसी फ़ैसले के लिए राजनेताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर रक्षा प्रमुख को फ़ैसला लेना चाहिए. सबसे अहम मुद्दा है रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारतीय सेना की क्षमताओं को बढ़ाने का, जिससे आम लोगों सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. सेना और नौकरशाहों के बीच मतभेद निर्णय लेने की प्रक्रिया में बाधा पैदा करते हैं.

ले. जनरल ओबराय यह भी कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर न तो राजनेता प्रतिबद्ध हैं, और न ही नौकरशाह. वह कहते हैं, आप बस किसी पुलिसवाले को शीर्ष पर बैठा दीजिए और वह केवल पाकिस्तान को सबूत भेजने का काम करता रहेगा. वहीं राजनयिक चंद्रा के मुताबिक़, समस्या यह है कि हमारे ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई की गई, उसके पर हमने जवाबी कार्रवाई नहीं की. हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं. जबकि होना यह चाहिए कि जब भारतीय हितों पर आंच आए तो सरकार को हमेशा कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए.

*( लेखिका विश्वविख्यात पत्रकार हैं )*

feedback@chauthiduniya.com

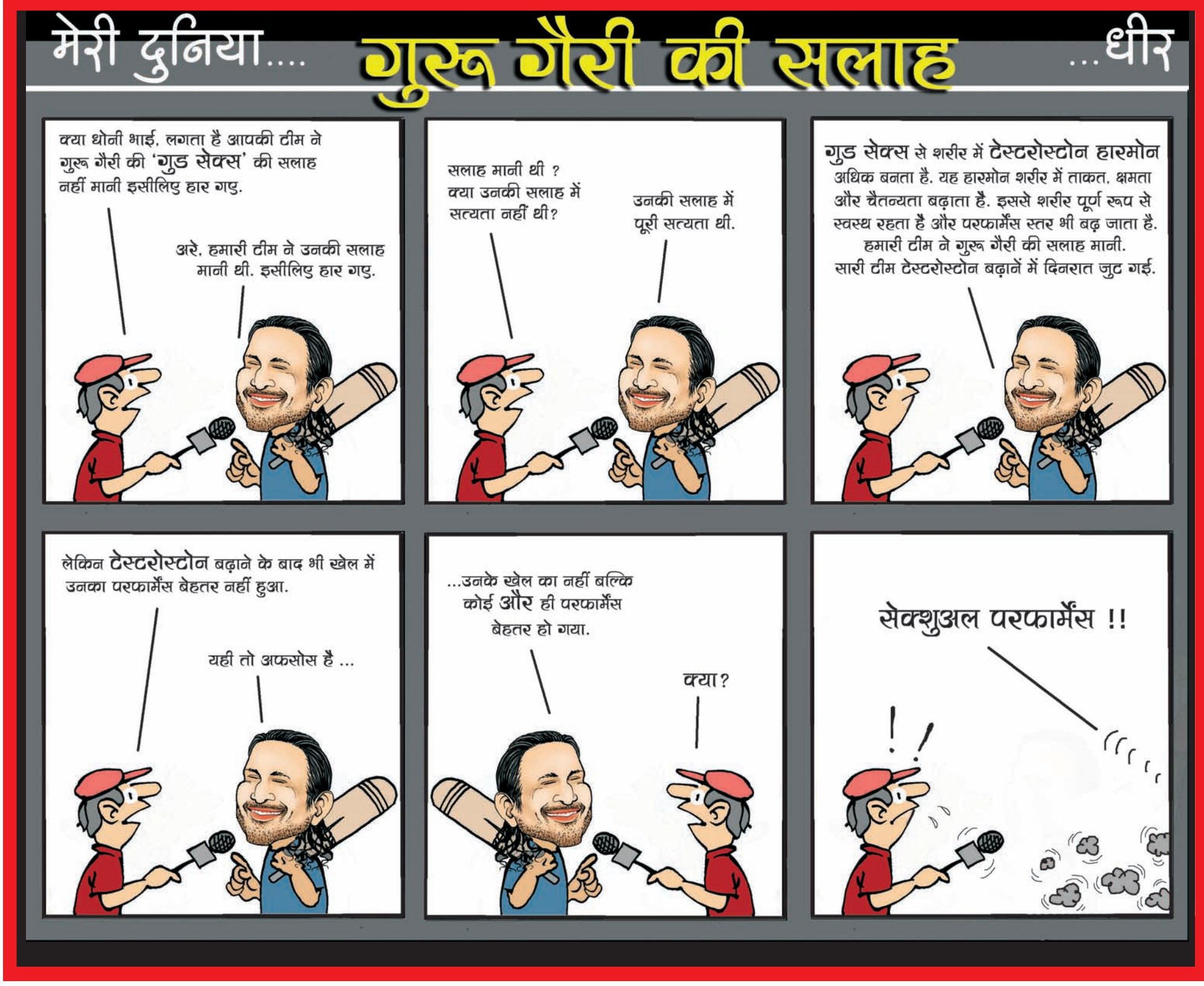

प्रकृति की गोद में बसे औली में सैफ खेलों की तैयारियां चल रही हैं. इससे पर्यावरण को जो नुक़सान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? कहीं ऐसा न हो कि यह औली के मूल स्वरूप को ही नष्ट कर दे.



# ...इतनी बड़ी क़ीमत चुकाएगी देवभूमि?

राजकुमार शर्मा

देवभूमि उत्तराखंड सदियों से अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात रहा है. यहां आने वाला हर पर्यटक कभी चमोली जनपद के जोशीमठ स्थित औली बुग्याल को देखने के लिए मचल उठता था, लेकिन इन दिनों सैफ खेलों के चलते इस पूरी बुग्याल में हर क़दम पर त्रासदी ही त्रासदी नज़र आ रही है. औली में सैफ खेलों की तैयारियां चल रही हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की तैयारी और इसे संपन्न करके सूबे को एक तमगा तो ज़रूर मिल जाएगा, किंतु प्रकृति को क्षति पहुंचाने की एक बड़ी क़ीमत भी इसे ज़रूर चुकानी पड़ेगी.

औली के बुग्यालों को काटकर स्कीइंग ट्रैक तैयार किया जा रहा है, जिसे देख हर पर्यावरण प्रेमी का दिल कराह उठता है. एक पर्यावरण प्रेमी कहते हैं कि यह देख ऐसा लगता है कि जैसे हरी मखमली चादर को बिल्ली ने अपने पंजों से नोच डाला हो. जिन बुग्यालों में कभी भेड़-बकरियां मिमियाती थीं, इन दिनों उन्हें काटने के लिए हर तरफ़ मशीनें नज़र आ रही हैं. इस कटाव व बरसाती पानी के रिसाव के चलते बुग्यालों में जगह- जगह दरारें पड़ गई हैं और उसका मलवा औली के ठीक नीचे बसे जोशीमठ में तबाही मचा रहा है. एक तरह से यह खेल प्रकृति के साथ अन्याय का एक नमूना बन चुका है, जिसे मानव अपनी निजी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए खेलने के प्रयास में है. यह देखकर पर्यावरण प्रेमी सहज ही कह उठते हैं कि एक ओर उत्तरकाशी में वरुणावत को थामने का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है, दूसरी ओर सैफ खेलों की आड़ में एक और वरुणावत औली में स्वयं तैयार किया जा रहा है.

मालूम हो कि यहां प्रभावशाली वर्ग के किलिफ टॉप क्लब को छोड़कर इस स्कीइंग ट्रैक और रोपवे के मार्ग में जो कुछ भी आ रहा है, उसे उखाड़ फेंका जा रहा है. गोल्डेन ओक के कई हज़ार वृक्षों को बलि के लिए चिन्हित किया जा चुका है. औली को बर्फ देने की ज़िम्मेदारी अब इन खरसू के वृक्षों के स्थान पर स्कीइंग ट्रैक के किनारे लगी लंबी लंबी स्नोगन्स की होगी, जो अपनी लंबाई से तक़रीबन तीन गुना ऊपर पानी की बौछारें कर बर्फ बनाएंगी. इन बौछारों के लिए पानी लगभग 12 किलोमीटर दूर बौड़कुंड से छह इंच मोटे पाइप द्वारा पहुंचाया जाएगा, जहां इसे एकत्रित करने के लिए एक झील भी बनाई गई है. औली में एशिया की सबसे बड़ी रोपवे इसलिए लगाई गई थी कि जब प्रकृति प्रदत्त चादरों से यह बुग्याल ढक जाए तो पर्यटक यहां पहुंच कर प्रकृति का आनंद ले सकें. अपनी मखमली घास के लिए मशहूर यह बुग्याल यहां के चुनिंदा रमणीक स्थानों में से एक है. लेकिन, कुछ अति महत्वाकांक्षी लोगों को आज इन बुग्यालों में कृत्रिम बर्फ की ज़रूरत दिखाई देती है. संभव है कि यहां भविष्य में कृत्रिम घास उगाने का काम भी शुरू हो जाए. राज्य सरकार ने भी करोड़ों रुपये ख़र्च करके प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की अनुमति दे दी है. इस तरह पर्यावरण को नुक़सान पहुंचाने का खेल खुलेआम जारी है.

**सैफ खेलों के चलते औली के बुग्यालों के सामने खासा बुरा समय आ गया है. इन बुग्यालों को काटकर लंबा चौड़ा स्कीइंग ट्रैक तैयार किया जा रहा है, जिसे देख हर पर्यावरण प्रेमी का दिल कराह उठता है. एक पर्यावरण प्रेमी कहते हैं कि यह देख ऐसा लगता है कि जैसे हरी मखमली चादर को बिल्ली ने अपने पंजों से नोच डाला हो. जिन बुग्यालों में कभी भेड़-बकरियां मिमियाती थीं, इन दिनों उन्हें काटने के लिए हर तरफ़ मशीनें नज़र आ रही हैं.**

इस देवभूमि में संपदा के नाम पर पर्वत, जंगल, कलकल करती नदियां और मनोहारी बुग्याल ही तो हैं, जिनका हम किसी न किसी बहाने हमेशा दोहन कराते रहे हैं. प्राकृतिक संपदा से धनार्जन की चाह में हम और हमारी सरकार इसे खोखला करने की छूट दे देते हैं. इसी बात का प्रमाण हैं सैफ खेल.

आज स्थिति यह है कि दिसंबर के महीने में औली में हम कृत्रिम बर्फ पर निर्भर हो रहे हैं. आज यहां का हर पर्यावरण प्रेमी इस चिंता से ग्रसित है कि हज़ारों पेड़ों और बुग्यालों की बलि चढ़ाकर सैफ खेल भले ही संपन्न हो जाएं, लेकिन क्या इसके बाद भी औली में बर्फबारी स्नोगन मशीनें ही करेंगी? हर पहाड़ प्रेमी को पर्यावरण के नाम पर शोर मचाने वालों की चुप्पी रहस्यमय लग रही है और अखर भी रही है.

ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर शोर मचाकर लंबे भाषण करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की चुप्पी और उनकी आंखों में पट्टी बंधी देख पर्यावरण प्रेमी परेशान हैं. विंटर गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एस एस पांतगी का कहना है कि स्कीइंग के लिए स्लोप तो खोदना ही पड़ेगा, इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी. राज्य सरकार को इन खेलों के आयोजन से पहले ही अपने नफा नुक़सान का आकलन कर लेना चाहिए. जनता में आज भी यह सवाल उथल पुथल मचा रहा है कि सौ करोड़ रुपये ख़र्च करके स्कीइंग जोन बनाया जा रहा है या स्लाइडिंग जोन? औली से लगे सलूड डूंग्रा गांव के लोग अभी से भयभीत हैं कि औली के बाद अब गोरस्यूं बुग्याल की भी खैर नहीं है. उन्हें डर है कि कहीं औली की तरह उनके गांव में भी कुदरत के साथ छेड़छाड़ का खेल शुरू न हो जाए.

feedback@chauthiduniya.com

# कैसे दुरुस्त हो देश की आत्मा की सेहत?

फोटो– प्रभात पाण्डेय

डॉ. यतींद्र सिंह सिसोदिया

हिंद के गांव ही असली हिंदुस्तान हैं, वे देश की आत्मा हैं, ऐसा उन विद्वानों का मानना रहा है जो कभी सात समंदर पार से यहां घूमने और इसकी संस्कृति को क़रीब से जानने की गरज से आए थे. वही असली हिंदुस्तान यानी देश की आत्मा आज बदहाली का दंश झेलने को मजबूर है. भारत ग्रामीण समुदायों की भूमि रहा है, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा. तथ्यों पर ग़ौर करें तो गांव वैदिककाल से ही प्रशासन की इकाई रहा है. भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण चरित्र की प्रमुखता यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत से प्रमाणित होती है. क़रीब 74.2 करोड़ लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और कृषि के ज़रिए, जिसमें वानिकी व मत्स्य भी शामिल है, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 18 प्रतिशत का योगदान करते हैं.

ग्रामीण विकास भारत की एक निरपेक्ष व त्वरित आवश्यकता है. भारत जैसे विशाल देश का विकास उसकी तीन चौथाई आबादी और क्षेत्रफल को केंद्र में रखे बग़ैर नहीं हो सकता. विकास की संपूर्ण योजनाओं के नियोजन हेतु पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं, लेकिन आज़ादी मिलने के 62 वर्षों बाद भी जब हम ग्रामीण क्षेत्रों पर दृष्टि डालते हैं तो स्थितियां किसी भी संदर्भ में संतोषजनक नहीं दिखतीं.

ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोज़गार, बिजली, सिंचाई, पेयजल और सड़क जैसे आधारभूत क्षेत्रों में स्थितियां अपेक्षित लक्ष्यों से बहुत पीछे हैं. यह संदर्भ में इसलिए ज़्यादा तर्कसंगत और सामयिक लगता है, क्योंकि जब शुरू से लेकर आज तक ग्रामीण विकास हमारी संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया में सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है, तब भी हम लक्ष्यों से इतने दूर क्यों हो गए?

लगभग सवा सौ करोड़ की आबादी वाले इस देश में 328 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले जनसमुदाय के पास प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता और विविधता है. इसके बावजूद एक चौथाई आबादी ग़रीबी में जीवन यापन करने को मजबूर है. यद्यपि विकास एवं नियोजन की स्थितियों में आए बदलाव से 1950 की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जिसमें सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 60 प्रतिशत कृषि से था, घटकर 18 प्रतिशत रह गया है. वर्ष 1950–51 में जहां हमारा खाद्यान्न उत्पादन 50.8 मिलियन टन था, वह आज बढ़कर 212 मिलियन टन हो गया है. बावजूद इसके ग्रामीण परिदृश्य चुनौतियों से भरा और प्रश्न खड़े करने वाला है.

आज ज़रूरत संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया के सूक्ष्म विवेचन व आलोचनात्मक मूल्यांकन की है, जिससे यह पता लग सके कि बेहतरी की दिशा में किस क़दम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. यह स्पष्ट है कि बिना आधारभूत अधोसंरचनात्मक विकास के ग्रामीण विकास की पूरी बहस बेमानी और अर्थहीन है. यदि हम गांवों को पर्याप्त बिजली, सिंचाई व पीने के लिए पानी, बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थानीय स्तर पर समुचित व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो विभिन्न नामों व स्वरूपों में कार्यरत योजनाओं की सार्थकता सवालों के घेरे में ही रहेगी.

बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुशासन पहली शर्त होती है. इसके लिए ज़रूरी है कि सभी क्षेत्रों में कार्य निष्पादन आकलन की व्यवस्था विकसित हो, जिसमें सभी स्तरों पर पुरस्कार व दंड का प्रावधान होना चाहिए. ज़रूरत इस बात की भी है कि सरकार और उपयोगकर्ता समुदाय की विभिन्न स्तरों पर भूमिका एवं जवाबदेही तय हो. सरकार में उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी का भी विकास होना चाहिए. विकास कार्यों में स्थानीय जनता की भागीदारी और उसका विश्वास हासिल करना भी विशेष महत्त्व रखता है. हमें ख़ुद के मौन रहने की प्रवृत्ति भी त्यागनी होगी, जिससे विकास के नाम पर चला एक रुपया गांव तक पहुंचते पहुंचते केवल दस पैसे में न सिमट जाए.

*(लेखक मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन में प्रोफेसर हैं.)*

feedback@chauthiduniya.com

MURUGAPPA GROUP
BSA MOTORS e-Scooters

BSA मोटार्स आ गया
सबके दिलों पे छा गया।

BSA MOTORS की हर एक इलैक्ट्रीक स्कूटर की खरीद पर पाईये
"एक साल की बैट्री वारंटी" एवम् "Rs. 4000/- का कैश कार्ड मुफ्त"।

Conditions apply##
*Ex. showroom Price starting from Rs.15,450/- for Smile in Delhi after subsidy & cash card.
*$ Battery Warranty of 12 months / 12000 km's whichever is earlier & applicable.
*# Savings Vary from model to model.

**SHAHDARA: Binsar Auto Mobiles,** 954 - E, Main 100 Ft Road, Babarpur Extn.Shahdara. Phone: 011-22831100 / 22831400/9911994444/9911450121. **NAJAFGARH: CNS Retail Pvt Ltd,** Plot No. 1, Block – G, Gopal Nagar. Phone: 011 - 28015634 / 28010709/ 09958019000/9212365634. **DWARKA-MAIN PALAM DABRI ROAD: CNS Retail Pvt Ltd,** D - 70/5, Main Palam Dabri Road, Mahavir Enclave. Phone: 011 – 28011702/ 45017150/09818239724/ 9212275634/ 9212170006. **NANGLOI: CNS Retail Pvt Ltd,** Plot No 18, Ram Nagar Colony, Main Najafgarh Road, Nangloi. Phone: 9971734599 / 9213899686. **KRISHNA NAGAR: Agrawal Motors,** A-1/14. Krishna Nagar, Chachi Building Chawk,Near Lal Quarter Market. Phone: 011 – 22452829/09312835117. **KAROL BAGH: Imperial Cycles,** 53/2, Deshbandhu Gupta Road, Karol Bagh. Phone: 011-65461542/ 28722276/25717886/9811453355. **ASHOK NAGAR: New Golden Cycle Store,** 36/13, Ground Floor, Ashok Nagar. Phone: 9810807183. **NOIDA: Agrawal Motors,** B-41 & 42, Sector 16 , Near Mirula's Hotel, Gautam Budh Nagar. Phone: 0120-4249906/ 4232242/9312835117/ 09350906906. **ROHINI: Rocky Autolinks,** F 18/61, Rohini, Sector 8. Phone: 9811032353 (Opening Shortly)

एम जे अकबर

# आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिलाओं की सुनिए

र हर्कोट बटलर ब्रिटिश हुकूमत के बेहतरीन नौकरशाह थे. वह एक ऐसे प्रतिनिधि अधिकारी थे, जिन्होंने भारत को बख़ूबी समझा और महमूदाबाद के राजा की तरह ही भारतीयों के साथ दोस्ती को ध्यान में रखा. साथ ही, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे कई फ़ैसलों को जायज़ ठहराया. यूनाइटेड प्रोविंस (आज का उत्तर प्रदेश) का पूर्व गवर्नर होने के नाते, 16 जनवरी, 1916 को रंगून से उन्होंने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को पत्र के ज़रिए एक सुझाव भेजा. पत्र में उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया कि भारत में साधु-संतों और महिलाओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा है. और जब तक राजनीतिक संगठन इन दोनों को प्रभावित करने में सफल नहीं होते, तब तक ब्रिटिश सरकार को कोई ख़तरा नहीं है.

महात्मा गांधी ने 1920-21 में असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत को ज़बरदस्त झटका दिया. इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके इस आंदोलन में साधु-संतों का सहयोग तो था ही, इसके अलावा ये महिलाओं को घरों की चारदीवारी से बाहर निकालने में भी सफल हुए थे. उन्होंने भारतीय महिलाओं से कहा कि जिस तरह सीता ने रावण के भोग-विलास के लोभ-लालच का परित्याग किया था, ठीक उसी तरह यदि वे भी भौतिक सुख-सुविधाओं का त्याग कर, आज़ादी की लड़ाई में योगदान दें तो छह महीने में ही भारत से रावण राज (ब्रिटिश) ख़त्म हो सकता है. मुसलमानों का भी कुछ ऐसा ही सोचना था. मौलाना मुहम्मद अली की मां बी अम्मन मुस्लिम लीग को संबोधित करने वाली पहली महिला बनीं. यह भी ग़ौर करने की बात है कि हकीम अजमल ख़ां और एम ए अंसारी की बीवियों ने 1921 में महिला ख़िलाफ़त कमेटी का गठन किया.

नौ दशक बाद, साधु-संत और महिलाएं आज भी राजनीतिक गतिशीलता के सशक्त इंजन हैं. ठीक उसी तरह जैसे, एक लंबी कहानी में दिलचस्प मोड़ होते हैं. अब, महिलाओं का प्रभाव साधु-संतों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है. हालांकि, उनका सामाजिक विकास अभी भी नहीं हुआ है. इन समुदायों के बाहर और समुदायों में, दोनों में तीखा मतभेद है. लेकिन, एक आधुनिक कड़ी के तौर पर, आने वाले दशक में मुखर महिलाओं का ही दबदबा रहने वाला है.

अभी भी मुस्लिम वोटों का रुख़ उलेमाओं के फ़तवों से तय होता है. लेकिन, महिलाएं यदि हिजाब या बुर्क़ा में भी वोट देने के लिए आज क़तार में लग रही हैं, तो यह नए बदलाव के प्रमाण हैं. वे अब मतदान की ताक़त और महत्व को समझ चुकी हैं और मतदान करते वक़्त वो काफ़ी उल्लासित होती हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक फ़ायदा कांग्रेस को हुआ था. लेकिन, इसे दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में सुरक्षित अल्पसंख्यक बहुल सीट गंवानी पड़ी. कांग्रेस को इसके कारण की पड़ताल करनी चाहिए. आख़िर क्यों उसे इस हार का सामना करना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे में रहने वाली महिलाओं ने किचन में बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया था या पिछले साल बाटला हाउस एनकाउंटर पर उठे सवालों के जवाब मांगने शुरू कर दिए?

1980 के उत्तरार्ध और 1990 के पूर्वार्ध में बीजेपी का राम मंदिर अभियान इसलिए भी सफल रहा, क्योंकि वह महिलाओं तक अपना संदेश पहुंचाने में सफल रहे. उसने सभी महिलाओं से मंदिर के लिए एक-एक ईंट के सहयोग की मांग की, जिससे बीजेपी महिलाओं को अपना हितैषी बनाने में सफल रहा. लेकिन यह मॉडल अब पुराना हो चुका है या फिर यह उत्साही प्रक्रिया फीकी पड़ने लगी है. 1989 में जिस लड़की का जन्म हुआ होगा, उसने 2009 में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया होगा.

**अभी भी मुस्लिम वोटों का रुख़ उलेमाओं के फ़तवों से तय होता है. लेकिन, महिलाएं यदि हिजाब या बुर्क़ा में भी वोट देने के लिए आज क़तार में लग रही हैं, तो यह नए बदलाव के प्रमाण हैं. वे अब मतदान की ताक़त और महत्व को समझ चुकी हैं और मतदान करते वक़्त वो काफ़ी उल्लासित होती हैं.**




बीजेपी के ठहराव या पतन की आंशिक वजह यह भी मानी जा सकती है कि आज हिंदू महिलाओं की सोच बदल रही है. और भाजपा इन महिलाओं को पार्टी से जोड़ने में असफल रही है. यह कहानी केवल महानगरीय भारत तक ही सीमित नहीं है. छोटे शहरों में नक़ली ब्रांडों की मौजूदगी, इन आकांक्षाओं के विस्तार के सबूत हैं. यह एक सनक या फ़ैशन भर भी नहीं है. यह नई विचारधारा में घर कर गई है. आधुनिक महिलाओं के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली शस्त्र है-चुनाव, चुनने की आज़ादी. चुनाव, व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर एक आज़ादी है. हर बात को महिलाओं पर थोपना, झूठा हुक्मबरदारी, स्थिरता और सुरक्षा अब कल की कहानी है. आज की महिलाएं कहना चाहती हैं कि पोशाक, शादी, लाइफस्टाइल या मतदान आदि के लिए उनपर कोई दबाव नहीं डाला जाए. उन्हें यह कतई पसंद नहीं कि कोई उन्हें यह कहे, कि वो जिंस नहीं पहन सकतीं, वेलेन्टाइन डे नहीं मना सकतीं या वह शाम को यदि पब जाना पसंद करती हैं, तो पब नहीं जा सकतीं. भारतीय महिला पड़ोसी देश में रूढ़िवादिता की घुटन को आसानी से देख सकती हैं. जिसे वह भारत में कभी नहीं देखना पसंद करेंगी.

दिल्ली में यह ख़ासा चर्चा का विषय बना रहा कि कश्मीर घाटी में ईद इस बार सबसे शांतिपूर्ण तरीक़े से मनाया गया. ज़्यादा ख़ुशियां मत मनाइए. ऐसा पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में बहुत ही कम हो सकता है. यहां तक कि पाकिस्तान पर सरसरी निगाह डालने के बाद कश्मीरी युवा और ख़ासकर युवा महिलाएं कहती हैं, चाहे जो भी ख़ामियां हो, बस भारत ही बेहतर विकल्प हो सकता है. ऐसे कितने युवा होंगे, जो तालिबान के संगीनों के साए में जीना पसंद करेंगे. ऐसी कितनी युवतियां होंगी, जो उस जगह अपने भविष्य की तलाश करना चाहेंगी, जहां धर्मगुरु कठोर जेंडर लॉ लागू करने पर ज़ोर देते हैं? यदि वे ऐसा करते हैं, तो भारत इस लिहाज़ से कम बुरा देश है.

पाकिस्तान समर्थित कश्मीरी नेता, जमात-ए-इस्लाम के सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरी मुसलमानों से ईद न मनाने की अपील की, लेकिन उनकी इस अपील का कोई असर नहीं दिखा. 1947 में गिलानी नौजवान थे. 2009 का नौजवान 1947 के नौजवान को कोई अहमियत नहीं देता. दरअसल, जबतक आप अपने अस्तित्व के बोझ से मुक्त नहीं होना चाहते, तब तक अंतर्द्वंद्व का कोई सवाल ही नहीं है. युवा ज़िंदगी पसंद करते हैं, जबकि युद्ध भड़काने वाले पुराने लोग मौत की पेशकश करते हैं.

ज़िंदगी की ख़ुशियां और व्यक्तिगत आज़ादी का आनंद ही निकट भविष्य में भारतीय राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाले हैं. जो नेता इसे नहीं मानते हैं, उनकी प्रासंगिकता पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं. जीवन को महिलाओं से बेहतर भला कौन समझ सकता है. महिलाएं ज़िंदगी देती हैं. पुरुष इसे ग्रहण करते हैं.

इतिहास के हर दौर में महिलाएं साधु-संतों की बात सुनती आई हैं. अब वक़्त आ गया है कि साधु-संत महिलाओं की बातों पर ग़ौर फरमाएं.

feedback@chauthiduniya.com

## जब तोप मुक़ाबिल हो



संतोष भारतीय

# प्रधानमंत्री जी, अभी भी वक़्त है

केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और अब कांग्रेस को अपनी आंखें खोलनी चाहिए. जिस देश में सेना सरकार से नक्सलवादियों पर हमला करने की इजाज़त मांगे, भले बहाना लें कि जब उस पर हमला हो तब, तो स्थिति की विकरालता का अनुमान लग जाता है. सेना की भूमिका देश के भीतर है ही नहीं, उसे तो देश की सीमा की निगरानी और पड़ोसियों के हमले से बचाव के लिए तैयार किया गया है. क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि देश के नागरिकों के वंचित तबकों ने जगह-जगह हथियार उठा लिए और हमारी पुलिस, अर्द्ध सैन्य बल उनका मुक़ाबला नहीं कर पा रहे हैं? अब सेना को सामने आने की अनुमति मांगनी पड़ रही है.

कश्मीर में हम पाकिस्तान पर आरोप लगाते हैं कि वहां प्रायोजित आतंकवाद है. होगा भी. लेकिन आंध्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में क्या है? सारे उत्तर-पूर्वी राज्य, असम सहित उग्रवादियों के क़ब्ज़े में हैं. इन प्रदेशों के बहुत से क्षेत्रों में शाम होते ही लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं. इन क्षेत्रों को नक्सलवादी प्रभाव वाले क्षेत्र कहा जाता है, पर जहां इनका प्रभाव नहीं है, वहां भी शाम के बाद लोग घर में ही रहना पसंद करते हैं. ये कौन लोग और किस धर्म के हैं जिन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए हैं, जो जीने से ज़्यादा मरने में यक़ीन करते हैं. शिक्षा पाए अच्छे परिवारों के लड़के-लड़कियां, बड़े प्रतिष्ठित स्कूलों की पैदाइश एक अच्छी ख़ासी संख्या में गांवों में नक्सलवादियों के साथ घूम रही है और कह रही है कि व्यवस्था बदलो. व्यवस्था बदलो का मतलब सरकार क्यों नहीं समझ रही है? हमारे गृह मंत्री नक्सलवाद को हथियारों से कुचलना चाहते हैं, वे कुचल सकते हैं, कम से कम कोशिश कर सकते हैं. आज तक का अनुभव बतलाता है कि ऐसी कोशिशें जब भी हुई हैं, निर्दोषों का ख़ून ज़्यादा बहा है. एक मरता है, चार खड़े हो जाते हैं. हमारे प्रधानमंत्री नक्सलवाद को सबसे बड़ा ख़तरा बताते हैं, पर अर्थशास्त्र के ज्ञाता यह भूल जाते हैं कि इसके कारण भी तो उन्हें बताने हैं. वे बता नहीं पाएंगे, क्योंकि दरअसल जिस अर्थशास्त्र के वे ज्ञाता हैं, वही अर्थशास्त्र इस समस्या की जड़ है.

सरकारी योजनाएं असफल, सरकार का विकास अधूरा, ग़रीब को अर्थव्यवस्था में हिस्सा ही नहीं मिलता, जबकि उसका अधिकार सबसे ज़्यादा है. यही अर्थशास्त्र धर्म के आधार पर लोगों को बांट देता है. यह ज़मीन है जो नक्सलवाद को पैदा करती है.

जब ग़रीब अपनी आवाज़ उठाता है तो उसे आश्वासन मिलता है, जो कभी पूरा नहीं होता. ग़रीब अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखे तो सरकार उसकी समस्या को समस्या ही नहीं मानती. अभी दो साल पहले पच्चीस हज़ार ग़रीब ग्वालियर से पैदल चलकर दिल्ली आए थे. उनकी व्यथा को अख़बारों और टीवी में जगह नहीं मिली. जब वे दिल्ली पहुंचे तो उनके बीच उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह पहुंचे और उन्होंने सभी समस्याएं सुलझाने का वायदा किया. समस्याएं थीं, ज़मीन की बेदख़ली, अधिग्रहण न हो, ग़रीब को उजाड़ा न जाए, रोजी-रोटी के बारे में सोचा जाए. दो साल बीत गए पर कुछ नहीं हुआ. अब अक्टूबर के आख़िरी सप्ताह में तीन हज़ार लोग फिर दिल्ली आ रहे हैं और कहने जा रहे हैं कि अपना वायदा याद करो सरकार मनमोहन सिंह. अगर नहीं याद किया तो एक लाख लोग दिल्ली में करो या मरो के नाम से आएंगे और दिल्ली को ग़रीबों की ताक़त दिखाएंगे.

**हमारे गृह मंत्री नक्सलवाद को हथियारों से कुचलना चाहते हैं, वे कुचल सकते हैं, कम से कम कोशिश कर सकते हैं. आज तक का अनुभव बतलाता है कि ऐसी कोशिशें जब भी हुई हैं, निर्दोषों का ख़ून ज़्यादा बहा है. एक मरता है, चार खड़े हो जाते हैं. हमारे प्रधानमंत्री नक्सलवाद को सबसे बड़ा ख़तरा बताते हैं, पर अर्थशास्त्र के ज्ञाता यह भूल जाते हैं कि इसके कारण भी तो उन्हें बताने हैं.**

अभी सरकार नहीं चेत रही. ये एक लाख लोग अगर निराश हुए तो क्या होगा? हो सकता है, नए नक्सलवादी क्षेत्र बन जाएं. गृह मंत्री को क़ानून व्यवस्था का सवाल बनाते कितनी देर लगेगी. गृह मंत्री को भारत के सामाजिक दबाव, सामाजिक अंतर्विरोध, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब, लोगों का दु:ख, दर्द, भूख, प्यास, असमानता जैसे शब्दों का मतलब भी समझना चाहिए. और, तभी वे समझ पाएंगे कि सिर्फ़ क़ानून व्यवस्था का नाम लेने भर से समस्या हल नहीं होगी. देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बंदूक़ की भाषा से अलग सामाजिक बदलाव की भाषा भी समझनी चाहिए. अगर वे नहीं समझते तो हमें मान लेना चाहिए कि देर हो रही है और नौजवानों का धीरज चुक रहा है. उन्हें खोखले वायदों और ख़त्म होते अवसरों की सच्चाई का पता चल रहा है. वे निराश हो रहे हैं. उनकी निराशा अब वायदों की बारिश से नहीं भीगने वाली.

हमें कहते हुए बहुत ख़ुशी नहीं हो रही कि जिस दिन सेना भारत के आंतरिक क़ानून व्यवस्था के सवालों में उलझेगी, उस दिन लोकतंत्र का क्या होगा? सेना वहीं लोकतंत्र के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है, जहां सेना का नागरिक प्रशासन या उसकी असफलता से वास्ता पड़ा है. दुनिया के उन देशों की, जहां फौज शासन कर रही है या कर चुकी है, ऐसा ही इतिहास है.

तो अपने वायदों को याद कीजिए प्रधानमंत्री जी. सौ दिन का रिपोर्ट कार्ड क्या है? अगले सौ दिनों का कोई एजेंडा आप बनाने जा रहे हैं या हमें आपके बयान को नज़रअंदाज़ करने की आदत डाल लेनी चाहिए. आप राज्यों के विधानसभा चुनाव जीत जाएं बहुत अच्छा, हार जाएं तो भी लोगों की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क़ पड़ने वाला है? अभी तो आपका विरोध करने के लिए न भाजपा में इच्छाशक्ति है और न ही वामपंथियों में हिम्मत. शासक भी आप, विरोधी दल भी आप. लेकिन, यह ख़तरनाक हालत है. देश की जनता आपके हाथ से निकल न जाए, इसके लिए तत्काल चेतने की ज़रूरत है. देश को नई शिक्षा व्यवस्था, नए रोज़गार के अवसर, न्याय की भ्रष्टाचार रहित व्यवस्था तथा ग़रीब की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी जैसी बातें टालनी नहीं चाहिए. अपनी ज़िम्मेदारी समझिए और उसे निभाइए.

संपादक
editor.chauthiduniya.com



रवि किशोर

# पुलिस एनकाउंटर का राजनीतिक खेल

गुजरात पुलिस ने 19 वर्षीय, इशरतजहां और जावेद शेख़ सहित दो लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया. इस पर काफी विवाद भी हुआ. हाल ही में, इस विवादास्पद मुठभेड़ की जांच अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस पी तमांग ने की. जिसने कई लोगों, ख़ासकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए मानो भानुमति का पिटारा ही खोल दिया है. अहमदाबाद पुलिस की मुठभेड़ में 26 नवंबर, 2005 को मारे गए सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर पर भी इसी तरह के सवाल उठाए गए थे. गुजरात सरकार के मुताबिक़, सोहराबुद्दीन लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था और वह मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के इरादे से यहां आया था. एक साल बाद इलाहाबाद में, पुलिस द्वारा बताया गया कि पिंटू मिश्रा एक छोटा-मोटा अपराधी था, लेकिन अपने आतंकी संबंधों की वजह से ही उसे गिरफ़्तार किया गया. सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में, 2007 में, 18 वर्षीय अब्दुल रहमान को जैश-ए-मोहम्मद से संबंध होने की वजह से मार गिराया. इसी तरह, बाटला हाउस एनकाउंटर, जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मोहनचंद शर्मा भी मारे गए, मुद्दे पर भी तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाने शुरू कर दिए.

उपरोक्त सभी हत्याएं मीडिया में छाई रहीं. ये मुठभेड़ भले ही फ़र्ज़ी क्यों न हो, लेकिन इसे फ़र्ज़ी साबित करने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले. लेकिन, इसने सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान ज़रूर खींचा, ख़ासकर सोहराबुद्दीन के मामले में. सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के आतंक-निरोधक स्क्वाड प्रमुख डीजी वंजारा द्वारा 2003 से 2006 के बीच किए गए 21 एनकाउंटर मामले की भी सुनवाई चल रही है. इशरत के मामले में केंद्र सरकार ने यह स्वीकार किया कि गुजरात सरकार को उसने सूचना दी थी कि इन चार दोषियों के संबंध पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से है. लेकिन अब वह अपने इस हलफनामे पर फिर से विचार कर रही है. इन सबके बावजूद प्राय: हररोज़ हम फ़र्ज़ी पुलिस मुठभेड़ में निर्दोष लोगों के मरने की ख़बरें सुनते रहते हैं. इसके कई उदाहरण हैं, उत्तरांचल पुलिस ने इसी तरह ग़ाज़ियाबाद के एक छात्र को मार डाला था. पुलिस द्वारा किसी भी तरह की हत्या, मीडिया को अपनी ओर आकर्षित करती है. लेकिन, जब किसी ख़ास समुदाय के लोग मारे जाते हैं तो स्थिति बहुत ही विकट हो जाती है. इस तरह के मामले में, जो लोग राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, स्थिति को सामान्य से बहुत ही भयावह बना देते हैं. इसका बेहतर उदाहरण इशरत-जहां का है. इस मामले में पहले केंद्र सरकार ने बताया कि इन सभी के संबंध लश्कर-ए-तैयबा से है, लेकिन जब न्यायिक जांच में पता चला कि मुठभेड़ फ़र्ज़ी था तो केंद्रीय गृह मंत्री पल्ला झाड़ लिया. अब वे सारा दोष गुजरात सरकार पर मढ़ रहे हैं. इसी तरह या कहें कि इससे भी एक क़दम आगे बढ़कर, कुछ लोग बाटला हाउस एनकाउंटर मामले को अपने राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक रंग देने पर तुले हुए हैं. जबकि इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस को अपने एक बेहतरीन और जांबाज अधिकारी को भी गंवाना पड़ा. यहां तक कि राष्ट्रीय मानवाधिकार ने भी पुलिस को क्लीन चिट दे दी. फिर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.

पुलिस द्वारा हत्याओं पर सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ है. लेकिन, क्या हमेशा इस तरह के सवाल उठाना जायज़ है? क्या पुलिस को भी इस तरह के विवादों से बचने और इस मसले पर हो-हल्ला मचाने की ज़रूरत है ताकि वह कह सके कि पुलिस इससे भी बेहतर तरीक़े से आतंकवाद और दूसरी तरह की समस्याओं से निपट सकती है. यदि पुलिस को हमेशा इस तरह की जांच से गुज़रना पड़े तो इसका सीधा असर उसकी कार्यप्रणालियों पर पड़ सकता है. यदि हमेशा ऐसा ही होता तो पंजाब में कभी भी सामान्य हालात की बहाली ही नहीं हो पाती. के पी एस गिल की अगुवाई में पुलिस ने एक योजना के तहत आतंकवादियों से हर मोर्चे पर लोहा लिया जो न केवल उपयुक्त था, बल्कि बेहद कारगर भी साबित हुआ. यदि पुलिस पूरी तरह क़ायदे-क़ानून का पालन करे तो हमारा देश, जो अभी माओवाद की समस्या से बुरी तरह त्रस्त है, ये माओवादी ही हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता सहित भारतीय समाज के मूलभूत ढांचे को ही तहस-नहस कर देंगे.

पुलिस एनकाउंटर शब्द की उत्पत्ति भारतीय उप-महाद्वीप में ही हुई है. जिसे भारतीय पुलिस, अर्द्ध सैनिकबल, सेना और दूसरे रक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती है. वह भी इसलिए कि उसने किसी व्यक्ति की हत्या क्यों की है? पुलिस ऐसा मानती है कि उन्होंने जिसकी हत्या की है वो एक ख़ूंख़ार अपराधी, गैंगस्टर, आतंकवादी और माओवादी या नक्सलवादी है. ऐसा प्रावधान है कि क़ानून को ताक पर रखकर ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता. अधिकतर मामलों में मृतक के पास हथियारों को रख देना, इस बात की ओर इशारा करता है कि आख़िर क्यों उस व्यक्ति की हत्या की गई? मृतक के ख़िलाफ़ दर्ज़ एफ़आईआर पुलिस को इस तरह के कारनामे के लिए बढ़ावा देते हैं.

जिस तरह भारत में आतंकवाद का ख़तरा बढ़ा है, ऐसे में फ़र्ज़ी मुठभेड़ के मामले में नैतिकता का स्तर गिरता ही गया है. और आज यह एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ा है. ज़रा सोचिए, देश में लगभग 50 फ़ीसदी ज़िले आतंकवाद से प्रभावित हैं और केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को इससे निपटने में काफी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है. समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि यदि समय रहते इस पर क़ाबू नहीं पाया गया तो स्थिति काफी चिंताजनक हो सकती है.

हालांकि, कोई प्रमाणिक आंकड़ा तो नहीं है, फिर भी एक अनुमानित तौर पर आतंकवाद की वजह से 75,000 आम नागरिकों और 15,000 से भी अधिक सुरक्षा अधिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और यह आंकड़ा दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसका ताज़ा उदाहरण है, बिहार के खगड़िया ज़िले में माओवादियों के हाथ मारे गए बेक़सूर लोग. ख़ुद को इस्लामिक आतंकवादी कहने वाले ये आतंकी ही पिछले तीन वर्षों में अब तक 6000 से भी अधिक भारतीयों की जान ले चुके हैं. दरअसल, 2004 से अब तक आतंकवादी वारदातों की वजह से जितने लोग उत्तरी, दक्षिणी और मध्य अमेरिका, यूरोप और यूरेशिया में नहीं मारे गए, उससे अधिक भारत में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा.

दुर्भाग्यवश, राजनीतिक दल एनकाउंटर सहित इन सभी मुद्दों को सिर्फ़ इसलिए वोट बैंक के लिए उठाते हैं. कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, जो संवेदनशील नहीं है. ख़ासकर, अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए. और ये मुद्दे हमेशा एक पार्टी द्वारा तुष्टीकरण की नीति के तहत अपने वोट बैंक के लिए ही उठाया जाता है. जबकि आज समय की मांग है कि व्यापक राष्ट्रीय हितों के मद्देनज़र तुच्छ और संकीर्ण मानसिकता को दरकिनार करते हुए इन सारे मसलों पर व्यापक दृष्टिकोण आपनाई जाए और इस मुद्दे का पुनर्मूल्यांकन किया जाए.

भारतीय समाज सबसे बड़े पाखंडी समाजों में एक है. एक ओर, जहां लोग बाटला हाउस एनकाउंटर सहित फ़र्ज़ी मुठभेड़ों की भर्त्सना करते हैं लेकिन संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा सुनाने के बावजूद इस पर अमल नहीं होता तो इसके ख़िलाफ़ कोई अपनी आवाज़ तक नहीं उठाता. ऐसा इसलिए क्योंकि अफजल एक ख़ास संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता है और उसे फांसी पर लटकाने से उस समुदाय का वोट बैंक प्रभावित हो सकता है.

*(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)*

feedback@chauthiduniya.com



**पुलिस एनकाउंटर शब्द की उत्पत्ति भारतीय उप-महाद्वीप में ही हुई है. जिसे भारतीय पुलिस, अर्द्ध सैन्यबल, सेना और दूसरे रक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती है. वह भी इसलिए कि उसने किसी व्यक्ति की हत्या क्यों की है? पुलिस ऐसा मानती है कि उन्होंने जिसकी हत्या की है वो एक ख़ूंख़ार अपराधी, गैंगस्टर, आतंकवादी और माओवादी या नक्सलवादी हैं.**



### बड़ा अहसान है आपका

**प्रिय संपादक,**
चौथी दुनिया का नया अंक मिला. पत्र का दाम घटाकर आपने हम पाठकों पर बड़ा अहसान किया है. पहले हमारे कुछ दोस्त चौथी दुनिया का फोटोकॉपी करा कर अपने पास रखते थे. अब यह आम आदमी तक पहुंच पाएगा. आम आदमी भी इसे ख़रीद पाने में सक्षम हो सकेंगे.

***संदीप,** सागर (म.प्र.)*

### अच्छा है नया रूप

**संपादक जी,**
अख़बार का परिवर्तित रूप देखकर बेहद हर्ष हुआ. यह बात राहत पहुंचाती है कि दाम कम होने के बाद भी इसकी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है. बिहार और झारखंड अलग पेज के लिए शुभकामनाएं. उम्मीद है दूसरे राज्यों के लिए भी भविष्य में जगह बनेगी.

***सोमनाथ,** धनबाद (झारखंड)*

### आम लोगों की आवाज़

**संतोष जी,**
अब तक तो सोचता ही रहा था कि आम लोगों की आवाज़ बनकर कोई पत्र आएगा. चौथी दुनिया की शुरुआत राहत पहुंचाने वाली थी पर इसकी क़ीमत आम लोगों की पहुंच से परे थी. कम क़ीमत पर पत्र के रूप में जनता का मित्र लाने के लिए धन्यवाद.

***अजीत,** आसनसोल (पश्चिम बंगाल)*

### तोप मुक़ाबिल का कोई मुक़ाबला नहीं

**संतोष जी**
तोप मुक़ाबिल है पढ़ा. ख़र्च कटौती के नाम नेताओं का जो दिखावा हो रहा है, उस पर से पर्दा उठाने की जो बात मेरे मन में चल रही थी, कोई माध्यम न होने की वजह से अधूरी रह गई. जहां चारों ओर नेताओं के ख़र्च कटौती के दिखावे पर तो वाहवाही हो रही है, वहीं विपक्ष को दरकिनार कर दिया गया है. ऐसे में आपका लेख एक सवाल बनकर उभरा है. आख़िर विपक्ष की भी देश के प्रति ज़िम्मेदारियां बनती हैं. लोगों तक सही संदेश पहुंचाने का आपका प्रयास सराहनीय है.

***कुणाल,** बेगुसराय (बिहार)*

### नया रूप नायाब

जिन्ना पर किताब लिखने के बाद जसवंत सिंह की स्थिति वैसी हो गई है, जिसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा. उनकी किताब आने के बाद जिन्ना और जसवंत जी पर आए लेखों को मैं लगातार पढ़ता रहा हूं. दोनो पक्षों पर मेरी नई समझ विकसित हुई है. इस बार अख़बार का नया स्वरूप देखकर और भी अधिक प्रसन्नता हुई. नवीन विचार और नजरिया अब ज़्यादा लोगों तक कम क़ीमत पर पहुंच पाएगी.

***शांतनु,** रतलाम (म.प्र.)*

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं-
संपादक, चौथी दुनिया, एफ़-2, सेक्टर - 11
नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com



सौमित्र मोहन

# ख़ुद को बदलें, पर्यावरण बदलेगा

इस बात से सभी सहमत हैं कि हमारे वायुमंडल में ग्रीन-हाउस गैसों की वृद्धि ही जलवायु परिवर्तन की वजह है. और इस नीले ग्रह (पृथ्वी) पर जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही है. और यदि कोई संदेह रह गया है तो भारत में मानसून की आंखमिचौली और पूरी दुनिया में जलवायु का अनिश्चित व्यवहार इसके प्रमाण हैं.

ऐसा माना गया है कि तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से भी पूरा पारिस्थितकी तंत्र बिगड़ जाएगा. वहीं, 19वीं सदी के आरंभ से अभी तक वैश्विक तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पहले ही हो चुकी है. इंटर-गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) का मानना है कि 2050 ईस्वी तक वैश्विक तापमान में 0.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस के बीच वृद्धि होगी, जबकि 2100 ईस्वी तक यह अनुमानित वृद्धि 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस के बीच हो जाएगी. ऐसा कहा गया है कि हर साल लगभग 10 बिलियन मिट्रिक टन कार्बन हमारे वायुमंडल में छोड़े जा रहे हैं.

इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में लगभग 1.1 और 2.9 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ोतरी होगी. आईपीसीसी का आकलन है कि 2100 ईस्वी तक समुद्र के जल स्तर में 23 इंच तक की बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि समुद्र के जल स्तर में एक इंच की वृद्धि लगभग एक मिलियन लोगों के विस्थापन की वजह बन रही है. मानव जाति के सामने आने वाले तबाही को देखते हुए, राहत और पुनर्वास कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार करने की ज़रूरत है. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) का भी मानना है कि आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए शरणार्थी संबंधी मुद्दों को जल्द हल करने की ज़रूरत है.

**जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव ग़रीब और समाज के सबसे निचले तबके पर पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि इनके हाथों में बहुत ही सीमित क्षमता, योग्यता और स्रोत हैं. इसलिए समाज के इन वर्गों के जीविकोपार्जन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की ज़रूरत है. जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या में नगण्य योगदान के बावजूद सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वालों में यही लोग होंगे.**

जलवायु परिवर्तन की वजह से कृषि पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ रहा है. जिससे पैदावार में कमी के कारण खाद्य संकट की समस्या भी उत्पन्न हो रही है. नतीजतन, दुनिया के 6.75 बिलियन लोगों को खाद्य सुरक्षा की गंभीर समस्याओं से दो-चार होना पड़ सकता है. अनियमित वर्षा की वजह से हम पानी की कमी की समस्या से भी जूझ रहे हैं. बारिश का अधिकांश पानी यूं ही अधिक बहाव की वजह से बर्बाद हो जाता है और जंगलों की कमी की वजह से ज़मीन में पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे सूखे की समस्या झेलनी पड़ती है. समुद्र के जल-स्तर मे वृद्धि से न सिर्फ़ कृषि प्रभावित होगी बल्कि मीठे पानी में समुद्र के खारे पानी के मिश्रण से पानी की विकट समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी. इसलिए, पानी प्रबंधन नीति की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. वाटरशेड विकास पर भी ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है.

जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव ग़रीब और समाज के सबसे निचले तबके पर पड़ेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि इनके हाथों में बहुत ही सीमित क्षमता, योग्यता और स्रोत हैं. इसलिए समाज के इन वर्गों के जीविकोपार्जन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की ज़रूरत है. जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या में नगण्य योगदान के बावजूद सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वालों में यही लोग होंगे.

बेहतर स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित पेय जल, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के साथ-साथ दूसरी अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों में शामिल हैं, जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है. स्वस्थ और बेहतर शिक्षित मानव संसाधन ही आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता है. चतुर्दिक विकास ही इन सभी समस्याओं को जड़ से दूर करने का सबसे बेहतर उपाय है. मशहूर समाज विज्ञानी जॉन रॉल्स बिल्कुल सही कहते हैं कि न्याय का मतलब ही होता है, कल्याण के दायरे में सभी व्यक्तियों का शामिल होना. दुनिया की सभी सरकारों को यह तय करना चाहिए कि इन परिस्थितयों से निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाए.

लेकिन, इसमें ही सभी समस्याओं का सार निहित है. फिर भी, हक़ीक़त यह है कि इनसे निपटने के लिए यूनाइटेड नेशनस फ्रेमवर्क कंवेंशन में विकसित और विकासशील देशों के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद सभी देश किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं. भारत सहित कई विकासशील देशों का मानना है कि इन समस्याओं के लिए विकसित देश ज़िम्मेदार हैं, इसलिए उन्हें सबसे अधिक ज़िम्मेदारी साझा करनी चाहिए.

आज भी, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन चीन से चार गुना और भारत से 20 गुना ज़्यादा है. हालांकि, 2006 में चीन ख़ुद कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है. भारत ने विकसित देशों को प्रस्तावित किया है कि उन्हें अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.5 फ़ीसदी (1960 में साउथ कमीशन द्वारा प्रस्तावित 0.7 फ़ीसदी से भी कम) हिस्सा अनुकूलन कोष (जैसे, ग्रीन मार्शल प्लान) में देना चाहिए, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से निपटा जा सके. ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर लगाम लगाने के लिए न सिर्फ़ उपभोक्तावाद पर ध्यान देने की ज़रूरत है बल्कि पूरी दुनिया में उत्पादन और खपत की बढ़ रही ज़रूरतों को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है. निजी वाहनों की तादाद कम करने के लिए ईंधन और गाड़ियों पर अधिक टैक्स लगाने की सिफ़ारिश भी की गई है.



इसके अलावा, हमें अपनी प्रकृति को नुक़सान से बचाने के लिए और इसे वापस हरा-भरा बनाने के लिए और भी कई क़दम उठाने की जरूरत है. इसलिए, इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर वनीकरण की आवश्यकता है. यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कंवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत क्लीन डेवलपमेंट मेकनिज़्म (सीडीएम) और एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम भी लागू करने की आवश्यकता है. सीडीएम का मतलब है कि धनी देशों के फर्म और संस्थाओं को यह प्रस्तावित किया गया है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए विकासशील देश की परियोजनाओं को आर्थिक मदद की जाए. और एमिशन ट्रेडिंग से तात्पर्य है, जो देश तयशुदा उत्सर्जन सीमा से अधिक उत्सर्जन करेंगे, वे कम कार्बन उत्सर्जन वाले देश को वित्तीय सहायता देकर ऐसा कर सकते हैं.

हमें अनियमित मानसून की समस्याओं से निपटने के लिए अपनी सिंचाई की क्षमता को और भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है. हालांकि, खाद्य सुरक्षा के लिहाज़ से नदियों को जोड़ने की प्रस्तावित परियोजना को अभी काफी लंबा सफ़र तय करना है, पर यह कम ख़र्चीला और वैज्ञानिक रूप से व्यवहारिक भी है. इसमें संबंधित अनुसंधान और विकास तथा कृषि सुविधाओं के विस्तार के लिए विचार पर ज़ोर देने की ज़रूरत है.

पश्चिमी देशों से पूर्व के देशों को तकनीक का हस्तांतरण कई समस्याओं को हल कर सकता है. कोयले से गैस बनाने, कार्बन पर नियंत्रण रखने, कम कार्बन वाले ईंधन की खोज और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों के विकास से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपटा जा सकता है. साथ ही, हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश और इस्तेमाल करनी चाहिए. इस उद्देश्य के लिए अनुसंधान और विकास के लिए व्यापक स्तर पर निवेश की ज़रूरत है.

*(लेखक प. बंगाल में आईएएस अधिकारी हैं. आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं और इनका सरकार के विचारों से कोई संबंध नहीं है.)*

feedback@chauthiduniya.com

अगर आप सोचते हैं कि महिलाओं की नींद पुरुषों की तुलना में ज़्यादा खराब होती है, तो अपना भ्रम दूर कर लीजिए. वे खूब जमकर सोती हैं.



## ख़ुफ़िया एजेंसियों के सीक्रेट

# मोसाद के मिशन म्यूनिख की दास्तां

वक़्त- सुबह के क़रीब साढ़े चार बजे. तारीख़- 5 सितंबर 1972 और जगह म्यूनिख ओलंपिक खेल का मैदान. यह इतिहास की अब तक की सबसे बर्बर और ख़ौफ़नाक साज़िश थी, जिसे सबकी नज़रों के सामने अंजाम दिया गया. इस काले दिन के गवाह कई लोग थे. सभी ने दिल दहला देने वाले इस नापाक मिशन को अपने अंजाम तक पहुंचते देखा. सरेआम! अपनी आंखों के सामने!! लेकिन, यह शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कोई खिलाड़ी अब तक के सबसे बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देगा. वे सही भी थे और ग़लत भी. दरअसल, आतंकी बहुरूपिया निकले. अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उन्होंने खिलाड़ियों की पोशाक पहन रखी थी, ताकि कोई उन पर शक़ न कर सके. हुआ भी कुछ ऐसा ही. एक-एक कर पांच अरबी आतंकी, जिन्होंने खिलाड़ियों वाला ट्रैक सूट पहन रखा था, ओलंपिक खेल गांव की छह फुट और छह इंच लंबी दीवार फांद रहे थे. वहां पहले से मौजूद उनके तीन और साथी उनका इंतज़ार कर रहे थे. यह सब हुआ, वह भी लोगों के सामने सरेआम. किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि दीवार फांदने वाले खिलाड़ी नहीं, बल्कि खेलों के खलनायक हैं, जिनका मक़सद था ख़ूनी खेल खेलना.

म्यूनिख जर्मनी के सबसे बड़े शहरों में एक है और बात 1972 के म्यूनिख ओलंपिक की ही है. जब खेल शुरू हुआ तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि म्यूनिख ओलंपिक अपनी भव्यता की वजह से कम, आतंकियों के काले कारनामों की वजह से ज़्यादा चर्चित होगा. शायद इतिहास भी अपने इस काले अध्याय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था. मानो, सब कुछ तय था. मौत के सारे साजो-सामान ओलंपिक खेल मैदान तक पहुंच चुके थे. जब तक आतंकियों ने क़हर नहीं बरपा दिया, किसी को उनकी साज़िश की भनक तक नहीं लग सकी. इन फिलिस्तीनी आतंकियों ने अपने हथियार एथलीट बैग में छुपा रखे थे, ताकि कोई उन पर शक़ न कर सके. लेकिन, एथलीट बैग में छुपाकर रखे गए हथियारों के निशाने पर वाक़ई में एथलीट ही थे. इनका मक़सद था, अपने सबसे बड़े दुश्मन देश के खिलाड़ियों को मौत की नींद सुलाना. जी हां, इनके निशाने पर थे इज़रायल के ओलंपिक खिलाड़ी. कहते हैं कि खिलाड़ी और खेल दो देशों के बीच संबंधों की बुनियाद मज़बूत करते हैं. लेकिन, इन फिलिस्तीनी आतंकियों के लिए ऐसी किसी भी मान्यता का कोई महत्व नहीं था.

इन आतंकियों ने अपने काले कारनामे की शुरुआत बिल्कुल पूर्व नियोजित साज़िश के तहत की. सबसे पहले छह फुट और छह इंच की विशाल दीवार फांदकर पांच फिलिस्तीनी आतंकियों ने ओलंपिक खेल गांव में अपने नापाक क़दम रखे. कुल आठ आतंकी अब तक खेल गांव पहुंच चुके थे. उसके बाद इनका सबसे पहला मक़सद था इज़रायली टीम के अपार्टमेंट की चाबियां चुराना, जिससे उन्हें खिलाड़ियों तक बेहद आसानी से पहुंचने में मदद मिलती. आतंकी अपने इस मक़सद को अंजाम देने के बाद उस होटल में पहुंचे, जहां इज़रायली खिलाड़ी बेफ़िक्री से आराम फरमा रहे थे. तभी इज़रायली रेसलिंग टीम के रेफरी को दरवाज़े के पास चरचराहट जैसी कोई आवाज़ सुनाई दी. जब रेफरी ने इसकी तहक़ीकात की तो देखा कि कुछ नक़ाबपोश बंदूक़धारी दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे हैं. रेफरी चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? भागो यहां से. साथ ही उसने उनकी ओर 135 किलो का वजन भी फेंका, ताकि उन फिलीस्तीनी आतंकियों को कमरे में आने से रोका जा सके. इस अफरातफरी में रेसलिंग टीम के छह खिलाड़ी भाग गए, जबकि टीम के साथ आए दो डॉक्टर और चार दूसरे खिलाड़ी छुप गए. लेकिन, रेसलिंग कोच मोश वीनबग खाली हाथ ही हथियारों से लैस उन आतंकियों पर टूट पड़े और उनकी गोली का शिकार होने से पहले एक आतंकी को बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया. इसके बावजूद आतंकी नौ इज़रायली खिलाड़ियों को बंधक बनाने में सफल हो गए.

इज़रायल के ओलंपिक खिलाड़ी, जो आतंकियों के निशाने पर थे.

ब्लैक सेप्टेंबर के आतंकी.

सुबह नौ बजे इन आतंकियों ने घोषणा की कि वे इन खिलाड़ियों की जान की क़ीमत के बदले चाहते हैं कि इज़रायल उनके 200 फिलीस्तीनी साथियों को आज़ाद कर दे. साथ ही, जर्मनी से सुरक्षित जाने का रास्ता दिया जाए, ताकि ब्लैक सेप्टेंबर के ये आतंकी अपनी निर्धारित योजना के मुताबिक़ मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंच सकें. जर्मन सरकार ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया. उन्हें इज़रायली खिलाड़ियों के साथ एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए नाटो एयरबेस पहुंचाया गया, ताकि वहां से इन्हें काहिरा पहुंचाया जा सके.

लेकिन, इस दौरान जर्मन अधिकारियों ने देखा कि आठ आतंकियों की जगह ब्लैक सेप्टेंबर के कुल पांच आतंकी ही हैं. फिर क्या था, जर्मन अधिकारियों ने उन आतंकियों को एयरबेस पर ही मार गिराने के लिए अपने शार्प शूटर लगा दिए. जब आतंकी एयरबेस पहुंचे तो शार्प शूटरों ने उन्हें अपने निशाने पर लेना शुरू कर दिया. कुछ देर बाद मीडिया ने सूचना दी कि सभी आतंकियों को मार गिराया गया है और इज़रायली खिलाड़ी सुरक्षित हैं. तभी लगभग एक घंटे बाद जिस हेलीकॉप्टर में खिलाड़ी थे, उसमें एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और सभी नौ इज़रायली खिलाड़ी काल के गाल में समा गए. यह कारनामा था जर्मन शार्प शूटरों की नज़रों से बचे उन तीन आतंकियों का, जिन्हें ढूंढ निकालने में जर्मन अधिकारी भी नाकामयाब रहे. हालांकि, बाद में ब्लैक सेप्टेंबर के इन तीनों आतंकियों को पकड़ लिया गया.

मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ. अपने खिलाड़ियों की मौत के मातम में डूबे इज़रायलियों पर अभी एक और क़हर टूटने वाला था, उसी साल यानी 1972 में ही और इस बार तारीख़ थी 29 अक्टूबर. फिलीस्तीनी आतंकियों ने एक जेट एयरवेज हाईजैक कर लिया. इस बार उनकी मांग थी कि म्यूनिख ओलंपिक के दौरान पकड़े गए आतंकियों को छोड़ दिया जाए. जर्मन अधिकारियों ने अपनी पिछली नाकामयाबी से सीख लेते हुए उन आतंकियों को छोड़ने और उन्हें सुरक्षित निकलने देने की शर्त मान ली.

लेकिन, अपने नौ खिलाड़ियों की मौत से तिलमिलाई इज़रायली ख़ुफ़िया एजेंसी मोसाद ने इस पर सख्त एतराज़ जताया और इस पूरे मिशन की ज़िम्मेदारी ख़ुद ले ली. फिर, मोसाद ने इस बहुचर्चित और विवादित मिशन म्यूनिख को बख़ूबी दिया अंजाम. कैसे? जानिए अगले अंक में.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

## ज़रा हट के

# चैन से सोती हैं महिलाएं

अगर आप अभी तक यह सोचते आ रहे हैं कि महिलाओं की नींद पुरुषों की तुलना में ज़्यादा खराब होती होती है तो ज़रा एक बार फिर से सोचिए. एक शोध के मुताबिक़, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अच्छी नींद ले पाती हैं और उन्हें पुरुषों से अधिक नींद आती है. बुज़ुर्ग महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि उनकी नींद की अवधि कम समय की होती है और पुरुषों की अपेक्षा उन्हें नींद भी अच्छी नहीं आती है. लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि नए शोध के अनुसार महिलाओं को अधिक नींद की ज़रूरत होती है.

स्लीप पत्रिका में छपे इस शोध को इरासमस मेडिकल सेंटर ने किया है. नीदरलैंड के शोधकर्ताओं के मुताबिक़, जितनी नींद पुरुषों के लिए पर्याप्त होती है, ज़रूरी नहीं है कि महिलाओं पर भी लागू हो. नींद विशेषज्ञ नील स्टान्ले के अनुसार, अमूमन लोग मानते हैं कि महिलाओं की नींद पुरुषों की नींद से खराब होती है. जबकि शोध बताता है कि महिलाएं नहीं, पुरुषों की नींद अपेक्षाकृत खराब होती है. शोध में 59 से लेकर 79 वर्ष की उम्र के 56 लोगों ने भाग लिया. नतीजा निकला कि महिलाएं पुरुषों से औसतन 16 मिनट अधिक सोती हैं और उनकी नींद भी कम टूटती है. रिसर्च ग्रुप के प्रमुख डा हेमिंग तिनियर कहते हैं कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर और अधिक समय तक सोती हैं.

शोध में शामिल होने वाले लोगों की नींद को एक्टीग्राफ की मदद से मापा गया. घड़ी की तरह काम करने वाला एक्टीग्राफ औसतन 6 दिन की नींद मापता है. शोध में पाया गया कि पुरुष सोचते थे कि वे रात में औसतन क़रीब 7 घंटे सोते हैं, जबकि वे 6 घंटे 40 मिनट ही सोए थे. वहीं महिलाओं का मानना था कि वे 6.79 घंटे सोईं, जबकि वे औसतन 6.55 घंटे सोई थीं. इसके अलावा एक और बात पाई गई कि महिलाएं सोने के लिए दवाओं का प्रयोग पुरुषों से ज़्यादा करती हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि वे कम सो पाती हैं.

# नए प्रोटीन की पहचान

न्यूजर्सी के यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेनडीस्ट्री के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे प्रोटीन की पहचान की है, जो अल्जाइमर के मरीजों के मस्तिष्क में हुई गड़बड़ी को ठीक कर सकता है.

वैज्ञानिकों के अनुसार, इस प्रोटीन को सामान्य तौर पर विमेटिन कहते हैं. यह पूरे जीवन में दो बार निकलता है. जीवन के पहले वर्ष में जब न्यूरोन्स दिमाग़ में आकार लेते हैं और दूसरी बार तब, जबकि दिमाग़ के न्यूरोन्स अल्जाइमर की गिरफ्त में होते हैं या अन्य दिमागी बीमारी से ग्रसित होते हैं. यूएमडीएनजे के प्रोफेसर एवं लेखक राबर्ट नागेले के अनुसार, विमेटिन को न्यूरोन्स के तौर पर व्यक्त किया गया है. एक बात गौर करने वाली है कि जहां अल्जाइमर क्षति होती है, यह विटामिन उसी के आसपास रहता है.

प्रोफेसर नागेले कहते हैं कि जब तक रोगी उपचार के लिए क्लीनिक या अस्पताल तक पहुंचता है, तब तक न्यूरोन्स उस बिंदु पर पहुंच चुके होते है, जहां वे बढ़ते हुए अल्जाइमर द्वारा हुई क्षति के साथ गति बनाए रखने में सक्षम नहीं रह पाते हैं. अध्ययन के निष्कर्ष को देखते हुए नागेले ने न्यूरोन्स की तुलना एक विशाल वृक्ष से की है, जिसे डेनडरीट्स कहते हैं.

डेनडरीट की शाखाएं दस हजार छोटे छोटे पत्तों से ढकी होती हैं, जिसे स्नेपसेस कहते हैं, जो न्यूरोन्स को एक दूसरे से संपर्क बनाने की आज़ादी देता है. डेनडरीट शाखाओं के बनने में विटामिन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जो स्नेपसेस की मदद करता है.

प्रोफेसर नागेले के मुताबिक, अल्जाइमर की पहचान अमॉलायड के इकट्ठा होने पर होती है, जो धीरे धीरे स्नेपसेस को नष्ट कर देता है और यही स्थिति डेनडरीट शाखाओं के पतन का भी कारण बनती है.

जब डेनडरीट्स और स्नेपसेस विकृत हो जाता है, तब न्यूरोन विटामिन छोड़ता है, ताकि डेनडरीट पेड़ की शाखाएं और स्नेपसेस एक फिर से निकल आएं. यह एक अविकसित प्रक्रिया है, जो मस्तिष्क को जीवन के शुरुआती वर्षों में विकसित करने के लिए स्वीकृति देता है.

शोधकर्ताओं ने कुछ शुरुआती तथ्यों के बारे में भी स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस तरह का नुक़सान मस्तिष्क में चोट लगने के कारण भी होता है.

उन्होंने यह संभावना व्यक्त की कि इस तरह की थेरेपी को मस्तिष्क आघात और दिमागी बीमारी ठीक करने के लिए विकसित किया जा सकता है. यह शोध ब्रेन रिसर्च जरनल में प्रकाशित हो चुका है.

# डायनासोर के अंडे मिले

भारतीय वैज्ञानिकों को तमिलनाडु की एक नदी के किनारे खुदाई के दौरान डायनासोर के सैकड़ों अंडे मिले हैं. लगभग साढ़े छह करोड़ साल पुराने उक्त अंडे वैज्ञानिकों को संयोगवश तब मिले, जब वे नदी के किनारे प्राचीन धरोहरों की तलाश में खुदाई कर रहे थे.

जीवाश्म बन चुके इन अंडों के नमूने दुनिया भर के विशेषज्ञों के पास भेजे गए. विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि ये अंडे डायनासोर के ही हैं. इनका आकार फुटबॉल जितना बड़ा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि मादा डायनासोर ने इन अंडों को रेत में दबा दिया होगा. वैज्ञानिक दल के प्रमुख डॉक्टर एमयू राजकुमार का कहना है कि इस अहम खोज से डायनासोर के लुप्त होने के कारणों का पता चल सकता है.

उनके मुताबिक़, हमें अंडों के ऊपर ज्वालामुखी की राख की परतें मिली हैं. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ज्वालामुखी विस्फोट ही डायनासोर के लुप्त होने की वजह रही होगी. अहम बात यह है कि अंडे कई परतों में मिले हैं, जिससे लगता है कि डायनासोर यहां हर साल आते रहे होंगे. वैज्ञानिकों के मुताबिक, प्राप्त अंडों के भ्रूण मृत हैं. अंडों में डायनासोर पैदा करने की क्षमता क्यों नहीं थी, इस बात की जानकारी पूर्ण अध्ययन के बाद ही पता चल सकेगी.

इसके अलावा वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उक्त अंडे किसी शांत स्वभाव वाले शाकाहारी डायनासोर के हैं. यह प्रजाति दुनिया के लगभग हर कोने में पाई जाती है. गौरतलब है कि इसी क्षेत्र में 1860 में ब्रितानी वैज्ञानिकों को भी डायनासोर के अंडे मिले थे. इसके अलावा 1990 के दशक में भी तमिलनाडु में डायनासोर के अंडे मिल चुके हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

इसके पहले अंक में अब तक आपने पढ़ा कि पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब का इलाक़ा किस तरह आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है.



# भारत को मिली नई चुनौती

नीनन कोशी

भारत सरकार की 1998 में न्यूक्लियर परीक्षण के बाद हुई किरकिरी की बात अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि एक और न्यूक्लियर विवाद ने नई दिल्ली में बैठी यूपीए सरकार को झकझोर दिया है. यह विवाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 1887 से उठा है. इस प्रस्ताव के मुताबिक़, जो देश पमाणु अप्रसार संधि के पक्ष में नहीं हैं वे इस संधि में केवल एक ग़ैर-परमाणु हथियार राज्य के दर्ज़े से ही शामिल हो सकते हैं. सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव को एक विशेष सत्र में पारित किया, जिसमें सभी देशों के प्रमुख शामिल हुए. आपको बता दें, सुरक्षा परिषद का ऐसा सत्र अब तक महज़ चार दफ़ा बुलाया गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने इस सत्र की अध्यक्षता की.

इस प्रस्ताव के पारित होने पर भारत ने अपने जवाब में कहा कि वह इस संधि में एक ग़ैर-न्यूक्लियर हथियार राज्य के दर्ज़े से शामिल नहीं होगा. न्यूक्लियर हथियार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है और हमेशा रहेगा. इस जवाब के बावजूद यूपीए सरकार यह बात अच्छी तरह समझ रही है कि यह प्रस्ताव उसके न्यूक्लियर दर्ज़े पर सवाल खड़ा कर रहा है. यह प्रस्ताव अमेरिका के साथ हुई परमाणु संधि और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों पर भी सवाल खड़ा करता है. भारत के ऊपर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ज़रिए न्यूक्लियर अप्रसार संधि को स्वीकार करने के लिए दो जगहों से दबाव भी डलवाने की कोशिश की. पहला न्यूक्लियर अप्रसार संधि में परिवर्तन के लिए बनी कमेटी और दूसरा जी-8 देशों के सम्मेलन के माध्यम से. 7 मई, 2009 को इस कमेटी में एक अमेरिकी अधिकारी रोज़ गोटेमोइलर ने कहा, अमेरिका चाहता है कि भारत भी इज़राइल, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया के साथ परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार ले. इस बयान से साफ़ ज़ाहिर है कि भारत के नाभकीय दर्ज़े को लेकर एक बार फिर अमेरिका की नीति में बदलाव लाने की कवायद हो रही है. भारतीय अधिकारियों को इस बात की उम्मीद थी कि राष्ट्रपति बराक की अप्रसार नीतियों के चलते अमेरिका उस पर सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल सकता है, लेकिन न्यूक्लियर अप्रसार पर सख्त होते अमेरिकी रुख़ ने उन्हें चकित कर दिया है. इस समिति में दिए गए अमेरिकी बयान से ठीक दो दिन पहले भारत में अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट ब्लैकविल ने कहा, दोनों देशों को अपने मौजूदा संबंधों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत और प्रखर कूटनीति की ज़रूरत होगी. यह बयान ब्लैकविल ने चैंबर ऑफ इंडियन इंड्रस्टीज़ के एक कार्यक्रम के दौरान दिया. ब्लैकविल ने यह भी कहा कि एक सफल कूटनीति के अलावा द्विपक्षीय संबंध इस बात पर निर्भर करेंगे कि राष्ट्रपति बराक ओबामा भारतीय न्यूक्लियर हथियारों को दक्षिण एशिया के लिए ख़तरा मानते हैं या नहीं. इस बयान से यह बात साफ़ है कि अमेरिका भारत के न्यूक्लियर दर्ज़े को लेकर अपनी नीति पर पुनर्विचार कर रहा है. अमेरिका का यह रुख़ पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की भारत नीति के विरुद्ध है. बुश ने कभी भी भारत से अप्रसार संधि को स्वीकार करने की बात नहीं कही थी. इसके साथ ही इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के साथ बातचीत के दौरान अमेरिका भारत को एक ख़ास तरह के न्यूक्लियर देश का दर्ज़ा देने की बात मानने के पक्ष में लग रहा था. लेकिन हाइड एक्ट जो भारत और अमेरिका के बीच हुए न्यूक्लियर समझौते को संचालित करता है, न्यूक्लियर अप्रसार संधि की बात करता है. हाइड एक्ट के मुताबिक़, भारत एनपीटी के बाहर रहकर वैश्विक अप्रसार के लिए एक राजनीतिक चुनौती है. यहां पर भारत के न्यूक्लियर दर्ज़े के मामले में अमेरिकी नीति में बदलाव साफ़ ज़ाहिर है और भारत-अमेरिका न्यूक्लियर समझौते के प्रति ओबामा सरकार का संकल्प डगमगा रहा है.

इसके अलावा जी-8 देशों की जुलाई में हुई बैठक के दौरान भी अमेरिका ने एनपीटी से असहमति जताने वाले देशों से एनपीटी में शामिल होने के लिए दबाव डाला था. इस दौरान उसने भारत, पाकिस्तान, इज़रायल और उत्तरी कोरिया को नाम सहित एनपीटी में शामिल होने की बात कही थी. इस बैठक के दौरान भी अमेरिका ने भारत को न्यूक्लियर क्षेत्र में किसी विशेष दर्ज़े की बात नकार दी.

दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा परमाणु अप्रसार के सामने आने वाले रोड़ों को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं, ताकि वह 2010 में एनपीटी कान्फ्रेंस को सफल बना सकें और दुनिया भर के देशों को एनपीटी के अधीन कर सकें. 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने ख़ुद को एक परमाणु हथियार शक्ति संपन्न देश साबित करते हुए एक ज़िम्मेदार नाभिकीय शक्ति संपन्न देश के तौर पर एनपीटी में शामिल होने की कोशिश की. एनपीटी की शर्तों के मुताबिक़ भारत को बतौर ग़ैर न्यूक्लियर हथियार देश ही शामिल किया जा सकता है.

यहां एक बात ग़ौर करने वाली है कि भारत का शुरू से ही कहना रहा है कि एनपीटी एक पक्षपातपूर्ण संधि है. भारत उन पहले देशों में से है जो परमाणु अप्रसार के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि की मांग कर रहा है. लेकिन जैसे ही यह साबित हुआ कि परमाणु अप्रसार के ज़रिए परमाणु हथियारों वाले देश यह शक्ति महज़ अपने तक सीमित रखने की फिराक में हैं, ताकि इसकी मदद से वे दूसरे देशों को यह दर्ज़ा हासिल करने से रोक सकें और ख़ुद परमाणु हथियारों के भंडार में वृद्धि करते रहें, भारत ने इस संधि को स्वीकारने से मना कर दिया.

इस संधि पर पक्षपात का आरोप अब ज़्यादा मायने नहीं रखता है. भारत ने बुश प्रशासन के दौरान सभी शर्तों को मानते हुए एक न्यूक्लियर क्लब में एक दूसरे दर्ज़े की सदस्यता पा ली थी. अब समस्या यह है कि बराक ओबामा इस नई शर्त को जोड़ना चाहते हैं. कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि ओबामा न्यूक्लियर क्लब में भारत को दूसरे दर्ज़े की भी सदस्यता नहीं देना चाहते हैं. एनपीटी को वैश्विक बनाने की अमेरिका की कोशिश एनपीटी में निहित विवाद का ही नतीजा है. एनपीटी का यह विवाद कोई नया नहीं है. पिछले चालीस सालों में यह साफ़ हो चुका है कि न्यूक्लियर हथियारों से संपन्न देशों ने वैश्विक स्तर पर परमाणु रहित दुनिया बनाने की कवायद को नामंजूर किया है. जबकि, वैश्विक निशस्त्रीकरण एनपीटी का एक प्रमुख अंग है. इसके बावजूद परमाणु हथियारों से संपन्न देशों ने इस संधि की आड़ में अपने परमाणु मिसाइल के जखीरों में जमकर वृद्धि की है. एनपीटी का 1995 में स्थाई और अनिश्चित विस्तार करके इसे एक तरह के व्यवस्थित तंत्र के तौर पर स्थापित कर दिया गया है. इसके ज़रिए न्यूक्लियर क्लब में किसी नए सदस्य को न घुसने देने की कोशिश की जा रही है. यह संधि के मूल तत्व के ख़िलाफ़ है. भारत एनपीटी के इसी स्वरूप का विरोध करता है और इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ पक्षपात मानता है. एनपीटी में सुधार के लिए बनी कमेटी विफल हो चुकी है. आज इन गोष्ठियों और ऐसी कमेटियों पर सवालिया निशान लग रहा है. आज ओबामा को अपना लक्ष्य पाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वे एनपीटी के मूल स्वरूप को बचाने की कोशिश करें, ताकि न्यूक्लियर अप्रसार और परमाणु रहित विश्व के उनके लक्ष्य को पाया जा सके. लेकिन, सभी देशों को एनपीटी के अधीन लाने की अमेरिकी नीति के चलते ओबामा मान रहे हैं कि भारत को किसी तरह का विशेष दर्ज़ा दिए जाने की आवश्यकता नहीं है.

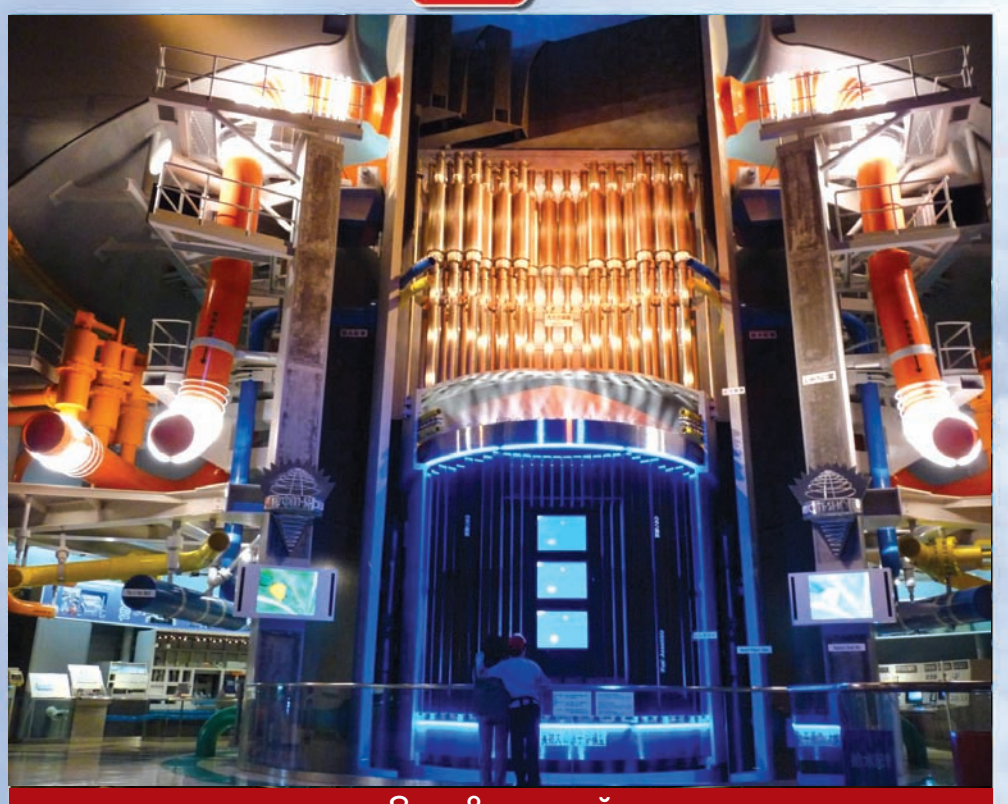

न्यूक्लियर रिएक्टर का मॉडल

*कैंब्रिज स्थित हार्वर्ड लॉ स्कूल के पूर्व प्रोफेसर नीनन कोशी राजनीतिक टीकाकार हैं.*

feedback@chauthiduniya.com

# पाकिस्तान के पांच भ्रम

आयशा सिद्दीका

*इसके पहले अंक में आपने पढ़ा कि पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब का इलाक़ा किस तरह आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है. वहां कैसे लोगों को गुमराह कर आतंकी बनाने की मुहिम-सी चल रही है. इसके बावजूद, कुछ लोग इसे ख़तरे की कोई वजह नहीं मानते. आख़िर क्यों? जानते हैं, पाकिस्तानी लेखिका आयशा सिद्दिका के इस लेख में गतांक से आगे...*

पाकिस्तानी मीडिया में द न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार द्वारा दक्षिण पंजाब की समस्याओं पर लेख की वजह से काफी बवाल मचा. इन पर बहावलपुर के रीजनल पुलिस अधिकारी (आरपीओ) मुश्ताक़ सुखेरा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दक्षिण पंजाब में तालिबानीकरण जैसा कोई ख़तरा नहीं है और ऐसी कोई भी रिपोर्ट पश्चिमी मीडिया की कोरी कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है. बहावलपुर आरपीओ के इस बयान पर कई लोगों ने अपनी सहमति जताई. इसकी पांच वजहें हैं. सबसे पहली बात यह कि नीतियां और विचारधारा तय करने वाले, इस समस्या की गंभीरता के बनिस्बत नकारात्मक रुख़ अख्तियार किए हुए हैं. लोग यह भी सोचते हैं कि पाकिस्तान की मुख्यधारा से जुड़े इस इलाक़े में, ज़्यादा ज़ोर देने का मतलब अमेरिकी दख़ल के लिए बहाने तलाशना भर है. यही वजह है कि इन जगहों पर आतंकी गतिविधियों से जुड़े सबूत इकट्ठा करना काफी मुश्किल है. सुखेरा और उनके जैसे कई अधिकारियों को चिंता की कोई बात इसलिए भी नज़र नहीं आती है क्योंकि ये सारे संगठन यहीं की उपज हैं और प्रत्यक्ष तौर पर अफ़ग़ानिस्तान में युद्ध से जुड़े नहीं दिखते हैं. तीसरी वजह यह कि, जब ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में इस्लामीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो आईएसआई ने कई ऐसे संगठनों को खड़ा किया जो जिहाद की लड़ाई में उनकी मदद कर सकें. साथ ही, इन संगठनों को तैयार करने का एक मक़सद यह भी था कि इसके ज़रिए एक तीर से दो-दो शिकार किए जाएं. एक तरफ़ शिया समुदाय को निशाना बनाकर इरान के ख़िलाफ़ सउदी अरब की मदद की जाए और बाद में कश्मीर में छद्म युद्ध को भी अंजाम दिया जा सके. तब इन अधिकारियों को इस बात का कतई इल्म नहीं रहा होगा कि ये संगठन बेलगाम भी हो जाएंगे. लेकिन, जिन्होंने भी ऐसी हिमाकत की उन्हें नेस्तनाबूत करने में भी पाकिस्तानी रहनुमाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ा. अल-फुरक़न को ही लें. यह संगठन जैश-ए-मोहम्मद से अलग होकर बना था और मुशर्रफ की हत्या की साज़िश में इसका हाथ बताया गया. संपत्ति, ताक़त और विचारधारा में मतभेद होने की वजह से यह संगठन जैश-ए-मोहम्मद से लग हुआ था. इसीलिए, सुरक्षा एजेंसियों ने बहावलपुर में मई 2009 में अल-फुरक़न के ज़िला प्रमुख को मार गिराने में कोई कोताही नहीं बरती. जहां तक जैश-ए-मोहम्मद का सवाल है, यह सत्ता के साथ हमेशा क़दमताल करता रहा. किसी भी हालात में, कोई भी संगठन जो भारत विरोधी और कश्मीर से जुड़े थे, वह अभी भी जीवित हैं. यही सोच लश्कर-ए-तैयबा की है. लेकिन वास्तविक तौर पर, कई वहाबी संगठन दूसरे इलाक़ों मसलन, अफ़ग़ानी प्रांत कुनर और बड़खशान में 2004 से ही सक्रिय हैं. चौथी वजह, तालिबानीकरण के संदर्भ में कार्रवाई के स्तर पर सरकार में दुविधा की स्थिति है. पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है वह तालिबानीकरण भले न हो, लेकिन घातक उससे कहीं ज़्यादा है.

आख़िर में, बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्लाम के सूफी मत के प्रभाव की वजह से इस क्षेत्र का तालिबानीकरण नहीं हो सकता. बहावलपुर आरपीओ के अलावा कई ऐसे शख्स हैं, जो इन सिद्धांतों से पूरी तरह सहमत नज़र आते हैं. फिर भी, तालिबानीकरण को मदद पहुंचाने वाली वजहों मसलन, ग़रीबी, ग़ैर-तरक़्क़ी और घटिया सरकार से सूफी इस्लाम मुक़ाबला नहीं कर सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

मधुमेह जानलेवा भी हो सकता है. यह हमारे जीवन शैली से जुड़ा है, इसलिए ज़िंदगी जीने के तौर-तरीकों में बदलाव से हम इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं.

# महामारी है मधुमेह

**एक अनुमान के मुताबिक़ इस समय दुनिया भर में 24 करोड़ 60 लाख लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और 2025 तक इस संख्या के 38 करोड़ हो जाने की आशंका है. दुख की बात यह है कि देश में मधुमेह के कुल रोगियों में 14 से 18 प्रतिशत युवा शामिल हैं.**

रीतिका सोनाली

मधुमेह मेटाबोलिक डिज़ऑर्डर है, जो शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाने, या फिर शरीर में मौजूद इंसुलिन के ठीक से काम नहीं कर पाने की वजह से होता है. इस स्थिति में शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है. यह ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मीठा खाने वाले लोगों को ही यह बीमारी हो, यह वंशानुगत भी होती है. रिपोर्टों के अनुसार, हर दस सेकेंड में दुनिया भर में मधुमेह से एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और उन्हीं दस सेकेंड में दो और लोगों में इसके लक्षण पैदा हो जाते हैं. दिल्ली डायबिटीज़ रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉ. ए के झिंगन के मुताबिक़, लक्षणों के आधार पर मधुमेह के दो प्रकार हैं. ज़्यादातर केस में मधुमेह 1 और मधुमेह 2 के लक्षण एक जैसे होते हैं और इस वजह से इनकी पहचान करने में काफी वक़्त लग जाता है.

### मधुमेह 1

यह इंसुलिन आधारित होता है, जो ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है. इस स्थिति में किसी इंफेक्शन की वजह से या वंशानुगत तौर पर पैंक्रियाज़ के बीटा सेल्स ठीक से काम करना बंद कर देते हैं और इससे एंटीबॉडीज़ बनने बंद हो जाते हैं. इसमें व्यक्ति को प्रतिदिन इंसुलिन देना पड़ता है तकि रक्त में ग्लूकोज़ की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके. वक़्त पर इंसुलिन न देने से व्यक्ति को डायबिटीक किटोएसिडोसीस हो जाता है और व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है.

### मधुमेह 2

नब्बे प्रतिशत लोगों में इसी प्रकार का मधुमेह देखा गया है. इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को कई प्रकार की रोज़मर्रा की परेशानियां हो जाती हैं. इसमें भी ग्लूकोज़ का निर्माण रक्त में होता है और शरीर में ऊर्जा के लिए सही प्रकार से सही तंत्र का इस्तेमाल नहीं कर पाता है.

### दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं

1. जल्दी-जल्दी प्यास का अहसास होना
2. बार-बार पेशाब की प्रबल इच्छा
3. भूख ज़्यादा लगना
4. वजन कम हो जाना
5. ठीक से दिखाई न देना
6. थकान और चिड़चिड़ाहट
7. हाथ-पैर में झनझनाहट
8. छोटे-मोटे इन्फेक्शन और चोट, घाव भरने में वक़्त का ज़्यादा लगना

### मीठी बीमारी में लाभकारी है योग

- डायबिटीज़ को प्रमुखता देते हुए भारत स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष 'योग' विभाग द्वारा देश में कई योगशालाएं खोलने की बात प्रस्तावित की गई है, जिनका लक्ष्य होगा ग्रामीण भारत तक इस विद्या को पहुंचाना.
- आयुष के मोरारजी देसाई योग संस्थान के डॉ. ईश्वर आचार्य के अनुसार, योग के क्रियाओं, आसनों, प्राणायाम, बंधों, साधनाओं व सात्विक आहार द्वारा डायबिटीज़ संयम में रह सकता है, चूंकि भांति-भांति प्रकार के आसन, क्रिया, बंध और प्राणायाम से पैंक्रियाज़ से निकलने वाले इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है और इंसुलिन रोधक क्षमता को घटाया जा सकता है.
- यौगिक क्रियाओं को किसी एक्सपर्ट की देख-रेख में करें. आस-पास योग केंद्र न होने पर पास के किसी शहर में जाकर कुछ दिन रुक कर योग प्रशिक्षण लें और आजीवन यौगिक करने के लिए खुद को तैयार करें.

### मधुमेह के कारण

**1. वंशानुगत :** यदि मां डायबिटीक हो तो बच्चों के इस बीमारी से ग्रसित होने की संभावना दो से तीन प्रतिशत मानी जाती है और यदि बच्चे के पिता को यह बीमारी है तो बच्चों में इसकी आशंका और भी बढ़ जाती है.

**2. प्रौढ़ अवस्था :** बढ़ती हुई उम्र में मधुमेह की आशंका बढ़ जाती है. अस्सी प्रतिशत मामलों में रोगियों की उम्र पचास वर्ष से ऊपर देखी गई है.

**3. कुपोषण या असंतुलित आहार :** अनुपयुक्त या अशुद्ध आहार, अल्प प्रोटीन और फाइबर लेना या तली-भुनी चीज़ें ज़्यादा खाने से भी मधुमेह होने की आशंका रहती है.

**4. मोटापा/स्थूलता :** आजकल के बच्चे पेप्सी, कोला व जंक फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे वे सीधे तौर पर मोटापा के शिकार हो रहे हैं और साथ में मधुमेह के भी.

**5. सुस्त जीवनशैली :** अपनी दिनचर्या में सुस्त रहने वाले लोगों को मधुमेह होने का ज़्यादा ख़तरा होता है. हफ़्ते में तीन बार व्यायाम करने वाले लोग डायबिटीज़ के शिकार कम होते हैं.

**6. स्ट्रेस/तनाव :** शारीरिक चोट हो या मानसिक तनाव दोनों डायबिटीज़ को बढ़ावा देती हैं.

**7. ड्रग का सेवन :** क्लोजापाइन क्लोजारिल, ओ-लेनजापाइन जायपेरेक्सा, रीसपेरीडोन रीसपर्डल, क्वेटीयापाइन सेरोक्वेल, जिप्रासीडोन जियोडॉन जैसे ड्रग्स इस प्राणघातक बीमारी को दावत देते हैं.

**8. इंफेक्शन :** इस इन्फेक्शन के होने से पूरा शरीर प्रभावित होता है और परिणामस्वरूप मधुमेह की आशंका बढ जाती है.

**9. संभोग :** वैसे संभोग से होने वाले डायबिटीज़ ज़्यादातर पुरुषों में देखी जाती है पर यह उन महिलाओं में भी ख़ूब देखी जाती है जो अपने जीवन काल में कई बार गर्भवती हो जाती हैं.

**10. सीरम लीपिड व लाइपोप्रोटीन :** रक्त में ट्राइग्लिसराइड और कॉलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर से ब्लड शुगर होने की संभावना हो जाती है जिससे मधुमेह होना स्वाभाविक हो जाता है.

### मधुमेह का असर

ज़्यादा ब्लड शुगर होने से हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है और रक्त का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है. शरीर का स्वप्रतिरक्षी तंत्र अव्यवस्थित होने के साथ ख़ून का संचार भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है. दृष्टि कमज़ोर हो जाती है और शरीर के जोड़ों में दर्द होता है. मधुमेह के रोगी को त्वचा रोग, जनन मूत्रीय परेशानियां व सांस लेने की तकलीफ़ हो सकती है. यदि डायबिटीज़ का इलाज जल्द से जल्द शुरू करने के साथ परहेज़ न किया जाए तो कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं- जैसे अंधापन, गैंगरीन, मोतियाबिंद, डायबिटीक नेफ्रोपैथी, डायबिटीक न्यूरोपैथी, डायबिटीक फुट इत्यादि जिसका अंतरिम उपचार टांगें कटवाना हो सकता है. एक स्तर पर पहुंचकर मधुमेह जानलेवा हो जाता है. जानकारी ही इसका बचाव है. अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर इस मीठी बीमारी से बचा जा सकती है.

ritika@chauthiduniya.com

### होम्योपैथी से नियंत्रण

- होम्योपैथी में भी डायबिटीज़ जैसी जानलेवा बीमारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं. भारत स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष में होम्योपैथी विभाग के डिप्टी एडवाइज़र डॉ. आलोक कुमार के अनुसार होम्योपैथी से भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना फ़ायदेमंद है. इन दवाओं की ख़ासियत है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. इसे एलोपैथिक दवाओं के साथ भी लिया जा सकता है.
- होम्योपैथी में इसके लिए जामुन सत् जैसी कारगर प्राकृतिक दवाएं भी हैं.
- होम्योपैथी दवाओं की जानकारी न होने की वजह से लोग बिना किसी लेबल इत्यादि की जांच-परख किए किसी भी झोलाछाप डॉक्टर से दवा ले लेते हैं जबकि डॉ.आलोक के मुताबिक़, प्रत्येक राज्य में होम्योपैथी दवा बेचने के लिए व मेडिकल प्रैक्टिस के लिए स्टेट ड्रग लाइसेंस होना ज़रूरी होता है. जिस भी डॉक्टर के पास दिखाने जाएं उसके सर्टिफिकेट की जांच ज़रूर करें.

### अंग्रेजी दवाओं से बचें

- केमिकल कंपोज़िशन की वजह से लगातार कई वर्षों तक एलोपैथी दवाओं के सेवन से शरीर में कई प्रकार की परेशानियां होने लगती हैं.
- शुगर-फ्री लेने के भी कई साइड इफेक्ट हैं. लंबे समय तक दवा लेते रहने से सिरदर्द, पेटदर्द, याददाश्त कमज़ोर होना और भूख कम लगने लगती है. इस वजह से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को शुगर-फ्री का सेवन नहीं करना चाहिए.
- यदि ऐलोपैथी दवाओं के सेवन के साथ योग और होम्योपैथी दवाओं का सेवन करें तो कुछ वक़्त बाद ऐलोपैथी दवाओं से छुटकारा मिल सकता है, इसके साइड इफेक्ट्स से बचा जा सकता है और साथ ही आसान व सही तरीक़े से मधुमेह को नियंत्रण में भी रखा जा सकता है.

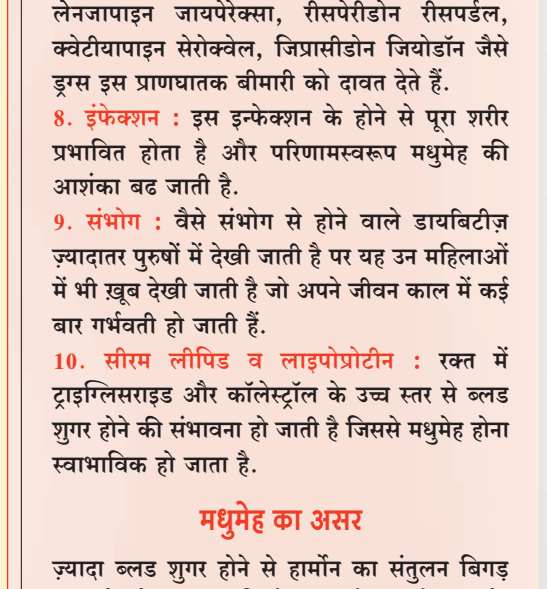


फ्लू में भी लाभकारी
कासमधु®
आयुर्वेदिक डाक्टर का बनाया हुआ फार्मूला

खांसी, नजला, जुकाम के लिए आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का योग
- कासमधु एल्कोहल रहित है। यह फेफड़ों व गले की नली में जमें बलगम को पतला करके बाहर निकालता है।
- सूखी व बलगमी खांसी में तुरन्त राहत पहुँचाता है।
- यह नजला व जुकाम में भी गुणकारी है।
- बच्चों के लिए भी सुरक्षित है।

43 YEARS OF TRUST HEALTH CARE

आँवला, हिना, ब्राह्मी के गुणों से युक्त हेयर स्पेशलिस्ट
केश जीवन तेल®

प्राकृतिक हर्बल हेयर आयल
- बालों का झड़ना/टूटना रोके, लम्बा, घना व काला बनायें
- पोषक तत्वों से भरपूर, चिपचिपाहट रहित
- सिर ठण्डा रखें सन स्ट्रोक (लू) से रक्षा करें।
- बालों को मजबूती दें और रूसी भी मिटाए।

ISO 9001 : 2000 & G.M.P. Certified Co
Mfd. by : TULISON® PHARMA
118H, East Moti Bagh, Sarai Rohilla, Delhi-110 007
Helpline : 011-23697278, 23694235 Fax : 011-23693500 E-mail : tulisonpharma@rediffmail.com Website : www.kasmadhu.in
Dealers : ● DELHI : Green Cross Herbals : 9899161855, ● U.P. : Ankit Enterprises, Noida : 9868416900, ● HARYANA : Medicine House, Panipat : 2648805, G.M. Medicine Centre, Rohtak : 256023, Gupta Pharma, Gurgaon : 9818564820, ● PUNJAB : Mukim Medical Agency, Ludhiana : 9417215515, Sh. Mukut Krishna, Bhatinda : 9463628512, Prakash Aushdhalaya, Chandigarh : 9888076156, Shiva Medical Agencies, Panchkula : 9872333733, Dinesh Pharma, Pathankot : 9855333755, Barumal Bhagwandas, Patiala : 9888089321 ● UTTRANCHAL : Tayal Agencies, Haridwar : 223085, Hitkari Vastu Bhandar, Dehradun : 2654802, Priya Sales, Haldwani : 9837543362, ● M.P. : Matadeen Medicos, Gwalior : 4077083, ● H.P. : Pittamber Medical Agencies, Kangra : 9816066189, Happy Medical Store, Una : 9418497477, Aaree Medical Agency, Joginder Naagr : 222127, ● RAJASTHAN : Aggarwal Ayurvedic & Medicals, Jaipur : 9351584411, Bhikha Ram Ram Dayal, Dholpur City : 9414584974 ● MAHARASTRA : Mumbai : Mitoba Biotech : 9820661700, ● THANE : Paras Medico : 9821061098, Rajesh Medical & Gen Store : 25449697 ● AKOLA : Chaudhary Ayushdhyala : 9422893089.

## राशिफल

(12 से 18 अक्टूबर तक)

**मेष** 12 से 18 अक्टूबर
आपके कुछ कार्य सफल होंगे. साथ ही आपके साथ अचानक कुछ ऐसा हो सकता है, जिससे लाभ की प्राप्ति होगी. स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें. कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. आर्थिक दिशा में किए जा रहे कार्य सफल होंगे.

**वृष** 12 से 18 अक्टूबर
किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग बने हुए हैं. जोख़िम की स्थिति बनेगी, इसलिए आर्थिक मामलों पर अभी कोई क़दम न उठाएं. समाज के लिए काम करेंगे तो उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. किसी कार्य में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

**मिथुन** 12 से 18 अक्टूबर
किसी पर अधिक विश्वास करना हानिकारक हो सकता है. मेलजोल की स्थिति बनेगी. मन प्रसन्न रहेगा. ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी. किसी अज्ञात डर के कारण परेशान भी रह सकते हैं. अपने सम्मान की सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है.

**कर्क** 12 से 18 अक्टूबर
पारिवारिक मामलों में अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी. किसी भी कार्य को करने से पहले विचार-विमर्श अवश्य करें. यात्रा की स्थिति बन रही है जो लाभदायक हो सकती है. आमोद-प्रमोद के सामानों पर व्यय अधिक होगा.

**सिंह** 12 से 18 अक्टूबर
सामाजिक क्षेत्र में काम करने की सोचेंगे तो सम्मान प्राप्त होगा. आपको कुछ अनावश्यक ख़र्च करना पड़ सकता है. आय के नए अवसर बनेंगे. बेटे के कॅरियर के संबंध में चिंता बढ सकती है. घर में भौतिक सुख सुविधाओं के साधन बढ़ेंगे.

**कन्या** 12 से 18 अक्टूबर
पारिवारिक कलह से बचें. अपनों से कार्य निकालने में सफल होंगे. आर्थिक क्षेत्र में कुछ नया करने की सोचेंगे तो लाभ अवश्य ही मिलेगा. यदि आप परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी. संतान के संबंध में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी.

**तुला** 12 से 18 अक्टूबर
बड़ी बहन से किसी बात पर विवाद हो सकता है, संयम बरतना हितकर होगा. कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा और आप व्यस्त भी रहेंगे. कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है तो उसका परिणाम आपके लिए अनुकूल नहीं होगा. नेत्र संबंधी विकार होने की आशंका है.

**वृश्चिक** 12 से 18 अक्टूबर
दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नुक़सान दे सकता है. अधिक व्यस्त होने के बावजूद मनोरंजन के सुखद अवसर मिलेंगे. धैर्य बनाकर रखें, नहीं तो संबंधों में दरार आने की आशंका है. कोई ऐसा भी कार्य होगा जिससे आपके प्रभाव तथा सम्मान में वृद्धि होगी.

**धनु** 12 से 18 अक्टूबर
जारी प्रयास सफल होगा. मानसिक और शारीरिक सुख में वृद्धि होगी. ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी साथ ही देवदर्शन होंगे. संतान का स्वास्थ्य प्रभावित होने की आशंका है, समय-समय पर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें. आय के नए मार्ग बनेंगे.

**मकर** 12 से 18 अक्टूबर
मकान,संपत्ति एवं ज़मीन आदि को लेकर चली आ रही समस्या का समाधान हो जाएगा. रचनात्मक कार्यों की दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल होगा. आप कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा.

**कुंभ** 12 से 18 अक्टूबर
निजी कार्यों में अधिकता रहेगी. निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी. पिता से छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं वाणी पर मधुरता बनाए रखें. कार्यकुशलता से प्रभावित होकर संबंधित अधिकारी के सहयोग के पात्र बनेंगे. परिवार के साथ आपका समय सुख के साथ गुज़रेगा.

**मीन** 12 से 18 अक्टूबर
भाग्यवश कोई अधूरा कार्य संपन्न हो जाएगा. उच्च रक्तचाप के रोगी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें. व्यावसायिक कार्य अगर आप साझे में करना चाहते हैं तो विचार-विमर्श करके ही निर्णय लें. बातचीत में सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी किसी बात से कोई नाराज़ हो सकता है.

ज्योतिषाचार्य पं. सुदर्शन

ख़बरिया चैनलों को जी भर कर गाली देना एक फ़ैशन सा हो गया है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप गाली देने के लिए भी स्वतंत्र हैं, पर इसके कुछ तार्किक आधार तो हों. दुख तब होता है, जब मीडिया भी इसमें शामिल हो जाती है.



# धुंधली छवि का विशेषांक

अनंत विजय

साहित्य, संस्कृति और कला का समग्र मासिक होने का दावा करनेवाली मासिक पत्रिका कथादेश ने अगस्त में मीडिया पर केंद्रित भारी-भरकम विशेषांक निकाला. इस अंक का संपादन पूर्व पत्रकार और अब शिक्षक अनिल चमड़िया ने किया है. अनिल चमड़िया पिछले कई सालों से कथादेश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर स्तंभ लिखते रहे हैं और यदा-कदा उसके संपादकों के नाम खुला पत्र लिखकर इस माध्यम को लेकर अपनी चिंता प्रकट करते रहे हैं. कथादेश के मीडिया विशेषांक में भी अनिल ने मीडिया के पतन पर अपनी गहरी चिंता जताई है. मीडिया के अधोपतन पर अतिथि संपादक इतने विचलित हो गए कि आख़िरकार उनकी भी चिंता की सूई टीआरपी पर आकर टिक गई. टीवी पत्रकारों पर लिखते हुए चमड़िया ने लिखा- पूंजीवाद ने उनके बीच कई हिस्से तैयार कर दिए. एक हिस्सा वह है जो चांदी काट रहा है. मीडिया मालिकों की तरह राजसभा (संभवत : वो राज्यसभा लिखना चाह रहे हों ) में रंगरलियां मना रहा है. इनकी रंगरलियों का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ये चंद वर्षों में सैकड़ों-करोड़ों डॉलर के मालिक बन गए. वे चैनल चला रहे हैं और उसी तरह से चला रहे हैं जैसे रुपर्ट मर्डोक और दूसरे साम्राज्यवाद समर्थक चैनल चलाते हैं. जो चैनल मालिक नहीं बन पाया, वह जिस तरह से चैनल चला रहा है, उनके उसी तरह चलने की बेशर्मी से वकालत करता है. टीआरपी को वह अपने कुकर्मों का सुरक्षा कवच बनाता है और ये नहीं बताता है कि टीआरपी क्या है? टीआरपी सांस्कृतिक वर्चस्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार हुआ है. इसमें पूंजी किसी संस्थान की नहीं, बल्कि पूंजीवादी विचारधारा की लगी हुई है. इसके वर्चस्ववादी सांस्कृतिक हथियार होने का प्रमाण तब मिलेगा, जब टीआरपी के ढांचे के रहस्य को खोला जाए. यहां अनिल चमड़िया ने टीआरपी की बेहद मनोरंजक और मौलिक व्याख्या की है - टीआरपी ख़ास तरह के विचारों को थोपने और अपनी मौलिकता को भुला देने वाला सांगठिक हथियार है- लेकिन, अपने इस फ़तवा के समर्थन में उन्होंने कोई उदाहरण या तर्क प्रस्तुत नहीं किया है. अपनी इस प्रस्थापना को पूंजीवाद, बाज़ारवाद, संकट का समय, संगठन जैसे शब्दों की चाशनी में डुबोकर पाठकों पर अपनी विद्वता का परचम लहरा दिया है. टीआरपी को बग़ैर जाने समझे उसे गाली देने का फ़ैशन बन गया है और अनिल उस फ़ैशन के शिकार हो गए हैं. ऐसा नहीं है कि अनिल चमड़िया ने सिर्फ़ न्यूज़ चैनलों की आलोचना की है. इन्होंने समान भाव से अख़बारों के गिरते स्तर पर भी अपनी चिंता जताते हुए पत्रकारों को कोसा है. अनिल इस बात का ख़तरा भी उठाते हुए चलते हैं कि उनके आलोचक उनपर एक ऐसे संत का ठप्पा लगा सकते हैं कि जो गांधी आश्रम में बैठकर पत्रकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार और गंदगी को अपनी लेखनी से साफ़ करना चाहता है. लेकिन, मैं उनके आलोचकों को ये कहना चाहता हूं कि संत तो संत होता है जो सिर्फ़ प्रेरित कर सकता है, पहल नहीं. अनिल चूंकि इस अंक के संपादक हैं, इसलिए रचनाओं पर भी उनके विचारों की छाप साफ़ दिखाई देती है. कई लेखक टीआरपी को लेकर रोते दिखाई दे रहे हैं. सिर्फ़ उमेश चतुर्वेदी ने अपने लेख में टीआरपी को समझने और समझाने की कोशिश की है. उमेश ने टीआरपी की तथाकथित गुत्थी को खोला है. श्रमपूर्वक लिखे गए इस लेख से टीआरपी की कई भ्रांतियां दूर होती हैं.

इस अंक में लेखों की भरमार है. यहां-वहां, जहां-तहां से लेखों को इकट्ठा कर, अनुवाद कर, प्रकाशित कर दिया गया है. वरिष्ठ टीवी पत्रकार अजीत अंजुम के पिछले साल पत्रकारिता संस्थान में दिए गए एक भाषण को छाप दिया गया है. भाषण देने की शैली और लिखने की शैली बिल्कुल अलग होती है. अजीत अंजुम के भाषण को लगता है, जस का तस छाप दिया गया है.

यहीं पर संपादक का दायित्व बनता है कि वो भाषण को लेख के रूप में संपादित कर दे. लेकिन, ये नहीं हुआ और साल भर पुराना भाषण छपा. जब अजीत अंजुम की बात चली तो बरबस जनवरी 2007 में उनके संपादन में हंस के मीडिया विशेषांक की याद आ गई. हंस का वह अंक भी लगभग ढाई सौ पृष्ठों का था. हंस का वह अंक, संपादन कौशल का बेहतरीन नमूना था. चिंताएं वहां भी थीं, लेकिन उन चिंताओं का जवाब भी था. राजदीप सरदेसाई, क़मर वहीद नक़वी, उदय शंकर के विचार इन चिंताओं से टकरा रहे थे. न्यूज़ चैनलों को लेकर जो कहानियां छपी थीं वो वहां काम करने वाले पत्रकारों के दर्द और प्रेम की प्रतिनिधि कहानियां थीं. मेरे जानते मीडिया पर हंस का वो अंक अब तक का सबसे अच्छा अंक है, जिसका एप्रोच एकदम फ़ोकस्ड है.

कथादेश के इस अंक में एक गुमनाम लेख छपा है, जिसमें स्टार न्यूज़ के संपादक शाजी जमां पर बेहद संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं. इस लेख के बारे में संपादक ने कहा है कि इंटरनेट के ज़रिए स्टार न्यूज़ के न्यूज़रूम में घूमता एक पत्र हमारे हाथ लगा है और विद्वान और पत्रकारिता में शुचिता की बात करने वाले संपादक अनिल चमड़िया ने इंटरनेट पर घूमते एक गुमनाम ख़त को मीडिया विशेषांक में छापकर मान्यता प्रदान कर दी. लेख के पहले अवश्य एक टिप्पणी संपादक की ओर से है, लेकिन यह लेख बेहद घटिया और स्तरहीन है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है. स्टार न्यूज़ के संपादक शाजी जमां पत्रकार के साथ-साथ एक संवेदनशील लेखक भी हैं. इनके लिखे को पढ़ने के बाद कथादेश में छपे इस लेख को पढ़कर ये लगता है कि कोई व्यक्ति शाजी को बदनाम करने की मंशा से ऐसा कर रहा है और कथादेश जाने-अनजाने बदनाम करने की उस मुहिम में उसका साथ देता नज़र आ रहा है.

कुल मिलाकर, अगर कथादेश के मीडिया विशेषांक पर समग्रता से विचार करें तो ये बेहद हल्का और उथला है. ढाई सौ पृष्ठों का ये भारी-भरकम विशेषांक डीफोकस्ड लगता है, जिसमें से कोई साफ़ तस्वीर सामने नहीं आती है. इस अंक की पहली रचना पंकज श्रीवास्तव की है, मी लॉर्ड ! आप समझ रहे हैं ना. इसमें पंकज ने मुन्नाभाई और गांधी की शैली में अपने अनुभवों को बेहद रोचक शैली में पेश किया है. इसे इस अंक की उपलब्धि के तौर पर रेखांकित किया जा सकता है.

*(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं.)*

feedback@chauthiduniya.com

# क्यों पूजते हैं पत्थर

देवेन्द्र झा

पत्थर भी हमारी तरह जीवात्मा हैं. फिर, हमें यह भी ज्ञात है कि वैज्ञानिक पत्थर की उम्र भी निकालते हैं और किसी पत्थर को डेड स्टोन अर्थात मृत पाषाण भी घोषित करते हैं. उनके इस प्रकरण से स्पष्ट होता है कि पत्थर का अपना जीवन-काल होता है. उसकी उत्पत्ति होती है और अंत भी होता है. ये सारे लक्षण सजीव के होते हैं, अत: पत्थर भी सजीव हुआ. चूंकि, उपर्युक्त सारे कार्य अविनाशी, आत्म-तत्व के बिना संभव नहीं हो सकते, अत: इसमें निस्संदेह आत्मा का वास है, यह सिद्ध हो जाता है. यह सत्य हमारे ग्रंथों में कथा रूप में वर्णित हैं, जिनके कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं.

### पर्वतराज हिमालय

हमारे ग्रंथों में पर्वतराज हिमालय का वर्णन विलक्षण मानव के रूप में मिलता है. जिसके माध्यम से मनीषियों ने इस सत्य को जन-समुदाय के समक्ष रखा कि एक कलाधारी जीव अर्थात पर्वत अपने तेज़ बल से चार पांच और कलाओं को धारण कर श्रेष्ठ मनुष्य बन सकता है. अब यहां यह प्रश्न उठता है कि अगर पर्वतराज हिमालय में आत्मा नहीं थी, तो कारक शक्ति के बिना उन्होंने अपनी कलाओं को कैसे बढ़ा लिया और सिर्फ़ कलाओं के बढ़ने से निर्जीव, सजीव कैसे हो गया? अब उपर्युक्त दोनों स्थितियां आत्मा के बिना संभव नहीं हैं, अत: यह सिद्ध हुआ कि पर्वत में आत्मा होती है. कथा के माध्यम से यह साफ़ इंगित होता है कि संपूर्ण पाषाण-जगत का प्रगटीकरण आत्म-तत्व के साथ ही संभव हो पाया है.

### गौतम-पत्नी अहिल्या

यह कथा सर्वविदित है कि गौतम ऋषि के श्रापवश उनकी पत्नी अहिल्या पत्थर बन गई और जब श्रीराम के चरण-रज ने उस पत्थर का स्पर्श किया तो उसने पुन: नारी रूप को प्राप्त कर लिया. इस प्रसंग से कई प्रश्न जन्म लेते हैं. प्रथम प्रश्न तो यह होगा कि श्रापवश अगर अहिल्या का शरीर पत्थर का बन गया और पत्थर में चूंकि आत्मा नहीं बस सकती, इस कारण अहिल्या की आत्मा अन्यत्र कहीं चली गई तो उसकी आत्मा ने कोई और रूप धारण कर लिया होगा और इस स्थिति में अहिल्या नहीं, बल्कि उसका मात्र शरीर पत्थर का रूप धारण किया तो क्या श्राप मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ? श्राप तभी मिथ्या सिद्ध नहीं होगा जब अहिल्या की आत्मा भी उस पत्थर में बस गई हो और तभी यह संभव हो पाया कि पत्थर-रूपी अहिल्या भगवान श्रीराम के चरण-रज का स्पर्श पाते ही पुन: नारी रूप प्राप्त कर पाई. इस कथा से यह सत्य स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है कि पत्थर में भी आत्मा का वास होता है. गौतम ऋषि के श्राप ने अहिल्या की एक कला को छोड़कर शेष सारी कलाएं छीन लीं और अहिल्या एक कलाधारी जीव अर्थात पाषाण रूप में परिणत हो गई. भगवान श्रीराम के चरण-रज के स्पर्श ने अहिल्या की श्राप

द्वारा छीनी हुई कलाएं लौटा दीं, फलत: अहिल्या पूर्ववत नारी रूप में प्रकट हो गई.

उपरोक्त दोनों कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि पाषाण ब्रह्म का प्रथम प्रकट स्वरूप है. अत: ब्रह्म के इस प्रथम प्रकट स्वरूप को ब्रह्म का प्रतीक मानकर पूजा अर्चना हेतु अपनाया गया. तब से पत्थर को ब्रह्म के अनेक रूपों में एक रूप देकर पूजा जाने लगा और इस तरह साकार ब्रह्म की उपासना हेतु मूर्ति-पूजा सशक्त परंपरा के रूप में प्रचलित हुई. यह परंपरा ब्रह्म के सर्वत्र प्राप्त होने वाले गुण को प्रतिबिंबित करने का प्रथम प्रयास है.

*(लेखक प्रसिद्ध इंजीनियर हैं.)*

feedback@chauthiduniya.com

spice
www.spice-mobile.com
अब सब खल्लास!
मल्टी-सिम M-4580 की आकर्षक कीमत और भरपूर खूबियाँ करे सबको खल्लास।
M-4580
किलर खूबी: बड़ी बैट्री
25 दिनों का स्टैंड-बाइ टाइम और 10 घंटों का टॉकटाइम
मल्टी-सिम (GSM/GSM)
MP3 प्लेयर और FM रिकार्ड
वन-टच टॉर्च और करैन्सी चेकर
4 GB तक एक्सपैन्डेबल मैमोरी
BEST BUY PRICE: Rs. 2149
M-5252
10 दिनों का स्टैंड-बाइ टाइम और 4 घंटों का टॉकटाइम
मल्टी-सिम (GSM/GSM)
डिजिटल कैमेरा
बिल्ट-इन FM एंटेना
ड्यूअल LED टॉर्च
8 GB तक एक्सपैन्डेबल मैमोरी
BEST BUY PRICE: Rs. 3049
C-5300
सभी CDMA कनेक्शन के साथ चले
बड़ी स्क्रीन
डिजिटल कैमेरा
MP3 प्लेयर और FM रिकार्ड
एक्सपैन्डेबल मैमोरी
वन-टच टॉर्च
BEST BUY PRICE: Rs. 2999
बड़ी स्क्रीन | बड़ी मैमोरी | बड़ा साउण्ड | बड़ी बैट्री
big series
Spice Mobiles come loaded with:
emergic email2sms Mail on Mobile | Shuffle Ring tone | mGurujee | ibibo i build · i bond | REUTERS | Mobile Tracker
Registered Office: Spice Mobiles Ltd., D-1, Sector-3, Noida 201301, Uttar Pradesh, India. Fax: +91-120-4363845. E-mail: contactus@spicemobile.in. Spice Mobile Phones are available at all leading telecom outlets. *Conditions apply. Price features and specifications are subject to change without prior notice. Some of the listed capacity is used for phone functions and thus available capacity could be less than the quoted figure. Battery operation time may vary depending on network usage, environment, music and video formats.
www.itsaugust.com

क्या आप लैपटॉप को वायर कनेक्टर से चार्ज कर-कर के परेशान हो गए हैं. क्या आप तार लगाने की झंझट से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है.

# बिना तार से चार्ज होगा लैपटॉप

क्या आप लैपटॉप को वायर कनेक्टर से चार्ज़ कर-करके परेशान हो गए हैं? क्या आप वायर कनेक्टर लगाने से मुक्ति चाहते हैं? यदि हां, तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. लैपटॉप बनाने वाली प्रमुख कंपनी डेल आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आई है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे. चौंकना भी लाजिमी है, क्योंकि पीसी बनाने वाली किसी भी कंपनी ने अभी तक ऐसा प्रयोग नहीं किया है. हालांकि, फोन बनाने वाली कुछ कंपनियों ने इस क्षेत्र में क़दम अवश्य बढ़ाया है.

कॉरपोरेट कस्टमर को ध्यान में रखकर डेल ने एक नया लैपटॉप, लैटिट्यूड जेड नाम से बाज़ार में लांच किया है. यह लैपटॉप बाक़ी लैपटॉप से अलग तो नहीं है, लेकिन इसके फीचर्स निश्चित तौर पर दूसरे लैपटॉप से अलग हैं. डेल ने एक बार फिर एक थीन नोटबुक लांच कर ख़ुद को श्रेख़ साबित करने की कोशिश की है और निश्चित तौर पर वह ऐसा करने में सफल भी रही है. ब्लैक चेरी रंग में उपलब्ध इस लैपटॉप का डिज़ाइन काफी आकर्षक है. इसकी लंबाई 16 इंच और मोटाई 14 मिलीमीटर है. इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत है यह लैटिट्यूड जेड बिना वायर से चार्ज होता है. डेल के मुताबिक़ वायर की मदद के बग़ैर भी आप इस लैपटॉप को आसानी से चार्ज कर सकते हैं. जिस पैड पर लैपटॉप को रखा जाता है, उसी पैड के ज़रिए आप लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं. पैड भी उतनी ही देर में चार्ज करता है, जितनी देर में एक प्रमाणित कोबल्ड चार्जर. वैसे स्मार्ट फोन बनाने वाली कंपनी पाल्म पहले ही इस तरह (वायरलेस चार्जिंग) की व्यवस्था अपना चुकी है. हालांकि, विस्टन और वाइल्ड चार्ज (मोबाइल एसेसरीज में) वायरलेस चार्जिंग के क्षेत्र में क़दम रख चुकी है. लेकिन, सबसे बड़ी बात यह है कि डेल के अलावा किसी भी पीसी बनाने वाली कंपनी ने अब तक वायर लेस चार्जिंग सिस्टम को नहीं अपनाया है.

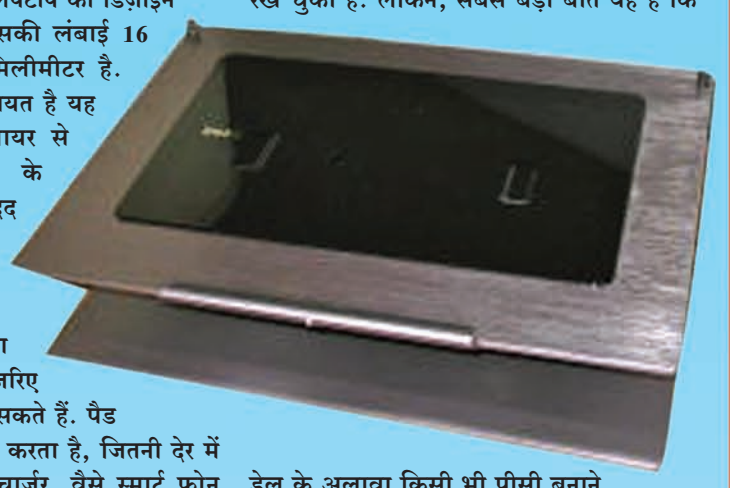

# सोनी का सायबर शॉट

क्या आप कैमरा के शौक़ीन हैं? क्या फोटो लेना आपकी आदत में शुमार है? क्या हर प्राकृतिक दृश्य को आप कैमरे में क़ैद करना चाहते हैं, लेकिन कैमरा भारी होने की वजह से आप असहज महसूस करते हैं या फिर पिक्चर क्वालिटी को लेकर चिंतित रहते हैं? यदि ऐसा है तो अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सोनी ने एक नया कैमरा सायबर-शॉट डीएससी-टी 90 लांच किया है, जिसे आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कंपनी ने तैयार किया है. हालांकि, सायबर शॉट डीएससी-टी 90 में वे सारी ख़ूबियां मौजूद हैं, जिससे पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है. इसका लुक बहुत अट्रैक्टिव है. इतना ही नहीं, इसका वजन भी बहुत कम है. पास में रहने के बावजूद आपको यह एहसास तक नहीं होगा कि आपके पास कोई कैमरा भी है. इसका वजन महज़ 148 ग्राम है और इसका आकार 94. 57. 15 मिलीमीटर है. वैसे तो देखने में यह काफी छोटा है, लेकिन फीचर्स के मामले में यह कैमरा दूसरे कैमरों जैसा ही है. इसकी ख़ासियत यह है कि इसमें तीन इंच का एलसीडी स्क्रीन है. इसकी सहायता से आप छवि को आसानी से देख सकते हैं. इसमें मैनुअल आईएसओ कंट्रोल की कमी आपको अखर सकती है. कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कैमरा घरेलू उपयोग के लिए काफ़ी अच्छा है. इसकी क़ीमत 17,990 रुपये है. हर लिहाज से यह एक बढ़िया कैमरा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि यह कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है या नहीं.

**सायबर शॉट डीएससी-टी 90 में वे सारी ख़ूबियां मौजूद हैं, जिससे पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है. इसका लुक बहुत अट्रैक्टिव है. इतना ही नहीं, इसका वजन भी बहुत कम है . पास में रहने के बावजूद भी आपको इसका एहसास तक नहीं होगा कि आपके पास कोई कैमरा है.**

# सीगेट ने लांच किया एनक्रिप्टिंग ड्राइव

सीगेट हार्ड डिस्क ड्राइव और स्टोरेज सॉल्यूशन डिज़ाइन बनाने और बेचने में दुनिया की अग्रणी कंपनी है. सीगेट टेक्नोलॉजी (नैसडैक : एसटीएक्स) ने सीगेट सिक्योर सेल्फ एनक्रिप्टिंग ड्राइव पेश करने की घोषणा की है. यह एंटरप्राइज श्रेणी के हार्ड ड्राइव की शृंखला में एक विकल्प है. इस विकल्प में सेवियो 15 के.2, सेवियो 10 के.3, कांसटेलेशन और चीता 15 के.7 ड्राइव हैं. इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सर्वर और स्टोरेज सिस्टम के लिए यह डाटा ऐट रेस्ट सुरक्षा मुहैया कराएगा. गारनर में वाइस प्रेसिडेंट एरिक ओउलेट ने कहा कि एसईडी का उपयोग कारोबारों को संपूर्ण डाटा ऐट रेस्ट सुरक्षा मुहैया करता है. एसईडी के उपयोग से सिस्टम का डाटा सुरक्षित रहता है. चाहे स्मैश ग्रैब ड्राइव हो या संपूर्ण सिस्टम की चोरी, सभी मामलों में यह उपकरण डाटा से छेड़छाड़ का सामना आसानी से कर सकता है. सूचना टेक्नोलॉजी प्रबंधकों को राजस्व और बाज़ार में हिस्सेदारी के साथ-साथ ग्राहक को भी संतुष्ट करना होता है. इसके अलावा सूचना के लिहाज़ से संवेदनशील कारोबारों जैसे हेल्थकेयर, बैंकिंग और इंश्योरेंस में सरकारी सुरक्षा नियमों का पालन करना सूचना टेक्नोलॉजी प्रबंधकों के लिए चिंता की बात होती है. इन संस्थाओं से रोज़ाना 50,000 ड्राइव और टेराबाइट डाटा बाहर निकलते हैं और वारंटी के लिए वापस आने वाले 90 प्रतिशत डाटा ही पढ़ने योग्य होते हैं. इसलिए सेफ ड्राइव रिटायरमेंट दुनिया भर में कारोबारों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है.

# सैमसंग का स्मार्ट फोन गैलेक्सी आई-7500

क़रीबन रोज़ कोई न कोई कंपनी भारतीय बाज़ार में अपना मोबाइल फोन उतारती है. सभी की कोशिश अपने यूज़र्स को सबसे बेहतर और लेटेस्ट सुविधा देने की होती है. कुछ इसी मक़सद से सैमसंग ने पहली बार भारतीय बाज़ार में एंड्रायड स्मार्ट फोन गैलेक्सी आई-7500 लांच किया है. इस हैंडसेट्स को आप टाटा डोकामो से ख़रीद सकते हैं. यह इतना आकर्षक है कि देखते ही आपका दिल इसे ख़रीदने को मचल उठेगा. इसका फुल टच स्क्रीन निश्चित रूप से यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है. इस हैंडसेट्स में गूगल के एंड्रायड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है. इसमें लगा पांच मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा इसकी ख़ूबी में चार चांद लगाता है. जहां तक दूसरी सुविधाओं की बात है तो यह मल्टीमीडिया फीचर, एमपी-3, डब्ल्यूएमए प्लेयर और एमपीईजी-4 प्लेबैक वीडियो आदि सुविधाओं से लैस है. इसकी वीडियो प्लेयर सुविधा संगीत प्रेमियों की ज़रूरतें भी पूरी करेगा. इतना ही नहीं, इसकी इंटरनल मेमोरी आठ जीबी है, जिसे 32 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है. इस फोन के साथ माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड स्लॉट की सुविधा भी उपलब्ध है. टाटा डोकोमो के अध्यक्ष दीपक गुलाटी के मुताबिक़, हमने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराने का वादा किया था. इस वादे को हमने गैलेक्सी आई-7500 को भारतीय बाज़ार में उतार कर पूरा कर दिया है. यूजर्स सिर्फ़ एक टच पर गूगल सर्च, गूगल मैप्स, जी-मेल, यू-ट्यूब, गूगल, कैलेंडर, गूगल टॉक आदि सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं. अलग-अलग रंग के मोबाइल फोन रखने के शौक़ीन यूजर्स को थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि यह मोबाइल फोन ब्लैक रंग में ही उपलब्ध है और इसकी क़ीमत लगभग 28,000 हज़ार रुपये है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# बोस ने बाज़ार में उतारा नया म्यूजिक सिस्टम

संगीत प्रेमियों के लिए एक गुड न्यूज़ है. बोस ने एक डिजीटल म्यूजिक सिस्टम भारतीय बाज़ार में उतारा है, जो दूसरे की तुलना में काफी अलग है. तभी तो कंपनी यह दावा कर रही है लोग इसे हाथोंहाथ ख़रीदेंगे. बोस कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट की साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है. दसके इस नए साउंड डॉक- 10 डिजीटल म्यूजिक सिस्टम की साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी है. वह भी तब जबकि इसमें एक ही स्पीकर लगा हुआ है. कंपनी का दावा है कि इसकी ऑडियो क्वालिटी लोगों को निश्चित तौर पर पसंद आएगी. साउंड डॉक-10 का लुक भी बढ़िया है. इसकी उंचाई नौ इंच, चौड़ाई और गहराई क्रमश: 17 और दस इंच है. इसकी ख़ासियत है, इसमें एक ही स्पीकर और वूफर लगा हुआ है. इसमें काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है. जिसके चलते इसकी आवाज़ काफी अच्छी है. इतना ही नहीं कंपनी साउंड डॉक-10 के साथ एक ब्ल्यू टूथ ऑफर कर रही है. इसके ज़रिए लोग बिना तार लगाए ही गाना सुन सकते हैं. मतलब यह कि मोबाइल फोन को ब्ल्यू टूथ से कनेक्ट कर आप म्यूजिक का लुत्फ उठा सकते हैं. डॉक को आप ज़रूरत पड़ने पर बदल भी सकते हैं. यह बाज़ार में उपलब्ध है. अतिरिक्त उपकरणों जैसे- आई पॉड शफ्ल, एमपी-3 प्लेयर और पोर्टेबल सीडी प्लेयर आदि को जोड़ने के लिए अलग से इनपुट डिवाइस दिया गया है. इसके अलावा एक वीडियो ऑउट पुट भी दिया गया है. एक इंफ्रेड रिमोट कंट्रोल है. इससे यूजर्स साउंड -10 के बेसिक फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : 9811205225 email : advt@chauthiduniya.com

अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत विजेंदर, आज भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बेहतरीन मुक्केबाज़ों में एक हैं.

# भारी पड़ा गेंदबाज़ों का लचर प्रदर्शन

चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की सारी उम्मीदें धूमिल हो गई. बड़े मौक़ों पर फ़िसड्डी साबित होना भारतीय टीम की फ़ितरत रही है. सामने चुनौती देख पल भर में भारतीय शेर ढेर हो जाते हैं. भारतीय टीम हमेशा से कुछ स्टार खिलाड़ियों पर ही निर्भर रही है. दरअसल, भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है, गेंदबाज़ों का लचर प्रदर्शन. ज़रा याद कीजिए, मुनाफ़ पटेल को जब पहली बार टीम में शामिल किया गया तो वह सबसे तेज़ गति के गेंदबाज़ थे और अब टीम में भी जगह के लिए जद्दोजेहद कर रहे हैं. इरफान पठान, अंडर 19 टीम में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चमत्कारी प्रदर्शन की बदौलत ही इंडियन टीम में शामिल हुए थे. लेकिन, आज हालत यह कि उनके बड़े भाई युसूफ़ पठान को चयन में भेदभाव की वजह से पठान के टीम से बाहर होने का बयान देना पड़ा. इस तरह के विवादास्पद बयान ख़ामियां छुपाने की कवायद के अलावा कुछ भी नहीं. भारत में गेंदबाज़ों की हालत चार दिन की चांदनी से ज़्यादा कुछ भी नहीं होती. ईशांत शर्मा इसके ताज़ा-तरीन उदाहरण हैं. ईशांत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरज़मीं पर अपनी तेज़ गेंदबाज़ी की बदौलत मात देने में अहम भूमिका निभाई थी. आज लगता है उनकी धार ही कुंद पड़ गई है. पहले बेजान पिचों पर ग़जब के उछाल से विरोधियों को परेशान करने वाली ईशांत की गेंदें अब उछाल वाली पिचों पर भी शांत रहती हैं. हक़ीक़त यह है कि अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में लंबी रेस का घोड़ा दिखने वाला गेंदबाज़, चंद महीनों में ही क्लब लेवल का प्रदर्शन करने लगता है. भारत की अब तक सबसे बड़ी कमज़ोरी गेंदबाज़ों की ही रही है. चैंपियंस ट्रॉफी में गेंदबाज़ों का प्रदर्शन इसी बात की ओर इशारा करते हैं.

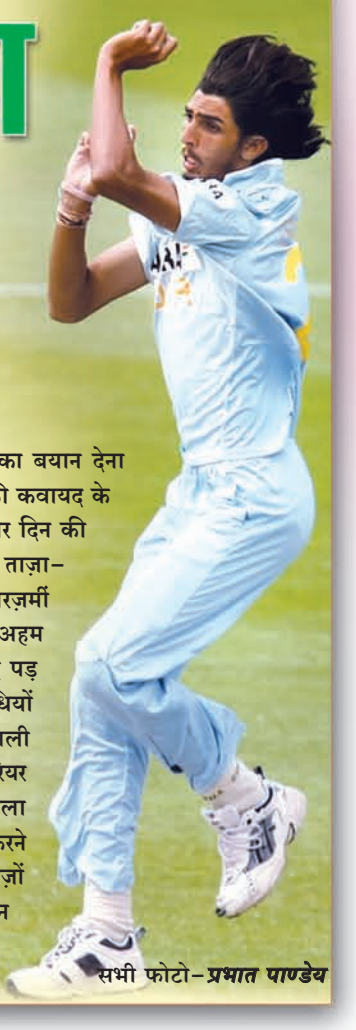

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

# विजेंदर बने विश्व के नंबर एक मुक्केबाज़

मुक्केबाज़ी में भारत को शीर्ष तक पहुंचाने वाले मुक्केबाज़ विजेंदर ने एक नया मुक़ाम हासिल कर लिया है. ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय मुक्केबाज़ विजेंदर ने विश्व मुक्केबाज़ी के 75 किलोग्राम वर्ग में दुनिया के नंबर एक मुक्केबाज़ का तमगा भी अपने नाम कर लिया. विजेंदर के कुल 2700 अंक हैं और वे उजबेकिस्तान के मौजूदा चैंपियन एब्बोस अतोव को पीछे छोड़ रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर क़ाबिज़ हैं. ग़ौरतलब है कि हरियाणा के इस खब्बू खिलाड़ी को विश्व चैंपियनशिप में उजबेकिस्तानी मुक्केबाज़ अतोव से सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. इसके बावजूद नंबर एक का ताज़ अपने नाम करने में यह ओलंपिक पदक विजेता कामयाब रहा. विजेंदर मुक्केबाज़ी के मिडिल वेट में नंबर एक मुक्केबाज़ बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं. तो यह मुक़ाम हासिल करने के बाद वह कैसा अनुभव करते हैं. विजेंदर कहते हैं कि नंबर एक होना किसे पसंद नहीं होगा. इससे उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है.

# सबसे अमीर खिलाड़ी

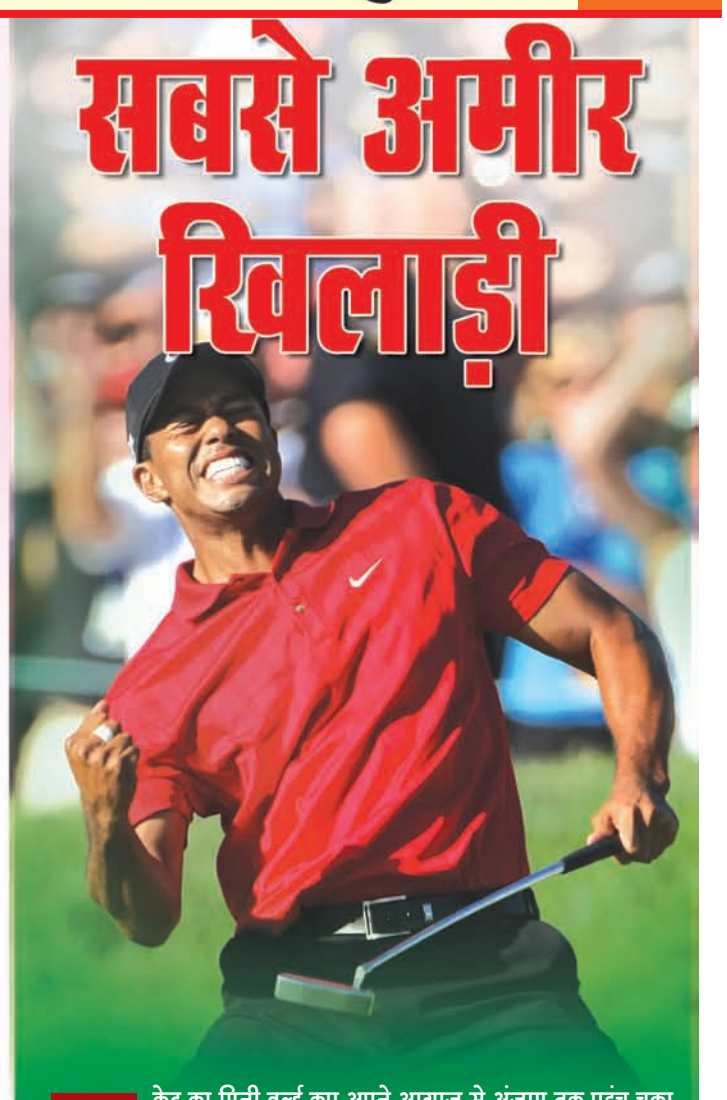

क्रिकेट का मिनी वर्ल्ड कप अपने आग़ाज़ से अंजाम तक पहुंच चुका है. भारत सहित कई देशों में तो खेल का मतलब ही क्रिकेट है. लेकिन कभी आपने सोचा है किस खेल में ज़्यादा पैसा है और कौन-सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा अमीर है? हम लोगों में कई यह सोचते होंगे कि हमारे क्रिकेटर साल भर खेलते रहते हैं और करोड़ों रुपये की कमाई करते हैं. इसके अलावा तमाम विज्ञापन के ज़रिए भी करोड़ों की कमाई में हमारे क्रिकेटर अव्वल हैं, तो यक़ीनन सचिन या धोनी ही सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ी होंगे. अभी हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने भी सबसे अमीर क्रिकेटरों की सूची जारी की थी. जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला क्रिकेटर बताया गया. लेकिन, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि धोनी करोड़ों रुपये की कमाई के बावजूद दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी नहीं हैं. जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा. दरअसल, दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी हैं, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स. पिछले साल वुड्स की कुल संपत्ति 90 करोड़ डॉलर थी जो इस वर्ष 100 करोड़ डॉलर के आंकड़े को भी पार कर गई. इसके साथ ही टाइगर वुड्स दुनिया के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जो एक अरब डॉलर के मालिक हैं. पूरी दुनिया में सबसे मशहूर और सर्वाधिक देखा जाने वाला खेल फुटबॉल है. उसके बावजूद कोई भी फुटबॉलर कमाई के मामले में इस गोल्फ खिलाड़ी के इर्द-गिर्द भी नहीं ठहरता.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया दिल्ली, 12–18 अक्टूबर 2009

थोड़े दिनों पहले तक उनके बीच प्रतिद्वंद्विता के चर्चे चल रहे थे और अब उनके साथ-साथ परदे पर आने की ख़बर से तो किसी का भी चौंकना लाज़िमी ही कहा जाएगा.



# एंट्री एक और सोनल की

स्टार प्लस पर प्रसारित टीवी सीरियल *सारा आकाश* में अपने अभिनय से धमाल मचा चुकी सोनल सहगल फिल्म *आशाएं* से एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही है. इस फिल्म में वह जॉन अब्राहम के अपोजिट नज़र आएगी. सोनल ख़ुद को लकी मानती है कि उन्हें पहली ही फिल्म में इतने बड़े सितारे के साथ काम करने का मौक़ा मिला है. सोनल की ख़ुशी की एक और वजह फिल्म निर्देशक नागेश कुकनूर भी हैं.

नागेश इससे पहले *इक़बाल, डोर* और *तीन दीवारें* जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं. ज़ाहिर है सोनम की आशाएं भी *आशाएं* पर ही टिकी हैं. वैसे आपको जानकारी होगी ही कि इससे पहले भी कई अभिनेत्रियां छोटे पर्दे से बड़े पर्दे की ओर रुख़ कर चुकी हैं. अब फिल्म *आलूचाट* की आमना शरीफ को ही लें. वह कब आईं और चली गई पता ही नहीं चल पाया. वैसे सोनल ने उस सीरियल से छोटे परदे पर काफी कामयाबी हासिल की थी तभी तो उन्हें जॉन की हीरोइन बनने का ऑफर मिला. बहुत-सी अभिनेत्रियों को छोटे परदे से बड़े परदे पर ऐंट्री पहले भी मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद कहां गुम हो गईं, किसी को कुछ पता नहीं. अब सोनल क्या गुल खिलाती हैं और उनकी आशाएं क्या इस फिल्म से पूरी हो पाएंगी या निराशा में बदल जाएंगी यह तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा.

# एक साथ दिखेंगी प्रियंका और कैटरीना

थोड़े दिनों पहले तक उनके बीच प्रतिद्वंद्विता के चर्चे चल रहे थे और अब उनके साथ-साथ परदे पर नमूदार होने की ख़बर से तो किसी का भी चौंकना लाज़िमी ही कहा जाएगा. जी हां, आप ने ठीक ही समझा. हम चर्चा दिग्गज अभिनेत्री कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा की ही कर रहे हैं. दोनों एक साथ एक नहीं, बल्कि दो फिल्मों- *ब्राइड वार* और *दोस्ताना 2*- में साथ आ रही हैं. *ब्राइड वार* हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है. बॉलीवुड के जाने-माने निर्माता-निर्देशक गोल्डी बहल की बहन सृष्टि आर्या ने यह फिल्म बनाई है. मूल फिल्म में जो भूमिका केट हडसन और एनी हेथवे ने निभाई है, रीमेक में प्रियंका और कैट ने उसी किरदार को परदे पर उतारा है. इस साल दोनों ही अभिनेत्रियों ने फिल्मों में ख़ूब अपना जलवा बिखेरा है, साथ ही दर्शकों की तारीफ़ बटोरने में भी दोनों कामयाब हुईं. उनकी आने वाली दोनों फिल्में उनको कितनी कामयाबी दिला पाएगी, यह तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद ही पता चल पाएगा. असल बात यह है कि कुछ समय से दोनों ने अपने पैर बॉलीवुड में बख़ूबी जमा लिए है. अब देखना यह है कि दर्शकों को ऐक्टिंग किसकी पसंद आती है. एक बात तो तय है, इन दोनों को परदे पर आमने-सामने देखना वाकई दिलचस्प होगा.

# किंग अब दक्षिण की फिल्मों में भी

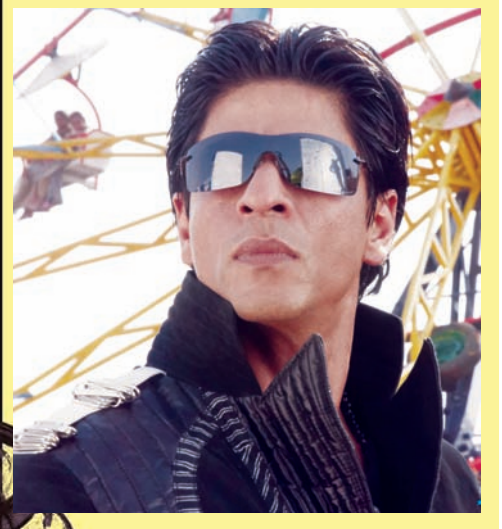

किंग ख़ान के बारे में जब कभी भी कुछ सुनने को मिलता तो वह कुछ नया ही होता है. इस बार किंग कई भाषाओं में बन रही फिल्म के लिए डबिंग कर रहे हैं. यह फिल्म केरल के एक क्रांतिकारी नायक पझास्सी राजा पर आधारित है. पझास्सी राजा केरल के मालाबार इलाक़े के वायनाड के राजा थे. ममूटी अभिनीत यह फिल्म हिंदी और अंग्रेज़ी सहित पांच भाषाओं में बन रही है. सूत्रों से पता चला है कि उन्होंने इस फिल्म की डबिंग के लिए काफी मोटी रक़म ली है. वैसे भी किंग अकेले नहीं हैं जिन्होंने फिल्म डबिंग के लिए पहली बार क़दम बढ़ाया हो. इससे पहले बॉलीवुड के कई जानेमाने सितारे फिल्मों में अपनी आवाज़ दे चुके हैं. उनमें करीना, सैफ और जावेद जाफरी ने एक साथ डबिंग की थी. शाहरुख ख़ान के लिए फिल्म की डबिंग करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वह इससे पहले भी हॉलीवुड की फिल्म *मिस्टर इनक्रेडिबल* के हिंदी संस्करण *मिस्टर लाजवाब* के लिए अपनी जवाब दे चुके हैं. इस डबिंग से भी उन्होंने काफी वाहवाही हासिल की थी और काफी दिनों तक चर्चा में भी बने रहे थे. शाहरुख ने पहले वाली फिल्म की डबिंग अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे आर्यन के लिए की थी. दरअसल, उस फिल्म में उनके बेटे ने आवाज़ दी थी. पहली डबिंग की वजह भले आर्यन रहे हों, इस डबिंग की वजह तो शाहरुख ही बेहतर बता सकते हैं.

# ए आर रहमान का नया जलवा

ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीत निर्देशक ए.आर.रहमान एक बार फिर से हॉलीवुड की एक कॉमेडी फिल्म में अपने संगीत का जलवा बिखेरने की तैयारी में जुटे हुए हैं. रहमान फिल्म *कपल्स रिट्रीट* में संगीत देंगे. ख़ास बात यह होगी कि यह संगीत अमेरिकी अंदाज़ में होगा और इसमें कहीं भी भारतीय धुन सुनाई नहीं देगी. हां, भारतीयता की झलक अवश्य देखने को मिलेगी. उनके प्रशंसक यह देखकर ख़ुश होते हैं या नहीं, यह तो फिल्म के प्रदर्शन के बाद ही पता चलेगा. रहमान को हाल ही में *स्लमडॉग मिलेनियर* की सफलता से ऑस्कर मिल चुका है. बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके रहमान का संगीत हॉलीवुड के दिल को भाएगा या नहीं, यह तो उनके संगीत को सुनने के बाद ही पता चल पाएगा.

# अक्की दोबारा लक्की के किरदार में

अक्की वाकई में अब अपने आप को लक्की समझने लगे हैं. तभी तो वह सिंह इज किंग दोबारा बनाने को तैयार हैं. आख़िरकार वह बॉलीवुड का किंग जो बनना चाहते हैं. ठीक वैसे ही जैसे शाहरुख ख़ान और अमिताभ ने किंग बनकर नाम हासिल किया है. सूत्रों से पता चला है कि निर्देशक निखिल आडवाणी की अगली फिल्म *पटियाला हाउस* में खिलाड़ी कुमार एक पंजाबी मुंडे का किरदार निभाएंगे. सब सही चलता रहा तो उनकी सास डिंपल कपाड़िया भी उनके साथ नज़र आएंगी. वैसे डिंपल पहले भी एक बार अक्षय के साथ एनिमेशन फिल्म *जंबो* के लिए आवाज़ दे चुकी हैं. इस फिल्म में अक्षय की जोड़ीदार होंगी *रब ने बना दी जोड़ी* फिल्म की अनुष्का. एक बात तो साफ़ है कि यह फिल्म पंजाब पर ही आधारित होगी, तभी तो फिल्म का नाम *पटियाला हाउस* रखा गया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

# चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

www.chauthiduniya.com

दिल्ली, 12-18 अक्टूबर 2009


# फिर लाल हुई कोसी की धरती

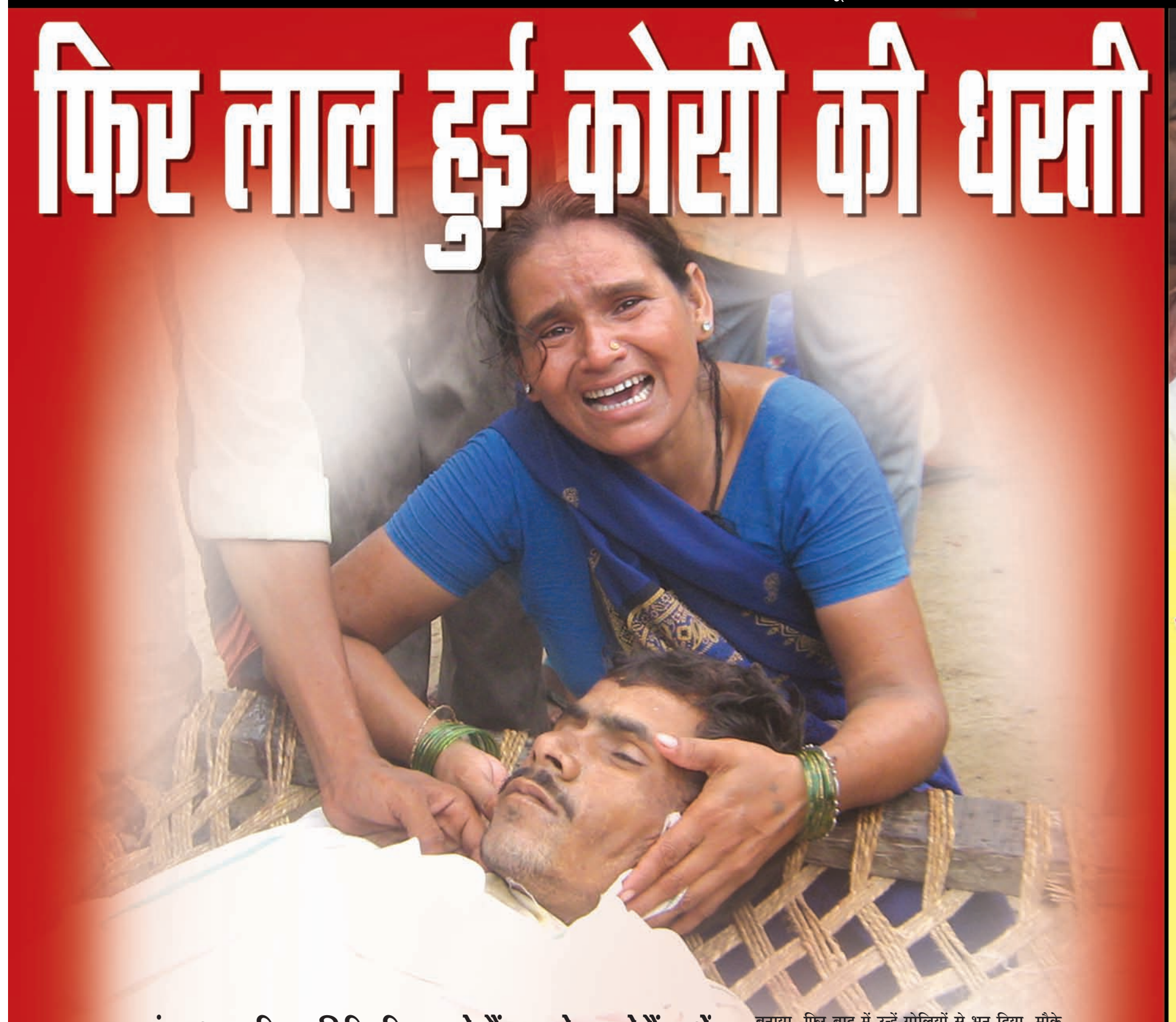

**नरसंहार शायद बिहार की नियति बन चुके हैं. असलहे गरजते हैं, लाशें बिछ जाती हैं और लुट जाता है किसी का सुहाग, किसी के सिर से पिता और भाई का साया. लेकिन, व्यवस्था हर बार केवल जांच और न्याय का कोरा आश्वासन देकर चुप बैठ जाती है. यूं कब तक मरते रहेंगे लोग?**

राजेश सिन्हा

बीती एक अक्टूबर की रात जब पूरा देश गांधी जयंती को अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त खगड़िया ज़िले के अलौली प्रखंड के अमौसी-कमलपुर दियारा में नक्सली ख़ून की होली खेल रहे थे. उन्होंने देखते ही देखते बेरहमी से 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया. ऐसा करके नक्सलियों ने पहली बार नीतीश सरकार को खुली चुनौती दी है.

नदियों के गर्भ से निकली ज़मीन पर कब्ज़ा जमाने की अंधी होड़ में कोसी की धरती वर्षों से लाल होती रही है, लेकिन आज तक भूमि विवाद का कोई स्थाई समाधान नहीं हो पाया. और, जब यह इलाक़ा किसी बड़े नरसंहार का गवाह बनता है, तब जाकर प्रशासनिक अमला सजग होता है. मंत्री आते हैं और मुआवजे का ऐलान करके चले जाते हैं. विपक्षी दलों के नेता भी आते हैं, वे सरकार को कोसते हैं और आंदोलन करने की बात कहकर चले जाते हैं. यहां रह जाते हैं बस वे लोग, जो नरसंहार में अपने प्रियजनों को खो बैठते हैं.

दरअसल जिस ज़मीन को लेकर इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उस पर वर्षों से कुर्मी जाति के लोगों का कब्ज़ा रहा है, लेकिन कुछ दिनों से सदा (मुसहर) जाति के लोग इसे कब्ज़ाने के लिए तरह-तरह के तिकड़म लगा रहे थे. महज़ 35 बीघा ज़मीन पर कब्ज़ा करने के उद्देश्य से नक्सलियों ने अमौसीबासा पर रहने वाले 16 लोगों को पहले बंधक बनाया, फिर बाद में उन्हें गोलियों से भून दिया. मौके पर मौजूद परमानंद सिंह उर्फ पारो सिंह किसी तरह ज़िंदा बच गया. गांव पहुंच कर उसने लोगों को घटना की जानकारी दी. उसके बाद सभी एकजुट होकर अमौसी बहियार पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. मरने वाले सभी 16 लोग कोयरी-कुर्मी थे. प्रशासन की कुंभकर्णी नींद तब टूटी, जब आक्रोशित लोगों ने लाशों को खगड़िया-अलौली मुख्य मार्ग पर रखकर सड़क जाम कर दी. लोग मुख्यमंत्री को घटनास्थल पर बुलाने की मांग कर रहे थे. प्रशासन ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने.

जानकारी पाकर मौके पर पहुंची राज्य की कृषि मंत्री रेणु कुमारी, परिवहन मंत्री रामानंद सिंह, सांसद दिनेश चंद्र यादव और खगड़िया की जदयू विधायक पूनम देवी यादव ने भी लोगों को मनाने का प्रयास किया, फिर भी बात नहीं बनी तो अंत में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को वहां आना पड़ा. जब मृतकों के घरवालों को दिलासा दी जा रही थी. उसी


(शेष पृष्ठ 18 पर)


**“नदियों के गर्भ से निकली ज़मीन पर कब्ज़ा जमाने की अंधी होड़ में कोशी की धरती वर्षों से लाल होती रही है, लेकिन आज तक भूमि विवाद का कोई स्थाई समाधान नहीं हो पाया. और, जब यह इलाक़ा किसी बड़े नरसंहार का गवाह बनता है, तब जाकर प्रशासनिक अमला सजग होता है.”**

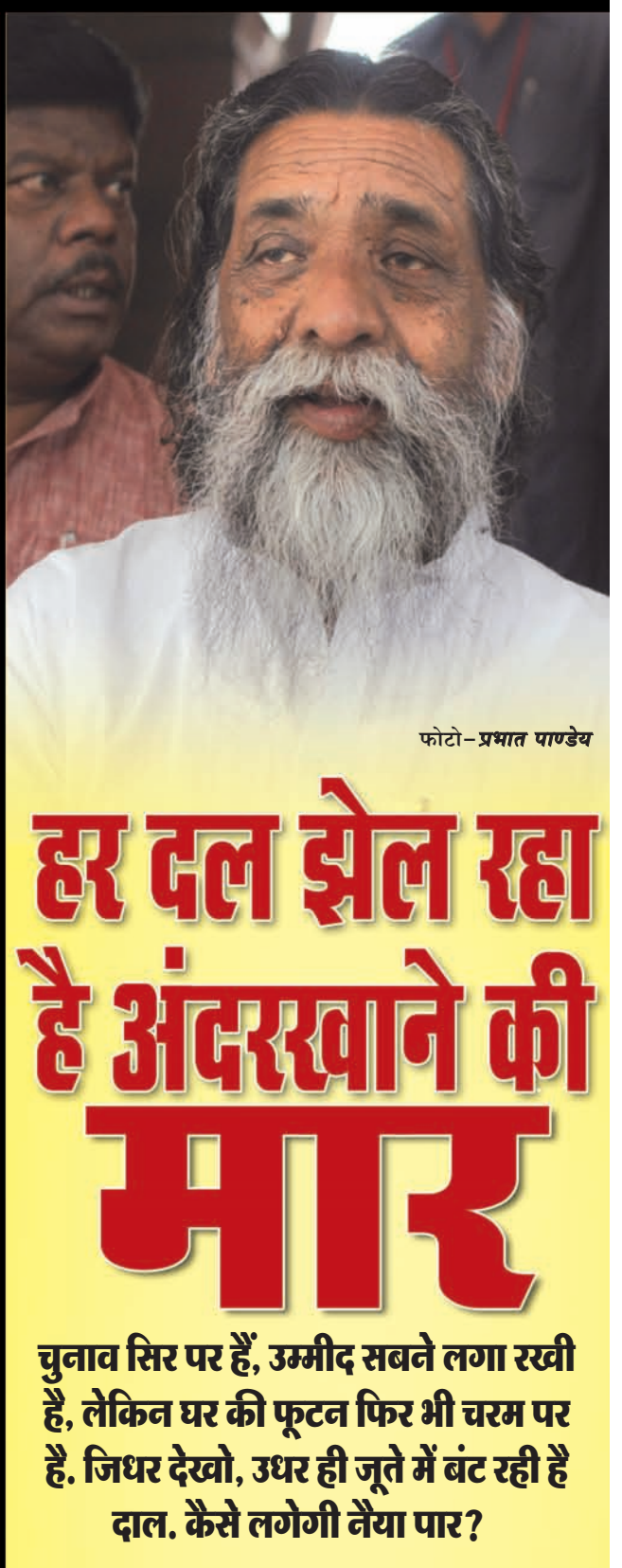

फोटो- *प्रभात पाण्डेय*

# हर दल झेल रहा है अंदरखाने की मार

**चुनाव सिर पर हैं, उम्मीद सबने लगा रखी है, लेकिन घर की फूटन फिर भी चरम पर है. जिधर देखो, उधर ही जूते में बंट रही है दाल. कैसे लगेगी नैया पार?**

झारखंड में विधानसभा चुनाव आगामी 15 जनवरी से पहले होना अब लगभग तय समझा जा रहा है. भाजपा नेता संजय सेठ द्वारा बीती 29 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय में दायर विधानसभा भंग करने से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए इस बात को स्वीकार किया कि राज्यपाल की ओर से विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की जा चुकी है और तीन सप्ताह के भीतर विधानसभा भंग कर दी जाएगी.

यह जानकारी मिलते ही सूबे की राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं. लगभग सभी पार्टियां प्रमंडल स्तर पर सम्मेलन कर चुकी हैं. अब ज़िला स्तर पर सम्मेलन का खाका तैयार किया जा रहा है, लेकिन एक बात साफ़ है कि सभी दल अंदरूनी कलह से परेशान हैं. इनमें सबसे बुरा हाल कांग्रेस का है. कांग्रेस में व्याप्त खटराग रांची से दिल्ली तक पहुंच गया है. पार्टी के पांच पूर्व सांसदों ने प्रदेश अध्यक्ष के ख़िलाफ़ सार्वजनिक तौर पर मोर्चा खोल रखा है, जिससे पार्टी को काफी नुक़सान हो रहा है. केंद्र ने यहां के लोगों को कुछ परिवर्तन दिखाने के उद्देश्य से विधानसभा के निलंबन की अवधि छह महीने के लिए और बढ़ा दी थी. लेकिन, राष्ट्रपति शासन के दौरान यहां वैसा कुछ नहीं हुआ, जिससे चुनाव में सीधे तौर पर कांग्रेस को फ़ायदा हो सके. लोकसभा चुनाव में भाजपा को राज्य में मिली सफलता के बाद से उसके नेताओं के हौसले बुलंद हैं, मगर यहां भी शीत अध्यक्ष रघुवर दास की कार्यशैली से पार्टी के कई वरिख़नेता नाराज़ चल रहे हैं, इनमें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री


(शेष पृष्ठ 18 पर)


**“लोकसभा चुनाव में भाजपा को राज्य में मिली सफलता के बाद उसके नेताओं के हौसले बुलंद हैं, मगर यहां भी शीत युद्ध चल रहा है. प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास की कार्यशैली से पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नाराज़ चल रहे हैं,”**

चौथी दुनिया



अगर बिहार सरकार और स्थानीय प्रशासन नहीं चेता तो एक और नरसंहार की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. जरूरत है कि इस ओर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाया जाए.



अलौली की घटना बताती है कि राज्य में विकास कार्यों की चाल क्या है? किस तरह लोग एक पुल के अभाव में नाव की जोखिम भरी यात्रा करने से नहीं हिचकते और अपनी जान गंवा बैठते हैं.

चौथी दुनिया



# फिर लाल हुई कोसी की धरती



पृष्ठ 17 का शेष

बीच कुछ युवक उत्तेजित हो गए और वे उप मुख्यमंत्री व डीजीपी के साथ बदसलूकी पर उतर आए, मोदी विरोधी नारे लगाने लगे. मौके की नज़ाकत को भांपकर उप मुख्यमंत्री और डीजीपी ने वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी. बाद में स्थानीय लोगों के समझाने पर स्थिति काबू में आई. तब कहीं जाकर लाशों का दाह-संस्कार संभव हो सका. पुलिस ने नरसंहार के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी परमानंद सिंह उर्फ पारो के बयान पर 34 लोगों को नामज़द अभियुक्त बनाया है. कोशी इलाक़े में यह कोई पहली घटना नहीं है, जिसमें भूमि विवाद को लेकर असलहे गरजे और इंसानों के खून से धरती लाल हो गई. इसके पहले भी 1994 में बेलदौर के वारुण गांव में हुए नरसंहार में नौ लोग मारे गए थे. उस घटना को किसी नक्सली संगठन ने नहीं, बल्कि गांव के लोगों ने ही अंजाम दिया था. इसके बाद परबत्ता थाना अंतर्गत मड़ैया, मोरकाही सहित कई अन्य जगहों पर भूमि विवाद के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. उक्त सभी घटनाओं में भी उच्च स्तरीय जांच की बात उठी थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही मामला दफन होकर रह गया. अन्य मामलों में पुलिस की लापरवाही की बात तो खुलकर सामने नहीं आई थी, मगर अमौसीबासा मामले में यह जाहिर हो चुका है कि अगर पुलिस सजग रहती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती. ऐसा इसीलिए, क्योंकि मरने वालों के परिवारीजनों द्वारा कई बार पुलिस प्रशासन तक यह ख़बर पहुंचाई जा चुकी थी कि नक्सली उनकी ज़मीन हथियाने का प्रयास कर रहे हैं और जान से मार देने की धमकी भी देते हैं. बावजूद इसके जब प्रशासन नहीं चेता तो कुर्मी समाज के लोगों ने खुद माओवादियों से लोहा लेने का मन बना लिया और वे इसके लिए अमौसी बहियार में हथियार जुटाने लगे.

इधर कुख्यात दस्यु सरगना रामानंद यादव के समर्थकों ने भी इन लोगों को संरक्षण दे दिया. रामानंद अगर जेल में न होते तो शायद नक्सली अपना सिर उठाते ही नहीं. इधर नक्सलियों को जब पता चला कि अमौसी बहियार में कुर्मी जाति के लोग हथियार जमा कर रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले अमौसी बहियार की घेराबंदी की. उसके बाद एक एक बासा से लोगों को बाहर निकालकर उनके हाथ-पैर बांध दिए और फिर गोली मार दी. घटना के बाद नक्सली हथियार भी लूट ले गए. लगभग एक माह पहले भी नक्सली सरगना बोधन सदा के समर्थकों द्वारा हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुर्मी जाति के लोगों की एकजुटता के चलते वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके थे. बावजूद इसके चार-पांच दिन पहले नक्सलियों ने इस ज़मीन पर केलाय का बीज छींटने के बाद यह चेतावनी दी थी कि इस खेत पर उनका ही अधिकार होगा. जबकि मरने वालों ने उस ज़मीन की जुताई बाग के लिए की थी. इचरूआ गांव के लोगों का कहना है कि ज़मीन चाहे जिस किसी की हो, बटाईदार की हैसियत से वे लोग भी जोत आबाद करते आ रहे हैं. इसीलिए अगर इस ज़मीन पर कोई कब्ज़ा करने का प्रयास करेगा तो संघर्ष जरूर होगा.

घटना के बाद से कुर्मी समाज के लोगों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है. पुलिस ने अगर सजगता नहीं बरती तो एक और नरसंहार होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. केलाय का बीज छींटने के बाद नक्सलियों द्वारा जिस तरह धमकी दी गई थी, उससे लगता है कि वे एक बार फिर जाति विशेष के लोगों को अपना निशाना बनाने से परहेज नहीं करेंगे. बहरहाल इस मामले में शामिल नक्सलियों तक पुलिस कब तक पहुंचेगी, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना तो तय है कि अन्य मामलों की तरह इस बार भी अगर पुलिस ने सुस्ती दिखाई तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं.

feedback@chauthiduniya.com





फोटो-प्रभात पाण्डेय

# हर दल झेल रहा है अंदरखाने की मार

पृष्ठ 17 का शेष

अर्जुन मुंडा, जमशेदपुर पश्चिम के पूर्व विधायक सरयू राय, धनबाद के सांसद पी एन सिंह आदि शामिल हैं. रघुवर दास पर संगठन में एक ख़ास जाति के लोगों को ज़्यादा तरजीह देने का आरोप लगाया जा रहा है. हालांकि अंदरूनी कलह के बावजूद भाजपा फ़िलहाल यहां सबसे मज़बूत पार्टी है. विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को यहां खुला मैदान मिला है.

झामुमो की भी कमोबेश वही स्थिति है. वर्तमान में झामुमो का संथाल परगना व कोल्हान प्रमंडल में वर्चस्व है. जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कोल्हान प्रमंडल में झामुमो को करारा झटका लग सकता है और उसके कई विधायक पार्टी को बाय बाय कर सकते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा में भी भगदड़ मची हुई है. शुरुआती दौर में जितनी तेज़ी के साथ झाविमो का दामन लोगों ने थामा था, अब उतनी ही तेज़ी के साथ वे वहां से भाग रहे हैं. रवींद्र राय एवं कुंती सिंह की भाजपा में वापसी और विष्णु भैया के झामुमो में चले जाने के बाद रही सही कसर थियोजोर कीड़ो ने पूरी कर दी. कीड़ो ने भी बाबूलाल का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया. यह सिलसिला अभी भी जारी है. इसी बीच

बाबूलाल की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 9 प्रतिशत से ज़्यादा मत हासिल कर यहां अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज़ करा दी है.

राजद पलामू व संथाल परगना इलाक़े तक ही सीमित है. इसके प्रदेश अध्यक्ष के ख़िलाफ़ पार्टी विधायकों के बगावती तेवर पिछले चार वर्षों से सार्वजनिक हैं. सारठ के विधायक चुन्ना सिंह ने पार्टी छोड़कर करारा झटका दिया है. राजद के कुछ वर्तमान एवं कई पूर्व विधायक कांग्रेस व भाजपा के संपर्क में हैं. यदि ऐसा होता है तो राजद को यहां काफी नुक़सान उठाना पड़ सकता है. जदयू नीतीश के नाम पर जनता के बीच जा रही है, मगर अंदरूनी कलह से पार्टी पूरी तरह ग्रसित है. लोकसभा चुनाव में जदयू ने दो सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, दोनों ही जगह वह बुरी तरह से हारी. छत्तरपुर के विधायक राधाकृष्ण किशोर ने पार्टी छोड़ दी, सिराज अंसारी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया. ऐसी स्थिति में भाजपा का सहयोग लिए बिना यहां अपना अस्तित्व बचाना जदयू के लिए बहुत मुश्किल काम होगा.

बहरहाल चुनाव की आहट के साथ ही सभी राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है. यह तय है कि इस बार भी कोई राजनीतिक दल अपने बूते पर सरकार नहीं बना सकता. चुनाव पूर्व गठबंधन के आसार अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं. भाजपा, कांग्रेस और झामुमो तीनों बड़ी पार्टियां सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं. यदि ऐसा हुआ तो यहां फिर त्रिशंकु विधानसभा देखने को मिलेगी.

अनीता
feedback@chauthiduniya.com

# साठ को फिर लील गई बागमती

**अगले महीने तीन साल पूरे हो जाएंगे फुलतौड़ा घाट पर पुल का शिलान्यास हुए, लेकिन अभी तक सिर्फ़ कुछ खंभे ही तैयार हो पाए हैं निर्माण के नाम पर. अगर यह पुल बनकर तैयार हो जाता तो ऐन दशहरे के दिन दर्ज़नों घरों में मातम की नौबत हरगिज़ न आती. कब जागेगी सरकार?**



कोसी के विभिन्न इलाक़े यूं तो अक्सर नाव दुर्घटनाओं के गवाह बनते रहे हैं, लेकिन ऐन दशहरे के दिन अलौली में जैसा हादसा हुआ, उसकी तो शायद किसी ने कभी कल्पना भी न की होगी. मालूम हो कि अलौली पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गृहक्षेत्र है. अगर समय रहते यहां पुल बनकर तैयार हो गया होता तो इस हादसे में मारे गए साठ इंसानों की जान बच सकती थी. अपने प्रियजनों की मौत पर आंसू बहाने और नेताओं के आगे अपना दुखड़ा सुनाने के बाद लोगों ने अपनी ज़ुबान सिल ली है. उन्हें पता है कि हर हादसे के बाद झूठे वायदों के अलावा पीड़ितों के हिस्से में और कुछ भी नहीं आता. दरअसल, ऐसे हादसे अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाते हैं. यातायात के साधनों का अभाव होने की वजह से अकुशल नाविकों के हाथों में रोज़ाना सैकड़ों लोगों की जान बंधक बनी रहती है. उधर सरकारी अमला अपने कानों में तेल डाले बैठा है. उसकी तंद्रा केवल तभी टूटती है, जब कोई अनहोनी घट जाती है. कुछ दिनों तक गहमागहमी रहती है, उसके बाद व्यवस्था फिर से कुंभकर्ण की नींद सो जाती है.

15 नवंबर, 2006 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुलतौड़ा घाट पर पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास करते हुए स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया था कि यह पुल 15 नवंबर 2009 तक बनकर तैयार हो जाएगा. लोगों को भी नाव से यात्रा करने की मजबूरी ख़त्म होने की उम्मीद बंध गई थी. लेकिन, बदक़िस्मती कोसी के निवासियों का पीछा ही नहीं छोड़ रही है. आपसी राजनीति और अफ़सरों के निकम्मेपन के चलते पुल के नाम पर आज तक केवल दो-चार खंभे ही तैयार हो पाए हैं. विजयादशमी के दिन जिस समय सूबे के लोग हर्षोल्लास के साथ त्योहार मना रहे थे, उसी समय खगड़िया ज़िला अंतर्गत अलौली प्रखंड के गम्हरिया, फुलतौड़ा और शहरबन्नी सहित आसपास के इलाक़े के लोगों पर क़िस्मत ने ऐसा कहर ढाया, जिसे याद कर हर किसी की रूह कांप जाती है.

महीनों शहर का मुंह तक न देख पाने वाले स्थानीय लोग विजयादशमी का मेला देखने पास के ही सनोखर गए थे. तब शायद लोगों ने यह नहीं सोचा होगा कि उनकी ज़िंदगी की नाव आज हमेशा के लिए डूब जाने वाली है. मेला देखकर लौटते समय शाम हो चुकी थी. जल्दी घर पहुंचने की आपाधापी में लगभग डेढ़ सौ लोग एक ही मोटरचालित नौका पर सवार हो गए. नाव जब बीच नदी में पहुंची तो अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आया और देखते ही देखते पूरी नाव बागमती में समा गई. जब तक आसपास रहने वालों को घटना की जानकारी मिलती, तब तक साठ लोग जीवन से हाथ धो चुके थे. नाव में महिलाओं और बच्चों की संख्या काफी थी, जिनमें से अधिकतर तो हाथ-पैर भी नहीं मार सकते थे.

जिन लोगों को तैरना आता था, वे तो किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन बाक़ी को बागमती लील गई. जानकारी मिलने के बाद सरकारी अमला मौक़े पर पहुंचा तो ज़रूर, लेकिन बागमती की तेज़ धार के आगे वह भी बेबस नज़र आया. स्थानीय गोताखोरों ने यह कहकर हाथ खड़े कर दिए कि नदी की धारा इतनी तेज़ है कि राहत और बचाव कार्य शुरू करना उनके बूते की बात नहीं है. आनन-फानन में पटना से राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) की टीम भेजने के लिए संदेश भेजा गया. एनडीआरएफ की टीम अगली सुबह मौक़े पर पहुंची. लाशों को निकालने का दौर शुरू हुआ तो स्थानीय लोगों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं. बच्चों की लाशें निकलते ही इलाक़े में कोहराम मच गया.

कोसी इलाक़े में यह कोई पहली घटना नहीं है. दुर्घटना होने के बाद हर बार प्रशासन पीड़ितों को मुआवज़ा स्वरूप एक चेक थमा देता है और उसके बाद शासन की सारी कवायदें विराम पा जाती हैं. सुर्ख़ियों में रहती है तो केवल मरने वालों की संख्या. ज़िला प्रशासन एक रटी रटाई गिनती मीडिया और सरकार के सामने पेश कर देता है. जिनकी लाशें मिल जाती हैं, उनका नाम तो मृतकों की सूची में शामिल कर लिया जाता है और मुआवज़े की शक्ल में उनके आश्रितों को मरहम भी मिल जाता है.

जिन लोगों की लाश नहीं मिल पाती, उनकी हालत तो और भी बदतर हो जाती है. उन्हें न तो ज़िंदा समझा जाता है और न ही मुर्दा. उनके आश्रित बिलखते रहते हैं, लेकिन प्रशासन कोई नहीं सुधि लेता. गुम लोगों के परिजन भी खोज की जहमत नहीं उठाते. जांच का भरोसा के सहारे मृतकों के आश्रितों की ज़िंदगी रेंगती रहती है.

हां, हर दुर्घटना के बाद यह ज़रूर होता है कि कुछ दिनों तक लोग नाव की सवारी करने से पहले अपने इष्ट देव को याद कर लेते हैं. टोटके के रूप में नाव पर चढ़ने से पहले चंद सिक्के नदी में फेंक देते हैं. शायद यह सोचकर कि चढ़ावा मिलने से मां प्रसन्न हो जाएंगी और कोई हादसा नहीं होगा. अलौली हादसे का शिकार हुए लोगों की कहानी भी खासी विचित्र है. हर शख्स एक अलग कामना लेकर देवी दर्शन के लिए सनोखर गया था. पति देवन-ारायण सदा के साथ सेम्पू देवी मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने गई थी. पति के दीर्घायु होने की मन्नत मांगकर वापस लौटी सेम्पू देवी को पता नहीं था कि वापसी में मौत आंचल फैलाए उसका और उसके पति देवनारायण का इंतज़ार कर रही है. शहरबन्नी गांव निवासी कृष्णा कुमार की पत्नी अपने दो मासूम बच्चों के साथ बेहतर भविष्य की कामना लेकर मां अम्बे के पास गई थी. लौटते समय वह अपने दोनों बच्चों समेत बागमती में विलीन हो गई. फुलतौड़ा के सिंघेश्वर साह पत्नी अनीता से यह कहकर सनोखर गए थे कि वापसी में मां का प्रसाद लेकर लौटेंगे, लेकिन वह तो नहीं पहुंच सके, अलबत्ता अनीता तक उनके डूब मरने की ख़बर ज़रूर पहुंच गई. पचराहा निवासी बटेश्वर सदा घरवालों से यह कहकर निकले थे कि बच्चों के लिए खिलौना ख़रीदकर जल्द ही वापस आ जाएंगे. लेकिन कुदरत को यह मंज़ूर नहीं था, इसीलिए वह ख़ुद सकुशल नहीं लौट पाए. फुलतौड़ा के चरित्र सदा अपने पोता-पोती के साथ मां दुर्गे का दर्शन करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापसी में उन तीनों को मौत ने अपने दर्शन दे दिए.

राजेश सिन्हा
feedback@chauthiduniya.com

# हद हो गई संवेदनहीनता की

प्रशासन की संवेदनहीनता पर कुछ ऐसे ही भाव दिल में लेकर संतोष पासवान ने अपने पिता राम उद्गार के पुतले को ही उनका शव मानकर अंतिम संस्कार कर दिया. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि दो ज़िलों के सीमा विवाद और प्रशासनिक लापरवाही के चलते घटना के पांच दिनों बाद राम उदगार का क्षत विक्षत शव नदी से निकाला जा सका.



समस्तीपुर-बेगूसराय की सीमा पर दोनों ज़िलों को जोड़ने वाला और लगभग सौ साल पुराना फफौत पुल बीती 26 सितंबर को एक दस चक्का ट्रक के गुज़र जाने की वजह से टूट गया. फफौत (समस्तीपुर) निवासी राम उद्गार पासवान, रंजीत कुमार, अरुण कुमार, विजय अवस्थी, राहुल रजक और मोहम्मद शब्बीर ने ट्रक चालक को उक्त पुल से गुज़रने से मना भी किया था, लेकिन चालक ने यह कहकर उनकी बात अनसुनी कर दी कि ट्रक पर लदी बालू बगल में बन रहे पुल की है. इसके बाद जैसे ही ट्रक पुल पर पहुंचा, एक तेज़ आवाज़ के साथ पुल भरभरा कर टूट गया और पलक झपकते ही आधा दर्ज़न से अधिक लोग ट्रक व पुल के मलवे के साथ बूढ़ी गंडक नदी में जा गिरे. इस हादसे में राम उदगार की मौत हो गई. घटना की जानकारी पाकर मौक़े पर पहुंचा बेगूसराय और समस्तीपुर प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के बजाय इस उधेड़बुन में डूबा रहा कि घटनास्थल किस ज़िले की सीमा में है. मंझौल (बेगूसराय) के अनुमंडल पदाधिकारी जी पी मंडल और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार सुधांशु वहां डेढ़ घंटे बाद पहुंचे, लेकिन वे भी यह तय नहीं कर पा रहे थे कि हादसा किस ज़िले की सीमा में हुआ है.

अफ़सरों को कुछ करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे देख इस दुर्घटना के शिकार हुए लोगों के परिवारजनों को काफी निराशा हुई. जब यह तय हो गया कि घटनास्थल समस्तीपुर की सीमा में आता है तो बेगूसराय से आए अधिकारी मौक़े से खिसक लिए.

हैरत की बात यह है कि ज़िले की आपदा प्रबंधन टीम ट्रक निकालने के लिए एक क्रेन तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी. उधर जब प्रदेश शासन के मंत्री रामनाथ ठाकुर मौक़े पर पहुंचे तो लोगों को लगा कि राम उदगार के आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से मुआवज़ा ज़रूर मिलेगा, लेकिन यह उम्मीद जल्द ही टूट गई. एक पखवाड़े बाद भी परिजनों को कोई मुआवज़ा नहीं मिल सका है.

माकपा विधायक रामदेव वर्मा ने घटना के लिए सरकार और प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहराया है. उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की बात कही है.

विकास कुमार
feedback@chauthiduniya.com

पत्रकारिता के क्षेत्र में चौथी दुनिया का बिहार व झारखंड संस्करण एक अहम प्रयास है। हम इसकी सफलता की कामना करते हैं। बिहार व झारखंड के सभी वासिंदों को दीपावली व छठ की

ढेर सारी बधाईयां



आशुतोष शरण
चिकित्सक
शरण नर्सिंग होम
मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण

चौथी दुनिया
पत्रकारिता के क्षेत्र में एक क्रांति स्वरूप है हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। रक्सौल विधानसभा के समस्त मतदाताओं, मालिकों को दीपावली व छठ की

हार्दिक शुभकामनायें



मोहम्मद असलम
प्रखंड प्रमुख, आदापुर, पूर्वी चम्पारण
पूर्व सदस्य प्रदेश हज कमेटी, बिहार पटना सह अध्यक्ष प्रमुख संघ पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

शुभ दिपावली

चौथी दुनिया

शुभ दिपावली

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक क्रांति स्वरूप है हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मधुबन विधानसभा के समस्त मतदाताओं मालिकों को दीपावली व छठ की





राणा रंधीर सिंह
पूर्व विधायक, मधुबन विधान सभा

# अनपढ़ जनता की गाढ़ी कमाई लूट रहे ओझा गुणी



*एक सो विदया लिखरू गौरी के पूत, मांग कोख-पूत-भतार, हम जाइले रइरे जान. ओढइल फुल-फुले भखनार ओमे जोगिन करे स्नान. झींगा लाला हुम, झींगा लाला हुम...*

मनोज कुमार राव

जी हां, इन्हीं अजीबोग़रीब मंत्रों से महिलाओं, बच्चों और बुज़ुर्गों की झाड़फूंक करता है चालीस वर्षीय दुखहरण. चेहरे पर चेचक के दाग, डरावनी आंखें और हाथ में हड्डी का एक टुकड़ा लेकर मोतिहारी मुख्यालय से सटे जीवधारा की एक फुलवारी में चल रहा है झाड़फूंक का यह गोरखधंधा, जहां न सिर्फ़ मोतिहारी व आसपास के, बल्कि कोलकाता, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के सैकड़ों लोग बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं. दुखहरण का दावा है कि उसके पास झाड़फूंक कराने के लिए वकील, डॉक्टर और बड़े-बड़े अधिकारी भी परिवार समेत आते हैं. दुखहरण प्रतिदिन सौ मरीज़ देखता है. रविवार व मंगलवार को यह संख्या अधिक भी हो जाती है. वह ताबीज के नाम पर प्रति मरीज़ 31 रुपये ऐंठता है. उसका सच चाहे जो हो, लेकिन ख़ुद को वह आयुर्वेद का ज्ञाता बताता है.

**दोषी दुखहरण नहीं है, बल्कि हमारी व्यवस्था है जो आज तक इस गोरखधंधे के प्रति उदासीन है. कब टूटेगी प्रशासन की कुंभकर्णी नींद?**

बातचीत के दौरान ही पैंतीस वर्षीय लालबाबू प्रसाद ने अपने पांच माह के नाती को दुखहरण के सामने रख दिया. दुखहरण ने पूछा, का होइल? लालबाबू ने कहा, देखी ना जनम के समय बुलेट रहे, अब सुखल जाता. दुखहरण ने बच्चे के माथे पर हड्डी सटाई, मंत्र बुदबुदाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा. लालबाबू ने आश्वस्त होकर दुखहरण के पैरों में पैसे रख दिए और वहां से चला गया. 32 वर्षीय बेबी अपनी तीन साल की बेटी को दुखहरण के सामने रखते हुए बोली, देखी ना सुख गइल बिया, दुध नइखे पीयत तनी मंतर मार दीं. बेबी ने इसी के साथ दुखहरण के सामने दूध की बोतल भी रख दी और कहा, तनी एकरो पर हाथ फेर दीं. दुखहरण ने बच्चे के सिर व दूध की बोतल पर हड्डी सटाई और कहा, जाओ सब ठीक हो जाएगा.

लोग बारी बारी से मिलते गए और दुखहरण के चरणों में पैसे रखते गए. यह सिलसिला दिन भर चलता रहा. आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि फुलवारी भुतही है, झाड़फूंक होती है, लेकिन बाबा पैसा नहीं लेते. जबकि दुखहरण ने स्वयं पैसे लेने की बात स्वीकारी. ज़िले के सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां पर मज़दूरों की संख्या अधिक है और जिनके पति कमाने के लिए बाहर गए हैं, उन परिवारों की महिलाएं आए दिन अपनी दिन भर की कमाई का आधा हिस्सा ऐसे बाबाओं को अर्पण करने में जरा भी नहीं हिचकतीं. विडंबना यह है कि जीवधारा का यह दुखहरण बार बार कुंवारी माता का नाम लेता है, जबकि फुलवारी स्थित कई मंदिरों में एक मंदिर ऐसा भी है, जहां किसी देवी देवता के बजाय एक अधेड़ व्यक्ति की तस्वीर रखी है और जिसके आगे स्वर्गीय दुखहरण लिखा हुआ है. फुलवारी के इस बाबा का नाम भी दुखहरण है. ज़ाहिर है कि दुखहरण का यह असली नाम नहीं है.

आसिन दशहरा की सप्तमी के दिन सैकड़ों लोगों की भीड़ फुलवारी के आसपास देखी जाती है. यहां आने वाले कितने लोग स्वस्थ हो पाते हैं, यह तो दुखहरण जाने या फिर रोगी?

लेकिन अपनी कथित ताबीज, भस्म, जड़ी-बूटी और विचित्र मंत्रों के सहारे ऐसे बाबा, ओझा व गुणी ज़रूर जमकर चांदी काट रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

# मठ, मंदिर और माफिया

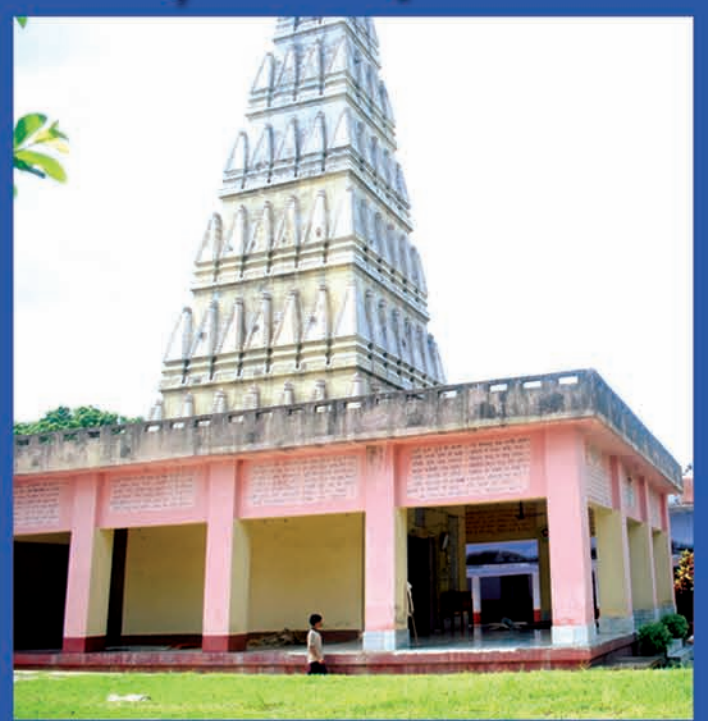



बिहार की राजधानी पटना से सटा है फतुहा अनुमंडल. नवरात्र में जब पूरा शहर मां की आराधना में जुटा हुआ था, उसी समय यहां के ऐतिहासिक कबीर मठ में एक कत्ल हो गया, जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी. हत्यारों का शिकार बने मठ के महंत रामेश्वर दास. सवाल यह है किसने मारा उन्हें? इसका जवाब तो पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा. उधर मठ के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि हत्या की साज़िश महंत के ही गुरु भाई परमानंद दास ने रची थी.

फतुहा के कबीर मठ में महंत की हत्या कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले 1988 में महंत विघानंद दास साहेब की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या की साज़िश का आरोप लगा था विघानंद के शिष्य श्यामसुंदर दास पर. बाद में श्यामसुंदर दास महंत बने, लेकिन 2004 में उनकी भी मठ के अंदर ही हत्या कर दी गई. फिर महंत बने रामेश्वर दास, लेकिन रामेश्वर दास के महंत बनने से परमानंद दास नाराज रहते थे. आख़िरकार रामेश्वर दास की भी हत्या हो गई. हद तो तब हो गई, जब शव के अंतिम संस्कार से पहले ही परमानंद दास ने महंत की चादर ले ली. वही चादर अब उनके गले की फांस बन गई है.

मामले की जांच करने पहुंचे बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के प्रशासक आचार्य किशोर कुणाल ने परमानंद दास को तुरंत मठ परिसर छोड़ देने का आदेश दिया और वहां की देखभाल की ज़िम्मेदारी अंचलाधिकारी को सौंप दी.

बिहार के करीब साढ़े चार सौ मठों का कमोबेश यही हाल है. किशोर कुणाल के मुताबिक़, इन मठ-मंदिरों के पास सौ करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति है, लेकिन उस पर बाहुबलियों का कब्ज़ा है. आलम यह है कि मंदिर में भगवान को भोग तक नहीं लग पा रहा है और दुराचारी लोग राज कर रहे हैं. मुज़फ़्फ़रपुर में कबीर मठ की करीब पांच एकड़ ज़मीन पर राज्य सरकार के एक पूर्व मंत्री के घरवालों ने कब्जा कर रखा था. मंदिर में ताला लगा था और मंत्री के रिश्तेदार उस ज़मीन को बेच रहे थे. विरोध करने पर जून 2005 में वहां के महंत कृष्ण कृपादास की हत्या कर दी गई. हालांकि धार्मिक न्यास बोर्ड की पहल पर अब मंदिर की अधिकांश ज़मीन कब्ज़ा मुक्त करा ली गई है और अब वहां संत कबीर के नाम पर एक अस्पताल बनाने की प्रक्रिया चल रही है.

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में दो दर्जन से ज़्यादा महंत मारे चुके हैं. इनमें से अधिकांश घटनाओं के मूल में मठ की संपत्ति को लेकर चलने वाला विवाद था. दरअसल, आज के महंत कमंडल के साथ पिस्तौल भी रखने लगे हैं. बदल गया है उनका जीने का अंदाज. महंगे वाहन, महंगे मोबाइल और साथ में हथियारबंद लोग उनकी नई पहचान है. पिछले ढाई साल में धार्मिक न्यास बोर्ड ने महंत से बाहुबली बने एक दर्जन से ज्यादा तथाकथित महंतों को मठ से बाहर का रास्ता दिखा दिया है.

कई लोगों के ख़िलाफ़ तो अदालत में मुकदमे भी किए गए हैं. ऐसा ही एक मामला पटना के भीखमदास ठाकुर बाड़ी से जुड़ा हुआ है, जहां आसाराम बापू के शिष्यों ने कब्जा कर रखा था. कब्जा की गई ज़मीन की क़ीमत भी थी करोड़ों में. बहरहाल अब इस ज़मीन को धार्मिक न्यास बोर्ड ने कब्जा मुक्त करा लिया है, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद.

किशोर कुणाल के अनुसार, बिहार में वर्ष 2006 में एक कानून बनाया गया, जिसके तहत वर्ष 1954 के बाद खरीदी व बेची गई मठ-मंदिरों की ज़मीन को अवैध घोषित कर दिया गया है. इन सभी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराए जाने की कार्रवाई चल रही है. 75 ऐसे मामलों में कार्रवाई भी हो चुकी है. इसके अलावा एक लाख से ज़्यादा की आय वाले सभी मठ-मंदिरों की देखभाल और आय व्यय का जिम्मा धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा बनाई गई स्थानीय कमेटियों को सौंप दिया गया है. यही नहीं, महंत से माफिया बन चुके कई महंतों को हटाने के लिए भी धार्मिक न्यास बोर्ड लगातार जुटा हुआ है.

अमिताभ ओझा
feedback@chauthiduniya.com

# गया : कमर कसने लगे दल

उपचुनाव के परिणाम आने के बाद से ही गया ज़िले के सभी दस विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं. सारे दल अभी से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गए हैं. भाजपा के लिए तो इस बार सवाल जीवन-मरण का बन गया है, क्योंकि हाल में हुए उपचुनाव में बोधगया की सीट उसके हाथों से निकलकर लोजपा के पास चली गई है.

गया के जदयू ज़िला अध्यक्ष रामचंद्र सिंह के अनुसार, इस चुनाव में मतदाताओं ने सीखने के लिए हमें एक संदेश दिया है. हमारे लिए यह चिंता नहीं, बल्कि चिंतन का विषय है. विधानसभा चुनाव में राजग गठबंधन गया की सभी सीटों पर सफल होगा. इसके लिए हमने तैयारी भी शुरू कर दी है. कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वे गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धियां मतदाताओं को बताएं. सरकार के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसे दूर करने के लिए भी कार्यकर्ताओं का एक विशेष दल मतदाताओं के पास जा रहा है.भाजपा ज़िला अध्यक्ष ललिता देवी के अनुसार, गया में भाजपा और जदयू पांच-पांच सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सफल होंगे. उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कुछ भूल हो गई थी, जिसके चलते बोधगया सीट हमसे छिन गई. हम उस भूल को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं. भाजपा कार्यकर्ताओं की टोली गांव-गांव जाकर संपर्क कर रही है, जिससे मतदाताओं से सीधे जुड़ा जा सके.

इसी तरह राजद ने भी गया में कड़ी चुनौती पेश करने के लिए अपने तंत्र को सक्रिय कर दिया है. पार्टी चाहती है कि वह गया में अपने पुराने जनाधार को फिर से हासिल करे. राजद ज़िला अध्यक्ष राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि अपने समाज जोड़ो कार्यक्रम के तहत हमारे कार्यकर्ता सभी वर्ग व समुदाय के लोगों के बीच जा रहे हैं. इसी सामाजिक सद्भाव के चलते ही राजद-लोजपा प्रत्याशी ने उपचुनाव में बोधगया में सफलता प्राप्त की. लोजपा ज़िलाध्यक्ष अताउल्लाह खां ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ता विकास कार्यों को तेज़ी से संपन्न कराने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं. वे गांव-गांव भ्रमण भी कर रहे हैं.

**"वर्तमान में इमामगंज, बाराचट्टी व कोंच विधानसभा सीटों पर जदयू का, गया शहर पर भाजपा, बोधगया पर लोजपा (उपचुनाव), मुफसिल में कांग्रेस और गुरूआ, बेलागंज, फतेहपुर व अतरी विधानसभा सीटों पर राजद का क़ब्ज़ा है. लेकिन नए परिसीमन में फतेहपुर, मुफसिल और कोंच विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त कर वजीरगंज, शेरघाटी और टिकारी नए विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं."**

हालांकि तालमेल को लेकर अभी स्थिति साफ़ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने भी गया के सभी दस विधानसभाई क्षेत्रों पर अपनी नज़र गड़ा दी है और चाहती है कि वह चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज़ कराए. ज़िलाध्यक्ष चिरागउद्दीन रहमानी कहते हैं कि हम नागरिक समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं. हमने धरना-प्रदर्शन के माध्यम से समस्याओं के प्रति प्रशासन का ध्यान आकर्षित भी किया है. सामाजिक समरसता कार्यक्रम के तहत गांधी जयंती से एक अभियान शुरू किया गया है जो गांव-गांव तक जाएगा.

फ़िलहाल इमामगंज, बाराचट्टी व कोंच विधानसभा सीटों पर जदयू का, गया शहर पर भाजपा, बोधगया पर लोजपा (उपचुनाव), मुफसिल में कांग्रेस और गुरूआ, बेलागंज, फतेहपुर व अतरी विधानसभा सीटों पर राजद का क़ब्ज़ा है. लेकिन नए परिसीमन में फतेहपुर, मुफसिल और कोंच विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त कर वजीरगंज, शेरघाटी और टिकारी नए विधानसभा क्षेत्र बनाए गए हैं. बदलते समीकरण और नए परिसीमन आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रंग दिखाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा. फ़िलहाल उपचुनाव परिणाम देख विपक्षी दलों में जहां उत्साह की लहर है, वहीं सत्ताधारी दलों के चेहरे पर शिकन साफ़ देखने को मिलती है.

सुनील कुमार सिंह
feedback@chauthiduniya.com

पत्रकारिता के क्षेत्र में चौथी दुनिया का बिहार व झारखंड संस्करण एक अहम प्रयास है। हम इसकी सफलता की कामना करते हैं। बिहार व झारखंड के सभी वासिंदों को दीपावली व छठ की

बधाईयां

डॉ. परवेज

रहमान नर्सिंग होम

मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण